04 - दुर्घटनाओं के लिये शासन जिम्मेदार

05 - निजी कानून सामाजिक मूल्यों के अनुरूप बनाने का मौका

06 - सतपुड़ा वैली स्कूल के 21वें फाउंडेशन डे पर छात्र परिषद...

07 - ब्यावरा में नीम, पीपल जैसे राज्यमंत्री ने 50 पौधे लगाए

सुबह सवेरे

A Daily News Magazine

इंदौर

सोमवार, 13 जुलाई, 2026

इंदौर एवं भोपाल से एक साथ प्रकाशित

वर्ष 11 अंक 281, नगर संस्करण, पृष्ठ 8, मूल्य रू. 2

प्रसंगवश

पंजाब: फिल्म 'सतलुज' कैसे बनी सबसे बड़ा सियासी मुद्दा

चितलीन सेठी

हाल के समय में शायद ही किसी फिल्म ने पंजाब में दिलजीत दोसांझ की 'सतलुज' जितनी राजनीतिक, कानूनी और सार्वजनिक बहस छेड़ी हो। मानवाधिकार कार्यकर्ता जसवंत सिंह खालड़ा के जीवन पर बनी इस फिल्म की रिलीज का लंबे समय से इंतिजार था, लेकिन अब यह पंजाब का सबसे बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गई है।

असल में, 'सतलुज' को OTT प्लेटफॉर्म ैश्वश्व5 से रिलीज के करीब 48 घंटे के भीतर हटाए जाने के बाद विवाद और बढ़ गया। इसके बाद अलग-अलग जगहों पर लोगों ने मिलकर फिल्म की कम्युनिटी स्क्रीनिंग शुरू कर दी, जिससे सेंसरशिप और अभिव्यक्ति की आजादी पर बहस को एक नया मोड़ मिल गया। OTT से हटाए जाने के बाद फिल्म की पहुंच कम होने के बजाय एक नया विकल्प सामने आया। पंजाब के गांवों के चौकों और गुरुद्वारों के आंगनों तक फिल्म पहुंचाने के लिए स्वयंसेवकों का एक नेटवर्क बन गया।

हालांकि कम्युनिटी स्क्रीनिंग की शुरुआत राजस्थान के एक गांव में हुई पहली स्क्रीनिंग से प्रेरित थी, लेकिन अब राजनीतिक दल भी इसे बढ़ावा दे रहे हैं। शिरोमणि अकाली दल ने घोषणा की है कि वह पंजाब के सभी गांवों में फिल्म की स्क्रीनिंग का खर्च उठाएगा। वहीं पंजाब विधानसभा के स्पीकर और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ विधायक कुलतार सिंह संधवां ने भी कहा है कि उनके विधानसभा क्षेत्र में समुदाय स्तर पर फिल्म दिखाई जाएगी।

फिल्म जसवंत सिंह खालड़ा के जीवन पर आधारित है। खालड़ा ने पंजाब में उग्रवाद के दौर में कथित अवैध अंतिम संस्कारों और लोगों के गायब होने के मामलों को उजागर किया था। बाद में 1995 में उनका अपहरण कर हत्या कर दी गई थी। फिल्म कई साल तक अटकी रही क्योंकि केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) ने इसमें कई बड़े बदलाव मांगे थे, जिनमें फिल्म का नाम और यहां तक कि खालड़ा का नाम बदलना भी शामिल था। निर्माताओं ने कहानी में बदलाव से इनकार कर दिया, जिसके कारण प्रमाणन को लेकर लंबी कानूनी लड़ाई चली और फिल्म की रिलीज करीब चार साल तक टल गई।

जब 3 जुलाई को फिल्म आखिरकार ZEE5 पर रिलीज हुई तो लोगों को लगा कि लंबे इंतजार का अंत हो गया। लेकिन इसके बजाय नया विवाद शुरू हो गया। दो दिन के भीतर भारत में दर्शकों के लिए फिल्म उपलब्ध नहीं रही। ZEE 5 ने कहा कि मौजूदा घटनाक्रम को देखते हुए और कानूनी विकल्पों पर विचार करते हुए यह फैसला लिया गया है। बाद में सरकारी सूत्रों ने संकेत दिया कि केंद्र ने सुरक्षा संबंधी चिंताओं का हवाला देते हुए फिल्म हटाने को कहा था और मामले की आगे जांच के लिए इसे सूचना प्रौद्योगिकी नियम, 2021 के तहत बनी अंतर-विभागीय समिति को भेजने की योजना बनाई है।

फिल्म हटाए जाने के बाद राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप भी तेज हो गए। शिरोमणि अकाली दल ने इसे अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला बताते हुए सवाल उठाया कि जो फिल्म पहले ही दर्शकों तक पहुंच चुकी थी, उसे वापस क्यों लिया गया। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (SGPC) ने भी फिल्म का समर्थन करते हुए कहा कि खालड़ा की कहानी लोगों तक पहुंचनी चाहिए।

सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी ने इस विवाद को बीजेपी और कांग्रेस दोनों पर राजनीतिक हमला करने का मौका बनाया। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने आरोप लगाया कि दोनों पार्टियां नई पीढ़ी को उग्रवाद के दौर और मानवाधिकार उल्लंघन के आरोपों के बारे में जानने से रोकना चाहती हैं।

केंद्र पर राजनीतिक हमला तेज करने के साथ-साथ पंजाब आप अध्यक्ष अमन अरोड़ा ने कहा कि राज्य सरकार नागरिकों द्वारा आयोजित निजी स्क्रीनिंग में हस्तक्षेप नहीं करेगी। उधर पंजाब बीजेपी अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों ने कहा कि उन्होंने यह मामला केंद्र सरकार के सामने उठाया, जिसके बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने फिल्म हटाए जाने की परिस्थितियों की समीक्षा के लिए तीन सदस्यीय समिति बनाई है। पंजाब बीजेपी ने इसे इस बात का संकेत बताया कि केंद्र विवाद को और बढ़ने देने के बजाय संस्थागत प्रक्रिया के जरिए दोबारा देखने को तैयार है।

फिल्म की कहानी ने पंजाब में उग्रवाद के दौर में पुलिस की भूमिका पर भी बहस फिर से छेड़ दी। एक पक्ष ने दशकों तक चले हिंसा और आतंकवाद को खत्म करने में पंजाब पुलिस की क्षमता और बहादुरी पर जोर देते हुए कहा कि फिल्म एकतरफा और बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया गया नजरिया दिखाती है। वहीं दूसरे पक्ष ने उस दौर में पुलिस द्वारा '25,000' कथित फर्जी मुठभेड़ों और न्यायेतर हत्याओं की कहानी को समर्थन दिया।

केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू, जिनके दादा और पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की 1995 में सिख उग्रवादियों ने हत्या कर दी थी, ने कहा कि फिल्म उस दौर की 'एकतरफा कहानी' दिखाती है। उन्होंने दिलजीत दोसांझ को 'इम्पोस्टर' कहा और आरोप लगाया कि वह पैसे कमाने के लिए पंजाब के लोगों को गुमराह कर रहे हैं। बिट्टू ने दोसांझ और हनी त्रेहन को चुनौती दी कि वे उस दौर में उग्रवादियों द्वारा पुलिस अधिकारियों की हत्या पर भी फिल्म बनाएं। इस विवाद ने जसवंत सिंह खालड़ा के अपहरण और हत्या के मामले को भी फिर से चर्चा में ला दिया है। इस मामले में दोषी ठहराए गए एक पुलिस अधिकारी को लेकर भी राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। अकाली नेता बिक्रम सिंह मजीठिया ने खालड़ा हत्याकांड में दोषी पंजाब पुलिस के पूर्व डीसीपी जसपाल सिंह को 2023 में जमानत मिलने की परिस्थितियों पर सवाल उठाए। मजीठिया ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली आप सरकार ने केंद्र से उसकी सजा कम करने की सिफारिश की थी। जबकि आप के पंजाब महासचिव बलतेज पन्नू ने कहा कि मजीठिया इस मुद्दे का राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं।

इस मुद्दे का एक मजबूत धार्मिक पहलू भी है। श्री अकाल तख्त साहिब सचिवालय ने कड़ा बयान जारी करते हुए जत्थेदार ज्ञानी कुलदीप सिंह गर्गज ने 'सतलुज' पर रोक की निंदा की। जत्थेदार ने कहा कि सच्चाई को हमेशा के लिए दबाया नहीं जा सकता। उन्होंने सरकार से उस दौर के पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए ज्यादा ईमानदार रुख अपनाने की अपील की। शुक्रवार को SGPC ने फिल्म रिलीज करने की मांग को लेकर अमृतसर में स्वर्ण मंदिर से डिप्टी कमिश्नर कार्यालय तक विरोध मार्च निकाला। यह विवाद अब राजनीति से निकलकर अदालत तक भी पहुंच गया है। बुधवार को पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई, जिसमें OTT प्लेटफॉर्म पर फिल्म को फिर से उपलब्ध कराने की मांग की गई।

(दि प्रिंट हिंदी में प्रकाशित लेख

subahsaverenews@gmail.com

facebook.com/subahsaverenews

www.subahsavere.news

twitter.com/subahsaverenews

सुप्रभात

ये भी नहीं
वो भी नहीं
कुछ भी नहीं
तो फिर क्या है जिंदगी के माने

पहली बूंद है बारिश की
पत्ते पर जमी ओस
या सुनहली धूप
जो भी नाम हो
जिंदगी का

जो भी आया यहां
उसे जीना होता

कुछ जिंदगी भोगते है
कुछ ढोते
और
कुछ जिंदगी जीते
एक अध लिखे नाटक
'क्यों पैदा हुआ'
का शुरुआती संवाद
अभी भी पच्चीस बरस बाद रखा
लाल स्याही से लिखा कागज पर।

– गोपाल दुबे

वृक्ष जीवन का आधार भी हैं और वसुधा का श्रृंगार भी

प्राण वायु का स्थाई प्रबंध है एक पेड़ मां के नाम अभियान : मुख्यमंत्री

भोपाल (नप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि जो हमें जीवन दें, सद्मार्ग पर ले जाए, वह सदैव वंदनीय है। हमारे लिए प्रकृति ही परमेश्वर के स्वरूप है, क्योंकि यह हमें जीवन देती है, हमारा उदर-पोषण करती है। इसलिए हम सबको प्रकृतिपूजक बनकर इसकी वंदना करनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि वृक्ष हमारे जीवन का आधार भी हैं और वसुधा का श्रृंगार भी। वृक्ष ऋषि मुनियों के समान एक ही स्थान पर रहकर साधना करते हैं। यह हमारी नकारात्मक ऊर्जा को स्वयं ग्रहण कर हमें सकारात्मक ऊर्जा (प्राण वायु) देने वाले उदार साधक होते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि बंजर भूमि को हरियाली की चादर ओढ़ाना प्रकृति माता को हरी चुनरी ओढ़ाने जैसा है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की पहल पर चलाया जा रहा है 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान कोई शासकीय कार्यक्रम नहीं, ये जीवन के लिए सांसों का स्थायी प्रबंध करने का अभियान है। जल, जंगल, जमीन और जानवर जिनसे हमारा पारिस्थितिकीय-तंत्र तैयार होता है, यह अभियान इनकी सुरक्षा का मिशन है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव रविवार को इन्दौर जिले के ग्राम बुढ़ानिया स्थित सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) परिसर में आयोजित पौधरोपण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने यहां अपनी पूजनीय माता स्व. श्रीमती लीला बाई यादव की स्मृति में संतरे का फलदार पौधा लगाकर इन्दौर में 21 लाख पौधारोपण एवं 51 हजार वर्षा जल संचयन इकाइयों की स्थापना (निर्माण) कार्य के महाभियान का दीप प्रज्ज्वलन कर शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि हमारी संस्कृति में पंच महाभूतों का मान्यता मिली है। इसमें सबसे प्रमुख है जल। जल से ही हमारा जीवन है। एक पेड़ मां के नाम अभियान तथा जल, जंगल एवं पर्यावरण बचाने के पुनीत महाभियान में पूरे समाज की सहभागिता बेहद सराहनीय है। हम सबको मिलकर इस दिशा में आगे आना ही चाहिए।

लाडली बहनों के खातों में सीएम ने किए 1500-1500 रुपए ट्रांसफर

लहार में नया पीजी कॉलेज खोलने की भी घोषणा की, 4 नए स्कूलों का शुभारंभ

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भिंड जिले के लहार में प्रदेश की करीब 1 करोड़ 25 लाख 15 हजार लाडली बहनों के खातों में 38वीं किश्त ट्रांसफर की। इस बार बहनों के खातों में 1835 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि भेजी गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 1000 रुपए से शुरू हुई इस योजना में अब बहनों को हर महीने 1500 रुपए दिए जा रहे हैं। पिछले ढाई सालों में कुल 51,000 करोड़ रुपए सीधे बहनों के खातों में पहुंचाए गए हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने लहार में नया पीजी कॉलेज खोलने की भी घोषणा की।

इसी महीने प्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू होने वाली

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने एक बड़ा ऐलान करते हुए बताया कि इसी महीने प्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू होने वाली है। इससे सभी लोगों, खासकर मुस्लिम महिलाओं को बराबरी का अधिकार मिलेगा।इस कानून को लेकर जनता से 10 लाख से ज्यादा सुझाव मिले हैं। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि शिवपुरी में 2500 करोड़ रुपए की लागत से नई मिसाइल फैक्ट्री बनाई गई है, जो देश की सुरक्षा में बड़ा योगदान देगी। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में बेरोजगारी दर सबसे कम है और सरकार युवाओं को नौकरी देने वाला बनाने का प्रयास कर रही है।

भारत में पहली बार निजी कंपनियां बनाएंगी मिसाइलें

रक्षा क्षेत्र में बड़ा बदलाव करने की तैयारी में केंद्र सरकार

नई दिल्ली (एजेंसी)। भारत अपनी रक्षा नीति में बड़ा बदलाव करने जा रहा है। केंद्र सरकार जल्द ही निजी भारतीय कंपनियों को मिसाइलों के निर्माण और विकास में भागीदारी की परमीशन दे सकती है। अब तक यह क्षेत्र मुख्य रूप से सरकारी रक्षा संस्थानों तक सीमित था। सरकार द्वारा यह फैसला ऐसे समय में लिया जा रहा है, जब ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत की स्वदेशी मिसाइलों की ताकत पूरी दुनिया ने देखी। साथ ही भारत में विकसित मिसाइलों की घरेलू और अंतरराष्ट्रीय मांग लगातार बढ़ रही है। खासकर इंडोनेशिया ने कंपनी द्वारा विकसित अस्त्र मिसाइल में रुचि दिखाई है।

अस्त्र मार्क-2 के निर्माण के लिए आएगा प्रस्ताव

रक्षा मंत्रालय जल्द ही अस्त्र मार्क-2 बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर-टू-एयर मिसाइल के निर्माण के लिए निजी कंपनियों से प्रस्ताव आमंत्रित कर सकता है। इस प्रक्रिया में देश की कई बड़ी निजी कंपनियों के भाग लेने की संभावना है। अस्त्र मार्क-2 मिसाइल को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) ने विकसित किया है। इसकी मारक क्षमता लगभग 180 से 200 किलोमीटर तक बताई जाती है।

बढ़ती मांग के चलते लिया गया फैसला

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय सशस्त्र बलों और मित्र देशों से मिसाइलों की मांग तेजी से बढ़ रही है। मौजूदा उत्पादन क्षमता इस बढ़ती आवश्यकता को पूरी तरह पूरा नहीं कर पा रही है। ऐसे में निजी क्षेत्र की भागीदारी से उत्पादन में तेजी लाने और निर्यात क्षमता बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। अस्त्र के बाद सरकार प्रलय सामरिक बैलिस्टिक मिसाइल के विकास और निर्माण में भी निजी कंपनियों की भागीदारी पर विचार कर रही है।

हैदराबाद को मिलेंगे 'बुलेट ट्रेन' के तीन नए कॉरिडोर

अगले साल से पटरी पर दौड़ेगी देश की पहली बुलेट ट्रेन

हैदराबाद (एजेंसी)। भारत में बुलेट ट्रेन जल्द ही पटरी पर दौड़ेगी। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शनिवार को घोषणा की कि मुंबई और अहमदाबाद के बीच पहली बुलेट ट्रेन का निर्माण कार्य चल रहा है। उन्होंने कहा कि बुलेट ट्रेन का पहला सेक्शन अगले साल शुरू किया जाएगा। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि अगले साल, हम मुंबई-अहमदाबाद रूट पर सूरत और बिलिमोरा के बीच बुलेट ट्रेन का पहला सेक्शन शुरू करेंगे। इसके बाद, एक-एक करके, हम वापी से सूरत, फिर वापी से अहमदाबाद, फिर अहमदाबाद से ठाणे और फिर अहमदाबाद से मुंबई तक का काम पूरा करेंगे। रेल मंत्रालय ने वैष्णव के बयान का एक वीडियो पोस्ट किया और उसके साथ मंत्री का एक कोट भी लिखा। इसमें लिखा था, भारत की पहली बुलेट ट्रेन अपने अगले चरण में प्रवेश कर रही है। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि पुणे और हैदराबाद के बीच का पहला प्रोजेक्ट यात्रा के समय को घटाकर दो घंटे कर देगा, हैदराबाद से मुंबई की यात्रा का समय 2 घंटे 50 मिनट हो जाएगा, हैदराबाद से अमरावती का सफर 1 घंटे 10 मिनट का हो जाएगा, हैदराबाद से चेन्नई का सफर 3 घंटे का होगा, और हैदराबाद से बेंगलुरु का सफर 2 घंटे 35 मिनट का हो जाएगा।

भारत-म्यांमार सीमा व्यापार 6 साल बाद फिर होगा शुरू

लिपुलेख दर्रे से ट्रेड को लेकर चीन की तैयारी हुई तेज

डिब्रूगढ़/नई दिल्ली (एजेंसी)। भारत और म्यांमार के बीच रिश्तों को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। पैंगसाऊ दर्रे पर भारत और म्यांमार के बीच सीमा व्यापार फिर शुरू होने की तैयारी है। करीब छह साल से अधिक समय से ये बंद चल रहा था। हालांकि, अब दोनों पक्षों के व्यापारिक संगठनों की बैठक के बाद 20 जुलाई को फिर से शुरू होने जा रहा है। फ्री मूवमेंट रिजीम के तहत सीमा-पार व्यापार से बॉर्डर के दोनों ओर 10 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले लोगों को स्थानीय व्यापार और सीमा-पार लेन-देन करने की अनुमति मिलती है।

कोविड के दौरान बंद हुआ ट्रेड लिंक

कोविड-19 महामारी के कारण 3 फरवरी, 2020 को बंद किए गए इस ट्रेड लिंक को खोलने का निर्णय लिया गया। ये फैसला स्थानीय व्यापार प्रतिनिधियों और म्यांमार में उनके समकक्षों के बीच 9 जुलाई को अरुणाचल के चांगलांग जिले में व्यापार फिर से शुरू करने की प्रक्रिया को अंतिम रूप देने के लिए हुई बैठक के बाद लिया गया।

नए बाजार के लिए इंतजार कराया

इस साल की खास बात यह थी कि 2020 में धारचूला-लिपुलेख सड़क के पूरा होने के कारण व्यापारी खच्चरों के बजाय सड़क मार्ग से लिपुलेख तक सामान ले जा सकते थे। हालांकि व्यापार का मौसम आधिकारिक तौर पर 1 जून को शुरू हुआ था, लेकिन भारतीय पक्ष में तैयारियां महीने के अंत तक ही पूरी हो पाईं।

पैंगसाऊ दर्रे से शुरू होगा ट्रेड

भारतीय पक्ष के एक स्थानीय व्यापार संगठन के अध्यक्ष जोंगखम मोरांग ने कहा कि हमें उम्मीद है कि इससे महामारी के दौरान खोई हुई आजीविका वापस आएगी। स्थानीय विधायक लैसम सिमाई ने कहा कि सीमा व्यापार के फिर से शुरू होने से बेहतर व्यापारिक अवसर पैदा होंगे। छोटे व्यापारियों और निवासियों की आजीविका में सुधार होगा, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को काफी बढ़ावा मिलेगा। बॉर्डर हाट हर महीने की 10, 20 और 30 तारीख को चलेगी। रिपोर्ट के अनुसार, भारत-चीन सीमा व्यापार का मौसम आधिकारिक तौर पर शुरू होने के एक महीने से अधिक समय बाद भी लिपुलेख दर्रे के माध्यम से सीमा-पार व्यापार शुरू नहीं हो पाया है। चीनी अधिकारियों ने भारतीय व्यापारियों से तिब्बत के तकलाकोट में एक नए बाजार और गोदाम का निर्माण पूरा होने तक इंतजार करने को कहा है। कोविड-19 के कारण 2020 में लिपुलेख के माध्यम से सीमा व्यापार को निलंबित कर दिया गया था और छह साल के अंतराल के बाद इसे फिर से शुरू किया गया था।

भोपाल का तापमान

अधिकतम 20 °c | न्यूनतम 18°c

सुबह सवेरे

जो अग्नि हमें गर्मी देती है , हमें नष्ट भी कर सकती है ; यह अग्नि का दोष नहीं है।

चाणक्य नीति

इंदौर ■ सोमवार, 13 जुलाई 2026

संक्षिप्त समाचार

महाराष्ट्र टीईटी पेपर लीक मामले में बड़ा खुलासा

- जूतों में छिपाकर बाहर लाया गया था टीईटी का पेपर

नई दिल्ली (एजेंसी)। महाराष्ट्र में 28 जून 2026 को आयोजित होने वाली शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) 2026 पेपर लीक के चलते एक दिन पहले यानी 27 जून को रद्द कर दी गई थी। अब इस परीक्षा को दोबारा आयोजित कराया जाएगा जिसकी नई तारीख का ऐलान होना बाकी

है, लेकिन पेपर लीक की जांच के बीच कुछ नए खुलासे हुए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, महाराष्ट्र टीईटी का पेपर आगरा के उस प्रिंटिंग प्रेस से लीक हुआ था जहां इस पेपर की छपाई होनी थी। बता दें कि यह परीक्षा 28 जून को 1028 सेंटर्स पर आयोजित होनी थी 6 लाख से अधिक उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल होने थे। रिपोर्ट के मुताबिक, 15 और 17 जून के बीच प्रिंटिंग प्रेस के एक एम्प्लॉई ने क्वेश्चन पेपर्स की मुड़ी हुई कॉपियां अपने जूते के सोल के नीचे छिपाकर प्रिंटिंग प्रेस से बाहर निकाली थी।

पहलगाम में बादल फटा उत्तराखंड में लैंडस्लाइड

- पहाड़ों के लिए आफत बनी बारिश,सड़क बही-खेत बर्बाद

श्रीनगर (एजेंसी)। पहाड़ी राज्यों में बारिश के चलते नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में बादल फटने के बाद बाढ़ आई। कई खेत बर्बाद हो गए, सड़क बह गई। उत्तराखंड के विकासनगर में भारी बारिश के कारण लखवाड़ हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट में लैंडस्लाइड हो गई। कई वाहन और मशीनें मलबे में दब गईं। उधर, देश के लगभग 70 फीसदी हिस्से से मानसून के बादल गायब हो गए हैं। राजस्थान, दिल्ली-एनसीआर, पश्चिमी मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र में अगले 5 दिन तक बारिश की संभावना भी कम है। बारिश रुकने से मध्य प्रदेश, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश समेत उत्तर भारत के राज्यों में तापमान बढ़ गया। श्रीगंगानगर में तापमान 42 डिग्री रहा।

पीएम के पंजाब दौरे से पहले ट्रेन में खालिस्तानी नारे

- आतंकी पन्नू ने वीडियो जारी किया,खालड़ा का भी जिक्र

जालंधर (एजेंसी)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पंजाब दौरे से पहले फिरोजपुर कैंट रेलवे स्टेशन का एक वीडियो सामने आया है। यह वीडियो प्रतिबंधित अलगाववादी संगठन सिख फॉर जस्टिस (एसएफजे) ने जारी किया है। वीडियो में दिल्ली जाने वाली एक ट्रेन के डिब्बों पर खालिस्तान जिंदाबाद और मोदी मुर्दाबाद जैसे नारे लिखे दिखाई दे रहे हैं। एसएफजे के आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने वीडियो जारी कर पंजाब में आतंकवाद के दौर के मानवाधिकार कार्यकर्ता जसवंत सिंह खालड़ा की विरासत का जिक्र करते हुए कथित एनकाउंटर मामलों को उठाया। हालांकि,हमारा अखबार पन्नू के वीडियो की पुष्टि नहीं करता। जसवंत सिंह खालड़ा पर ही दिलजीत दोसांझ की फिल्म सतलुज बनी थी, जिसे रिलीज होने के दूसरे दिन ही हटा दिया गया था और अब पूरी तरह से बैन कर दिया गया है।

यूट्यूबर्स और इन्फ्लुएंसर्स के लिए सीएम मोहन यादव का बड़ा ऐलान

अच्छा वीडियो बनाओ, सरकार देगी इनाम

इंदौर (नप्र)। मध्य प्रदेश के यूट्यूबर्स, रील मेकर्स और डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स के लिए एक बड़ी और अच्छी खबर है। इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में आयोजित 'मध्य प्रदेश युवा कॉन्क्लेव-2026' में पहुंचे मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने ऐलान किया है कि सकारात्मक और जागरूकता फैलाने वाले वीडियो बनाने वाले क्रिएटर्स को अब सरकार 'डिजिटल कंटेंट अवॉर्ड' से सम्मानित करेगी और उन्हें नकद इनाम भी दिया जाएगा।

कॉन्क्लेव के दौरान सीएम ने इंदौर, उज्जैन, धार समेत मालवा-निमाड़ से आए सैकड़ों डिजिटल इन्फ्लुएंसर्स से सीधा संवाद किया। उन्होंने युवाओं के काम को सराहते हुए कहा कि आज की पीढ़ी सोशल मीडिया के जरिए समाज में बड़ा बदलाव ला रही है।

आज का युवा केवल कंटेंट नहीं बना रहा, बल्कि वो समाज को जोड़ रहा है और नई पीढ़ी की आकांक्षाओं को स्वर दे रहा है। सकारात्मक सोच और सामाजिक सरोकार के साथ काम करने वाले इन युवाओं को प्रोत्साहित करना बेहद जरूरी है, इसीलिए हम इस राजकीय अवॉर्ड की शुरुआत कर रहे हैं।

सरकार का मानना है कि इस कदम से राज्य में गुणवत्तापूर्ण और जिम्मेदार डिजिटल कंटेंट को बढ़ावा मिलेगा। इस योजना के तहत शिक्षा, पर्यटन, संस्कृति और सामाजिक जागरूकता जैसे विषयों पर बेहतरीन वीडियो बनाने वालों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा।

बंगाल में 20 साल बाद टाटा की वापसी संभव

सीएम शुभेंदु अधिकारी खुद मामले को देख रहे

ममता बनर्जी के आंदोलन से बंद हुआ था प्लांट

कोलकाता (एजेंसी)। पश्चिम बंगाल के सिंगूर में करीब दो दशक पहले टाटा की नैनो परियोजना को लेकर शुरू हुआ विवाद एक बार फिर सुर्खियों में है। राज्य में भाजपा सरकार बनने के बाद टाटा समूह की सिंगूर में वापसी को लेकर चर्चा तेज हो रही है। राज्य के उद्योग मंत्री तापस रॉय ने कहा कि टाटा के साथ शुरुआती स्तर पर बातचीत चल रही है। अगर टाटा ग्रुप लौटने को तैयार होता है तो सरकार वहां किसी दूसरी कंपनी को नहीं लाएगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी खुद मामले की निगरानी कर रहे हैं। हालांकि, जिन किसानों ने 2006 में नैनो के लिए अपनी जमीन दी थी, उनके लिए यह अधूरा सपना है।

997 एकड़ जमीन बेकार हो रही

वर्तमान में सिंगूर की वह 997 एकड़ जमीन, जहां कभी नैनो परियोजना शुरू हुई थी, बड़े हिस्से में झाड़ियों से ढकी पड़ी है। कभी यह इलाका पश्चिम बंगाल की सबसे उपजाऊ कृषि भूमि माना जाता था, जहां धान, आलू और अन्य फसलें होती थीं। लेकिन परियोजना रुकने के बाद खेती भी प्रभावित हुई और बड़ी संख्या में किसान रोजगार की तलाश में दूसरे क्षेत्रों में चले गए। हालांकि, सिंगूर में सभी लोग टाटा की वापसी के पक्ष में नहीं हैं। सिंगूर कृषि रक्षा समिति के प्रमुख सदस्य प्रबीर पात्रा का कहना है कि उनका विरोध उद्योगों से नहीं था।

टाटा को जमीन देने के लिए तैयार हैं लोग

75 साल की अंगूर दास बताती हैं कि उनके पति ने छह बीघा जमीन परियोजना के लिए दी थी। टाटा के जाने के बाद वे गहरे सदमे में चले गए और वर्ष 2019 में उनका निधन हो गया। अंगूर दास कहती हैं कि यदि टाटा दोबारा लौटती है तो वे अपनी बची हुई जमीन भी देने को तैयार हैं। जब सिंगूर आंदोलन चल रहा था तब अनिद्य दास महज 12 साल के थे। आज 32 साल के अनिद्य को रोजगार के लिए कोलकाता जाना पड़ता है। उनका कहना है कि यदि फैक्ट्री लग गई होती तो उन्हें रोज शहर जाकर नौकरी नहीं करनी पड़ती। उनके पिता ने भी जमीन दी थी, लेकिन आज वह जमीन भी खेती के योग्य नहीं बची है। खासेरभेड़ी गांव के स्वरूप दास ने भी दो बीघा जमीन परियोजना के लिए दी थी। वे बताते हैं कि मुआवजा मिलने के बाद वे दुबई चले गए थे, जबकि उनके दोनों भाइयों का चयन टाटा ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रशिक्षण के लिए किया था। उत्तराखंड में ट्रेनिंग शुरू हो चुकी थी और नौकरी की उम्मीद भी थी, लेकिन परियोजना बंद होने के साथ सारे सपने टूट गए।

सीएम सम्राट ने मुजफ्फरपुर को दी 1047 करोड़ की सौगात

- आर्किटेक्चर और सिविल इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय बनाने की घोषणा

मुजफ्फरपुर (एजेंसी)। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने रविवार को मुजफ्फरपुर जिले को 1047 करोड़ रुपये की सौगात दी। इस मौके पर उन्होंने मुजफ्फरपुर के एमआईटी कॉलेज में आर्किटेक्चर और सिविल इंजीनियरिंग

विश्वविद्यालय बनाने की घोषणा की। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि विकसित भारत का रास्ता विकसित बिहार से होकर गुजरता है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार 12 शहरों में पटना के कंकड़बाग की तर्ज पर सैटेलाइट सिटी विकसित करेगी, जिससे शहरी विकास को नई गति मिलेगी।

विकास की गति बनाए रखने सभी का सहयोग जरूरी

सम्राट चौधरी ने कहा कि बाबा गरीबनाथ की पावन धरती पर 1,047.09 करोड़ रुपये की 982 विकास योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया गया है। उन्होंने कहा कि ये योजनाएं जिले के विकास को नई दिशा देंगी। मुख्यमंत्री ने केंद्र और राज्य सरकार के तालमेल की चर्चा करते हुए कहा कि समृद्ध बिहार और विकसित भारत का रास्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतिश कुमार की जोड़ी से होकर जाता है।

संसद सत्र से पहले सरकार ने बुलाई सर्वदलीय बैठक

- विपक्ष के साथ आने वाले बिलों को लेकर होगी चर्चा

नई दिल्ली (एजेंसी)। संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हो रहा है। इससे पहले ठीक एक दिन पहले सरकार 19 जुलाई को सर्वदलीय बैठक करने जा रही है। बैठक में इस सत्र के दौरान होने वाली महत्वपूर्ण चर्चा की योजना को लेकर बातचीत की जा सकती है। सर्वदलीय बैठक में सरकार विपक्ष को यह भी बताएगी कि इस सत्र में कौन से बिल पेश किए जा सकते हैं। संसद सत्र के एक दिन पहले यानी 19 जुलाई को होने वाली सर्वदलीय बैठक का समय सुबह 11 बजे निर्धारित किया गया है। दरअसल, सरकार मानसून सत्र को सुचारु रूप से संचालित करना चाहती है।

अमेरिका के हवाई हमले के बाद भड़का ईरान

गालिबाफ बोले-एकतरफा समझौतों का दौर खत्म हो चुका

तेहरान (एजेंसी)। ईरान और अमेरिका के बीच हवाई हमले बढ़ गए हैं। टकराव की रफ्तार में इजाफा पूरी दुनिया के लिए चिंता की वजह बना हुआ है। इस बीच ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बाघेर गालिबाफ ने स्पष्ट किया कि अब एकतरफा समझौतों का दौर खत्म हो चुका है। अपने कड़क और तीखे तेवरों के लिए पहचाने जाने वाले गालिबाफ ने सोशल मीडिया पोस्ट एक्स पर लिखा, हमने पहले ही कहा था- वादा

निभाओ, नहीं तो कीमत चुकाओ। अब हकीकत सामने है। उन्होंने अपनी पोस्ट के साथ अमेरिका-ईरान समझौता मसौदे के अनुच्छेद-5 की तस्वीर भी साझा की। यह अनुच्छेद होर्मुज स्ट्रेट को दोबारा खोलने से जुड़ा है। इसी को लेकर विवाद बढ़ा और उसने फिर से सैन्य टकराव का रुख अख्तियार कर लिया है। इस बीच, ईरानी सेना ने अमेरिका से जून में हुए समझौते (एमओयू) का पालन करने को कहा है।

अमेरिका और ईरान के एक-दूसरे पर हमले

अमेरिकी हमलों के जवाब में ईरान ने भी गल्फ क्षेत्र में स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले तेज कर दिए हैं। रविवार को बहरीन में अमेरिकी सैन्य अड्डे से धुआं उठता दिखाई दिया। सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में बेस के ऊपर धुएं का गुबार नजर आ रहा है। एजेंसी ने दावा किया कि उसने जॉर्डन में एक अमेरिकी कमांड कंट्रोल यूनिट और ड्रोन हैंग को तबाह कर दिया। इससे पहले ईरान ने सुबह दावा किया था कि उसने बहरीन में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को ड्रोन और मिसाइलों से निशाना बनाया है। बहरीन में भी मिसाइल अलर्ट जारी किया गया और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए कहा गया था। वहीं, अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने रविवार सुबह बताया कि उसने ईरान के 140 सैन्य ठिकानों पर हमले किए हैं।

इंफाल में मैतेई लोगों के घरों में भीषण आगजनी

- मणिपुर में फिर से भड़की हिंसा कई घर जलाए

इंफाल (एजेंसी)। मणिपुर की राजधानी इंफाल के पश्चिमी क्षेत्र में मैतेई समुदाय के लोगों के घरों को जलाने की घटना के बाद इलाके में तनाव पैदा हो गया है। आगजनी की इस घटना के बाद पीड़ित समुदाय के करीब 600 लोगों के समूह ने पथराव करना शुरू कर दिया।

कांतो सबल इलाके में शनिवार को हुई इस घटना के बाद प्रशासन सक्रिय हो गया और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात कर दिए गए हैं। सुरक्षा बलों ने टकराव से बचाव के लिए गश्त बढ़ा दी है और लोगों को एकत्रित नहीं होने दे रहे हैं। बताया गया है कि आगजनी की घटना में ज्यादातर उन घरों में आग लगाई गई जो खाली पड़े थे।

एमपी ट्रांसको के ट्रेनीज असिस्टेंट इंजीनियरों को दिया गया ट्रांसमिशन लाइन के मेंटेनेंस का व्यावहारिक प्रशिक्षण

भोपाल (नप्र)। मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी के सहायक अभियंता (अस्सिटेंट इंजीनियर) प्रशिक्षुओं ने 132 केवी भोपाल-बगरोदा ट्रांसमिशन लाइन पर फ्लैशओवर से प्रभावित डिस्क इंसुलेटर के रिप्लेसमेंट के लिये लिए गए शटडाउन कार्य के दौरान महत्वपूर्ण व्यावहारिक प्रशिक्षण प्राप्त किया

प्रशिक्षुओं ने शटडाउन लेने की संपूर्ण प्रक्रिया, सुरक्षा मानकों, वर्क परमिट व्यवस्था, लाइन को सुरक्षित रूप से आइसोलेट करने की कार्यवाही तथा कार्यस्थल पर उपयोग किए जाने वाले विभिन्न टूल्स की जानकारी प्राप्त की। साथ ही उन्होंने डिस्क इंसुलेटर बदलने की वास्तविक प्रक्रिया को निकट से देखा और ट्रांसमिशन लाइन के मेंटेनेंस कार्यों की तकनीकी बारीकियों को समझा। विद्युत क्षेत्र के अभियंताओं के लिए इस प्रकार के फील्ड प्रशिक्षण में सुरक्षा प्रक्रियाओं एवं उपकरणों के संचालन का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हुआ। मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी भोपाल के कार्यपालन अभियंता श्री रवि चौरसिया एवं सहायक अभियंता श्री अंकित महरौलिया ने स्वयं प्रशिक्षुओं को शटडाउन प्रबंधन, कार्यस्थल पर सुरक्षा तथा एक्स्ट्रा हाई टेंशन लाइनों के रखरखाव से जुड़े विभिन्न पहलुओं की जानकारी दी। प्रशिक्षण के माध्यम से प्रशिक्षुओं को सैद्धांतिक ज्ञान के साथ वास्तविक कार्य परिस्थितियों में कार्य निष्पादन की समझ विकसित करने का अवसर मिला।

इंदौर समेत मप्र के 27 जिलों में आज हल्की बारिश

भोपाल, उज्जैन-ग्वालियर में बढ़ा रहेगा तापमान, अगले 4 दिन ऐसा ही मौसम

भोपाल (नप्र)। मध्य प्रदेश में अगले 4 दिन बादल और हल्की बारिश का दौर ही रहेगा। कहीं भी भारी बारिश का अलर्ट नहीं है। मौसम विभाग ने इंदौर समेत 27 जिलों में बूंदाबांदी का अलर्ट जारी किया है। भोपाल, ग्वालियर और उज्जैन में दिन के तापमान में बढ़ोतरी होगी।

जिन जिलों में आंधी-बारिश का अनुमान है, उनमें भिंड, दतिया, सतना, रीवा, मऊगंज, सीधी, सिंगरौली, शहडोल, अनूपपुर, डिंडौरी, मंडला, बालाघाट, सिवनी, पांढुर्णा, छिंदवाड़ा, नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, खंडवा, बुरहानपुर, देवास, इंदौर, खरगोन, धार, बड़वानी, झाबुआ और आलीराजपुर शामिल हैं।

वहीं, ग्वालियर, श्योपुर, मुरैना, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, विदिशा, रायसेन, सागर, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, दमोह, जबलपुर, कटनी, उमरिया, भोपाल, सीहोर, राजगढ़, शाजापुर, आगर-मालवा, उज्जैन, रतलाम, मंदसौर और नीमच में मौसम साफ रहने का अनुमान है।

मध्य प्रदेश में पिछले 3 दिन से तेज बारिश नहीं हुई है। इस वजह से दिन के तापमान में भी बढ़ोतरी देखने को मिली है। शनिवार को राज्य में तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा रहा। उमस का असर भी बना रहा।

प्रदेश में 10 प्रतिशत बारिश ज्यादा

प्रदेश में इस बार पूरे जून महीने आंधी-बारिश का दौर रहा। इसके बावजूद कोटे से 30 प्रतिशत पानी कम बरसा। जुलाई के 9 दिन ने यह कोटा न सिर्फ पूरा कर दिया, बल्कि 10 प्रतिशत ज्यादा पानी बरसा दिया।

हालांकि, पिछले तीन दिन से बारिश नहीं होने से ओवरऑल आंकड़ा घटकर 8 प्रतिशत पर आ गया है। मौसम विभाग ने बताया कि प्रदेश में औसत 9.4 इंच बारिश हो चुकी है। अब तक 8.7 इंच पानी गिरना था। इस हिसाब से 8 प्रतिशत ज्यादा बारिश हुई है। यह कोटे की 25 प्रतिशत है।

जून में कम बारिश, जुलाई से उम्मीदें

मौसम विभाग के अनुसार, जून में कम बारिश हुई है लेकिन जुलाई से काफी उम्मीदें हैं। इस महीने पूरे मानसून की एक तिहाई बारिश का ट्रेंड है। जैसे- भोपाल में 39 इंच सामान्य बारिश है तो 14 इंच बारिश जुलाई में होती है। बड़े शहरों में जबलपुर ही ऐसा है, जहां सबसे ज्यादा 17 इंच से ज्यादा बारिश होती है। जुलाई के महीने में ही प्रदेश में कोटे की 40 प्रतिशत तक बारिश होती है।

प्रदेश की सामान्य बारिश 37.3 इंच है। भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर जिले की सामान्य बारिश 38 से 39 इंच तक है।

सरकारी आवास में महिला पोस्टल असिस्टेंट की हत्या, पति भाग गया

स्कूल से लौटकर बच्चों ने मां का खून से लथपथ शव देखा

इंदौर। डाक कुंज कॉलोनी स्थित ग्राउंड फ्लोर के सरकारी आवास में शनिवार को डाक विभाग की पोस्टल असिस्टेंट उर्मिला सैनी (38) की हत्या कर दी गई। दोपहर करीब 1 बजे स्कूल से लौटे दोनों बच्चों ने घर के भीतर मां का खून से लथपथ शव देखा। घटना के बाद से महिला का पति अखिलेश सैनी फरार है। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है।

परिजनों के अनुसार, शनिवार सुबह करीब 9 बजे अखिलेश बच्चों के स्कूल पहुंचा और कहा कि वह और उनकी मां भोपाल जा रहे हैं। उसने बच्चों को मौसी के घर चले जाने को कहा। साथ ही बेटी को घर की चाबी, एटीएम कार्ड और जेवरात की जानकारी भी दी तथा बताया कि एक्टिवा स्कूल में ही रहेगी। हालांकि, छुट्टी के बाद दोनों बच्चे मौसी के घर जाने के बजाय सीधे घर पहुंचे। मुख्य दरवाजा खुला था और टीवी तेज आवाज में चल रहा था। अंदर पहुंचते ही उन्होंने मां का शव देखा। घबराए बच्चों ने अपने नाना सत्यनारायण

मालाकार को फोन किया। सूचना मिलने पर आसपास के लोग पहुंचे और पुलिस को खबर दी। बेटी 9वीं कक्षा में पढ़ती है, जबकि बेटा 4वीं कक्षा का छात्र है। सूचना मिलते ही संयोगितागंज और पलासिया थाना पुलिस, एसीपी निधि दंडोतिया तथा एफएसएल टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटा कर शव को पोस्टमार्टम के लिए एमवाय अस्पताल भेज दिया। प्रारंभिक जांच में पति-पत्नी के बीच विवाद को हत्या की संभावित वजह माना जा रहा है।

लंबे समय से चल रहा विवाद

महिला के परिजनों का आरोप है कि अखिलेश कोई काम नहीं करता था और अक्सर उर्मिला से विवाद करता था। उनका कहना है कि आपसी झगड़े के दौरान उसने पत्नी की हत्या कर दी और फरार हो गया। स्थानीय लोगों के मुताबिक, अखिलेश वर्क फ्रॉम होम के तहत अगरबत्ती ट्रेडिंग का काम करता और पत्नी पर शक करता था। भोपाल में रहने के दौरान भी दोनों के बीच विवाद हुआ था। उर्मिला एमजी रोड स्थित डिविजनल ऑफिस में पोस्टल असिस्टेंट थीं। दोनों बच्चे पढ़ाई में होनहार बताए जाते हैं।

फरार आरोपी पति की तलाश

फरार आरोपी पति अखिलेश सैनी की तलाश तेज कर दी है। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की अलग-अलग टीमें संभावित ठिकानों पर लगातार दबिश दे रही हैं। अधिकारियों का दावा है कि तकनीकी इनपुट और मुखबिरों से मिली जानकारी के आधार पर आरोपी को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पुलिस जांच के अनुसार, आरोपी ने कथित रूप से धारदार हथियार से पत्नी की हत्या करने के बाद अपनी बेटी के स्कूल पहुंचकर उसे एटीएम कार्ड और उसका पिन सौंपा तथा वहां से फरार हो गया। इसके बाद से वह लगातार अपने ठिकाने बदल रहा है।

मुंबई-पुणे में भारी बारिश का असर कई ट्रेनें बदले हुए मार्ग से चलेंगी

इंदौर। मुंबई एवं पुणे क्षेत्र में लगातार हो रही भारी वर्षा के कारण रेल यातायात प्रभावित हुआ है। जलभराव, मुंबई-पुणे घाट सेक्शन में भूस्खलन तथा रेलवे ट्रैक पर बोल्डर गिरने की घटनाओं के चलते पश्चिम रेलवे और मध्य रेलवे के विभिन्न रेलखंडों पर ट्रेनों का संचालन प्रभावित हुआ है।

पश्चिम रेलवे रतलाम मंडल के जनसंपर्क अधिकारी मुकेश कुमार द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया है कि प्रभावित परिस्थितियों को देखते हुए रतलाम मंडल से होकर गुजरने वाली कुछ ट्रेनों का संचालन परिवर्तित मार्ग से किया जाएगा।

इन ट्रेनों का मार्ग बदला गया

16 जुलाई 2026 को सोलापुर से रवाना होने वाली गाड़ी संख्या 09628 सोलापुर-अजमेर स्पेशल अब दौंड, मनमाड, जलगांव, पालधी और सूरत होकर चलेगी।

- 12 जुलाई 2026 को दौंड से प्रस्थान करने वाली गाड़ी संख्या 22193 दौंड-ग्वालियर एक्सप्रेस का संचालन भी दौंड, मनमाड, जलगांव, पालधी और सूरत मार्ग से किया जाएगा।
- 15 जुलाई 2026 को अजमेर से रवाना होने वाली गाड़ी संख्या 09627 अजमेर-सोलापुर स्पेशल सूरत, पालधी, मनमाड और दौंड होकर अपने गंतव्य तक पहुंचेगी।
- 11 जुलाई 2026 को ग्वालियर से चलने वाली गाड़ी संख्या 22194 ग्वालियर-दौंड एक्सप्रेस का मार्ग भी बदल दिया गया है। यह ट्रेन सूरत, पालधी और मनमाड होकर चलेगी।
- इसी तरह 16 जुलाई 2026 को अजमेर से प्रस्थान करने वाली गाड़ी संख्या 20991 अजमेर-दौंड एक्सप्रेस का संचालन भी सूरत, पालधी और मनमाड मार्ग से किया जाएगा।

यात्रियों से सतर्कता की अपील

रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि यात्रा पर निकलने से पहले अपनी ट्रेन की नवीनतम स्थिति की जानकारी अवश्य प्राप्त कर लें, ताकि किसी प्रकार की असुविधा से बचा जा सके। भारी वर्षा के कारण हालात सामान्य होने तक परिचालन में आवश्यकतानुसार बदलाव किए जा सकते हैं।

सुसाइड नोट लिखकर आत्महत्या की

इंदौर। मेरी मौत पर ज्यादा पैसा खर्च मत करना। जिनके लिए मुझे जीना था, वही छोड़कर चले गए। यह सुसाइड नोट युवक ने खुदकुशी करने से पहले लिखा। युवक ऑटो चालक था। शुक्रवार रात उसने घर पर खाना खाया और बाद में जहर खाकर जान दे दी। शनिवार सुबह जब वह काफी देर तक नहीं उठा तो परिजनों ने दरवाजा तोड़ा। घटना एरोड्रम थाना क्षेत्र की है। मृतक का नाम रघुनाथ (50) है। पुलिस को उसके पास से एक पेज का सुसाइड नोट मिला। जांच में सामने आया है कि डेढ़ साल पहले 22 वर्षीय बेटे आदित्य की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। पिछले महीने बेटी भी घर छोड़कर चली गई थी। परिवार में लगातार हुई इन घटनाओं से वह तनाव में रहने लगा था। तनाव के चलते वह पत्नी से भी विवाद करने लगा था। सुसाइड नोट में यह भी लिखा कि वह अपनी मर्जी से आत्महत्या कर रहा है और इसके लिए किसी को जिम्मेदार न ठहराया जाए। उसने लिखा कि इतने बड़े संसार में वह पत्नी को अकेला छोड़कर जा रहा है, लेकिन उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था, क्योंकि जिनके लिए जीना था, वे उससे बिछड़ चुके हैं।

10 हजार के इनामी तस्कर पकड़ाए

इंदौर। क्राइम ब्रांच की टीम लगातार मादक पदार्थों की खरीद फरोख्त रोकने में लगा हुआ है। लेकिन, कड़ी कार्रवाई नहीं होने से तस्करी की घटनाएं कम नहीं हो रही है। इसी क्रम में पुलिस ने 10 हजार के इनाम दो तस्करों को मंदसौर से गिरफ्तार किया है। दोनों की लंबे समय से तलाश थी। पकड़े गए आरोपियों के साथी खालिद हुसैन एवं नदीम खान को पिछले दिनों पुलिस ने 151 ग्राम एमडी ड्रग्स के साथ गिरफ्तार किया गया था। दोनों ने पूछताछ में अपने साथियों शाहिद एवं महफूज से मादक पदार्थ लेना बताया था। इसके बाद से पुलिस को शाहिद पिता युसूफ खान निवासी अभिन कालोनी मंदसौर और मह?फूज पिता मुबारिक खान निवासी मंदसौर की तलाश थी। आरोपी शाहिद मंदसौर अनाज मंडी में मजदूरी करता है। जबकि, महफूज ड्राइवर है। दोनों आरोपियों से कड़ाई से पूछताछ की जा रही है।

घेराबंदी देख बाइक छोड़ भागा शराब तस्कर

इंदौर। शहर में अवैध शराब के कारोबार पर अंकुश लगाने के लिए आबकारी विभाग की कार्रवाई लगातार जारी है। शनिवार को काछी मोहल्ला वृत्त में घेराबंदी के दौरान एक शराब तस्कर बाइक छोड़कर फरार हो गया। टीम ने मौके से 300 पाव अवैध देशी शराब और दोपहिया वाहन जब्त कर लिया। आरोपी के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी गई है। कार्रवाई सहायक आयुक्त आबकारी अभिषेक तिवारी के निर्देश पर डिप्टी कंट्रोलर मनोज अग्रवाल एवं सहायक जिला आबकारी अधिकारी अनिल माथुर के नेतृत्व में हुई। उपनिरीक्षक भगवानदास अहिरवार की टीम ने गश्त के दौरान संदिग्ध बाइक का पीछा किया। सुभाष नगर चौराहे के पास घेराबंदी होते ही चालक वाहन छोड़कर भाग निकला। तलाशी में बोरे से 200 पाव देशी प्लेन तथा डिक्की से 50 पाव देशी मसाला और 50 पाव देशी प्लेन शराब बरामद हुई। मामले में धारा 34(1)(क) एवं 34(2) के तहत विवेचना जारी है।

पटवारी संघ अध्यक्ष का तबादला बना विवाद

इंदौर। मध्य प्रदेश पटवारी संघ जिला शाखा इंदौर ने जिला अध्यक्ष मनोज परिहार के स्थानांतरण सहित पांच सूत्रीय मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ आंदोलन की चेतावनी दी। संघ का आरोप है कि 16 जून को जारी स्थानांतरण सूची में नियमों के विपरीत मनोज परिहार का तबादला भिचौली हप्सी से देपालपुर कर दिया गया। इस संबंध में जिला कलेक्टर को ज्ञापन देने के बावजूद न तो कोई जवाब मिला और न ही कार्रवाई हुई। संघ ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि पदाधिकारियों को चर्चा के लिए बुलाकर पांच सूत्रीय मांगों का समाधान कराया जाए। साथ ही मनोज परिहार का स्थानांतरण निरस्त करने और कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान के लिए नियमित परामर्शदात्री समिति की बैठक आयोजित करने की भी मांग की गई है। संघ ने चेतावनी दी है कि यदि सात दिनों के भीतर मांगों का समाधान नहीं हुआ तो प्रदेशव्यापी आह्वान के तहत 15 से 17 जुलाई तक तीन दिवसीय सांकेतिक आंदोलन किया जाएगा।

चित्र परिचय

जिला न्यायालय परिसर में रविवार को विशेष सफाई अभियान चलाया गया। यह अभियान इंदौर अभिभाषक संघ की कार्यकारिणी की पहल पर आयोजित हुआ। संघ के अध्यक्ष के नेतृत्व में पदाधिकारियों की मौजूदगी में अभिभाषकों की बैठकों और न्यायालय परिसर के विभिन्न हिस्सों की व्यापक सफाई कराई गई। बताया गया कि कुछ दिन पहले एमआईसी सदस्य जिला न्यायालय पहुंचे थे। इस दौरान अभिभाषक संघ के अध्यक्ष ने उन्हें परिसर में सफाई और आवश्यक कार्यों की जरूरत से अवगत कराया था। इसके बाद नगर निगम के सहयोग से रविवार को विशेष सफाई अभियान चलाया गया। अभियान का उद्देश्य न्यायालय परिसर को स्वच्छ, व्यवस्थित और बेहतर कार्य वातावरण उपलब्ध कराना रहा। अभिभाषक संघ ने कहा कि परिसर की साफ-सफाई और अन्य सुविधाओं में सुधार के लिए भविष्य में भी इसी तरह के प्रयास जारी रहेंगे। अभियान को अधिवक्ताओं ने भी सराहा और इसे न्यायालय परिसर की व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने की सकारात्मक पहल बताया।

रातभर चला पुलिस का सर्च अभियान 511 बदमाशों पर कार्रवाई की गई

- 201 नशाखोर वाहन चलाते मिले, 222 से अधिक वारंट की तामील

इंदौर। शहर में अपराधियों और असामाजिक तत्वों पर शिकंजा कसते हुए इंदौर पुलिस ने शनिवार-रविवार की दरमियानी रात विशेष अभियान चलाया। चारों जोन में एक साथ हुई कार्रवाई के दौरान 511 बदमाशों और संदिग्धों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की गई। अभियान में लंबे समय से फरार अपराधियों की तलाश, वारंट तामील, नशाखोरों, शराब पीकर वाहन चलाने वालों और अवैध हथियार रखने वालों पर भी सख्त कार्रवाई की गई। पुलिस ने अभियान के दौरान 222 से अधिक वारंट तामील कराए, जिनमें 56 स्थायी, 61 गिरफ्तारी और 105 जमानती वारंट शामिल हैं। वहीं शराब पीकर वाहन चलाने वाले 201 वाहन चालकों के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 185 के तहत कार्रवाई की गई। सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने वाले 17 लोगों तथा मादक पदार्थ का सेवन करने वाले तीन आरोपियों के खिलाफ भी प्रकरण दर्ज किए गए। इसके अलावा कनाड़िया और बाणगंगा थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक चाकू और एक खंजर के साथ दो आरोपियों को गिरफ्तार कर आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज किया। अभियान के दौरान 60 आदतन बदमाशों के विरुद्ध प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई। सक्रिय अपराधियों को थानों में बुलाकर डोजियर

भरवाए गए और दोबारा अपराध करने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई। पुलिस ने हॉटस्पॉट और शैडो क्षेत्रों में ड्रोन से निगरानी की, जबकि संवेदनशील इलाकों में पैदल गश्त कर संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी। अधिकारियों ने आम लोगों से संवाद कर साइबर अपराध, महिला सुरक्षा, नशे के दुष्परिणाम और सड़क सुरक्षा को लेकर भी जागरूक किया।

तीन आत्महत्याओं से सनसनी

ठेकेदार समेत युवक, महिला मजदूर ने जान दी

- कनाड़िया, छत्रीपुरा और भंवरकुआं क्षेत्र की घटनाओं की जांच जारी

इंदौर। रविवार को अलग-अलग थाना क्षेत्रों से आत्महत्या के तीन मामले सामने आए हैं। कनाड़िया क्षेत्र में एक ठेकेदार, छत्रीपुरा में एक युवक और भंवरकुआं क्षेत्र में एक महिला मजदूर ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। तीनों मामलों में पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है।

कनाड़िया थाना क्षेत्र की भूरी टेकरी स्थित आईडीए बिल्डिंग में रहने वाले 36 वर्षीय भीम सिंह चौहान का शव रविवार सुबह उनके घर के कमरे में फंदे पर लटका मिला। भीम सिंह ड्रेनेज लाइन डालने का ठेका लेते थे। सुबह उनकी पत्नी ने उन्हें फंदे पर लटका देखा और नीचे रहने वाले छोटे भाई अरुण चौहान को सूचना दी। इसके बाद परिजन उन्हें तत्काल एमवाय अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

महिला के दबाव, तनाव की बात

मृतक के भाई अरुण चौहान ने पुलिस को बताया कि परिवार पिछले 3 वर्षों से यहां रह रहा है। उनके अनुसार सामने रहने वाली एक महिला से भीम सिंह की बातचीत होती थी। महिला कथित रूप से उन पर शादी करने और साथ रहने का दबाव बना रही थी। भीम सिंह पहले से विवाहित थे और उनके 3 बच्चे हैं। परिवार में उनके पिता भी साथ रहते हैं। अरुण के मुताबिक संबंधित महिला भी एक बच्चे की मां है। उन्होंने बताया कि भीम सिंह द्वारा इनकार किए जाने के बावजूद महिला लगातार दबाव बना रही थी, जिसके कारण वह पिछले करीब 10 दिनों से मानसिक तनाव में थे। पुलिस ने मामले के सभी पहलुओं को जांच में शामिल किया है।

महिला मजदूर ने की खुदकुशी

भंवरकुआं थाना क्षेत्र में 28 वर्षीय पूजा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पूजा मूल रूप से हरदा जिले की रहने वाली थीं। वह अपने पति सुखदेव के साथ इंदौर में मजदूरी करने आई थीं और आईटी पार्क के पास निर्माणाधीन भवन में काम कर रही थीं। शनिवार को परिजनों ने उन्हें फंदे पर लटका देखा, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है। कनाड़िया, छत्रीपुरा और भंवरकुआं थाना पुलिस अलग-अलग मामलों की जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि परिजनों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं और आत्महत्या के कारणों का पता लगाने के लिए सभी पहलुओं की पड़ताल की जा रही है।

युवक ने फांसी लगाई

छत्रीपुरा थाना क्षेत्र के सिलावटपुरा में रहने वाले 25 वर्षीय प्रियांशु राठौर ने शनिवार रात अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। प्रियांशु एक कपड़ों की दुकान पर काम करते थे। पुलिस के अनुसार देर रात उनकी मां ने उन्हें आवाज लगाई, लेकिन काफी देर तक कोई जवाब नहीं मिला। इसके बाद जब परिजन कमरे में पहुंचे तो वह फंदे पर लटके मिले। प्रियांशु के परिवार में माता-पिता और एक भाई हैं। बड़े पिता का परिवार भी उनके साथ ही रहता है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है।

हाई कोर्ट ने 14 साल की बेटी को पिता, बड़ी बहन के सुपुर्द किया

- मां के दबाव में लगाए थे आरोप, मैं पिता के साथ सुरक्षित

इंदौर। हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने पॉक्सो मामले में आरोपी एक पिता को उसकी 14 वर्षीय बेटी की कस्टडी वापस सौंपने का आदेश दिया। जस्टिस सुबोध अभ्यंकर और जस्टिस आलोक अवस्थी की खंडपीठ ने शेल्टर होम में रह रही 9वीं कक्षा की छात्रा की इच्छा, उसकी सुरक्षा और पढ़ाई को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय दिया। अदालत ने माना कि बच्ची अपने भविष्य को लेकर गंभीर है और वह आईआईटी की तैयारी करना चाहती है, इसलिए उसके सर्वोत्तम हित को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। पति-पत्नी के बीच वर्ष 2020 से पारिवारिक विवाद चल रहा था। इसके बाद वर्ष 2021 में मां ने पति के खिलाफ अपनी छोटी बेटी के यौन उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए पॉक्सो अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कराया। इस मामले में पिता को 51 दिन जेल में भी रहना पड़ा। बाद में वर्ष 2025 में जब मामले की सुनवाई चल रही थी, तब बेटी ने अदालत में लिखित रूप से कहा कि उसके पिता निर्दोष हैं। उसने यह भी बताया कि उसने मां के दबाव में आकर पिता के खिलाफ बयान दिए थे। इसी दौरान बच्ची को बाल संरक्षण समिति ने शेल्टर होम भेज दिया था। इसके विरोध में पिता और बड़ी बहन ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की।

बंद कमरे में सभी से बात

फैसला सुनाने से पहले हाई कोर्ट ने सभी संबंधित पक्षों से बंद कमरे में अलग-अलग बातचीत की। इस दौरान 14 साल की छात्रा ने स्पष्ट कहा कि उसके पिता ने कभी उसके साथ कोई गलत व्यवहार नहीं किया। उसने अदालत से कहा कि पिता उसकी पढ़ाई और हर जरूरत का पूरा ध्यान रखते हैं। वह उनके साथ पूरी तरह सुरक्षित महसूस करती है। छात्रा ने यह भी कहा कि वह आगे भी अपने पिता के साथ ही रहना चाहती है। पेशे से इंजीनियर बड़ी बहन ने भी अदालत के सामने कहा कि वैवाहिक विवाद के कारण मां ने छोटी बहन पर दबाव बनाकर पिता के खिलाफ झूठे बयान दिलवाए थे। उसने बताया कि पिता ने हमेशा दोनों बेटियों की देखभाल की और उनके पालन-पोषण में कोई कमी नहीं रखी।

इच्छा और भविष्य को प्राथमिकता

हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि दोनों बेटियां शिक्षित, समझदार और अपने भविष्य के प्रति जागरूक हैं। ऐसी स्थिति में नाबालिग की इच्छा और उसके सर्वोत्तम हित को महत्व दिया जाना चाहिए। अदालत ने इसी आधार पर शेल्टर होम से बच्ची को निकालकर उसकी कस्टडी पिता और बड़ी बहन को सौंपने का आदेश दिया। कस्टडी सौंपने के साथ हाई कोर्ट ने बच्ची की सुरक्षा के लिए विशेष निर्देश भी जारी किए। अदालत ने कहा कि छात्रा को एक मोबाइल फोन उपलब्ध कराया जाए, जिसमें स्थानीय थाना प्रभारी का नंबर पहले से सुरक्षित रखा जाए। यदि उसे किसी भी समय किसी प्रकार की परेशानी या असुरक्षा महसूस हो तो वह सीधे पुलिस से संपर्क कर सके।

मुझसे कोई आरोप नहीं लगवाए गए उन्हें फंसाया गया नाना केस में मोड़

- नाना पटवारी ड्रग केस में युवती के पुलिस के खिलाफ बयान

इंदौर। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के भाई नाना से जुड़े कथित ड्रग मामले में शनिवार को नया घटनाक्रम सामने आया। पहले चर्चा थी कि पुलिस को एक युवती ने बयान देकर नाना पर गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं अब वही युवती मीडिया के सामने आई और उसने इन सभी आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि नाना के खिलाफ झूठा माहौल बनाया जा रहा है।

राजस्थान के रहने वाली युवती ने बताया कि वह यहां अपनी बहन के साथ रहती है। शुक्रवार को राजेन्द्र नगर थाने से बयान देने के लिए फोन आया था। मैं अपने बयान दर्ज कर चुकी हूं। युवती ने मीडिया से बातचीत में कहा कि वह उसने नाना के खिलाफ कोई आरोप नहीं लगाए हैं। नाना अच्छे इंसान हैं और उनके बारे में जो बातें कही जा रही हैं, वे पूरी तरह गलत है।

ड्रग्स लेने की बात झूठी

युवती ने कहा कि नाना कभी ड्रग्स नहीं लेते। यहां तक की शराब भी नहीं पीते। युवतियों को ड्रग्स देते हैं या उन्हें इसकी लत लगाते हैं, यह बात पूरी तरह झूठी है। मैं नाना को 4-5 साल से जानती हूं, उन्हें फंसाने की कोशिश हो रही है। मेरी मुलाकात नाना से इंदौर में हुई थी। तबसे वह उन्हें व्यक्तिगत रूप से जानती है और उनके संपर्क में रही है। उसके अनुसार नाना का व्यवहार हमेशा अच्छा रहा है। उन पर लगाए जा रहे आरोप वास्तविकता से मेल नहीं खाते। उसे लगता है कि नाना को किसी साजिश के तहत फंसाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि जब उससे पूछा गया कि यह साजिश कौन कर रहा है तो उसने कहा कि उसे इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन संभव है कि राजनीतिक कारणों से ऐसा किया जा रहा हो।

जांच जारी रहने की बात

इधर, मामले की जांच कर रही क्राइम ब्रांच का कहना है कि पूरे प्रकरण की गंभीरता से जांच की जा रही है। एडिशनल डीसीपी (क्राइम) राजेश दंडोतिया ने बताया कि इस मामले में ड्रग्स के बड़े नेटवर्क से जुड़े होने की आशंका को भी ध्यान में रखते हुए जांच आगे बढ़ाई जा रही है। पुलिस सभी संबंधित लोगों से पूछताछ कर रही है, साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं और हर पहलू की बारीकी से जांच की जा रही है।

संपादकीय

नरोत्तम के बहाने संदेश

मध्यप्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में भाजपा द्वारा अपने दिग्गज नेता, पिछला विस चुनाव हारे तथा इस बार मंत्री पद की शपथ लेने का मंसूबा पाले डॉ. नरोत्तम मिश्रा को दरकिनार कर एक दूसरे ब्राह्मण और युवा नेता आशु तोष तिवारी को टिकट देकर न केवल नरोत्तम मिश्रा बल्कि पार्टी के उन तमाम साठ पार नेताओं को बड़ा संदेश दे दिया है कि वो अब बोरिया? बिस्तर बांधने की तैयारी कर लें। भाजपा में पिछले साल पीढ़ी परिवर्तन (दो शीर्ष नेताओं को छोड़कर) का जो सिलसिला शुरू हुआ था, वो अब उपचुनावों में प्रत्या?शी चयन में पल्लवित होता? दिखाई दे रहा है। हालांकि आशुतोष तिवारी को टिकट देने की खबर सुनकर दतिया में नरोत्तम समर्थकों ने 12 घंटे तक बवाल मचाया, हिंसा और आगजनी की, लेकिन पार्टी आला कमान के सख्त तेवरों के आगे उसकी सुदर्शन छवि की भी एक न चली। झक मारकर नरोत्तम को आशुतोष का समर्थन करने का ऐलान करना पड़ा। वैसे अंदरखाने नरोत्तम का टिकट कटवाने के पीछे मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की भूमिका पर सवाल उठ रहा है। क्योंकि ऐसा होने से जहां प्रदेश में एक और सत्ता केन्द्र उभरने की संभावना की भ्रूण हत्या हो गई और अगर भाजपा यह उपचुनाव हारी तो भीतरघात का संशय नरोत्तम पर ही जाएगा। यानी एक तीर से दो शिकार वाली स्थिति है। कुल मिलाकर हरदम चमकता चेहरा लेकर घूमने वाले नरोत्तम की राजनीति का यह दि एंड हो सकता है।

विडंबना यह है कि नरोत्तम किसी जमाने में खुद को राज्य का सबसे बड़े ब्राह्मण चेहरे के रूप में स्थापित करने में लगे थे। दरअसल नरोत्तम मिश्रा दतिया में आयातित नेता हैं। वो मूलतः ग्वालियर के हैं और शुरू में डबरा विधानसभा सीट से जीतते रहे हैं। परिसीमन में जब डबरा सीट आरक्षित हो गई तो नरोत्तम दतिया इसलिए चले आए, क्योंकि यह अनारक्षित होने के साथ-साथ यहां ब्राह्मण वोटरों की संख्या काफी है। धीरे-धीरे नरोत्तम ने यहां अपनी सल्तनत कायम कर ली। उसी अनुपात में वो लोगों के बीच अलोकप्रिय भी होते गए। नतीजा यह हुआ कि 2023 में जब पूरे प्रदेश में भाजपा की लहर चल रही थी, नरोत्तम पौने 8 हजार वोटों से अपनी सीट कांग्रेस के राजेन्द्र भारती के हाथों गवां बैठे।

नरोत्तम का ?टकट क्यों कटा, इसको लेकर कई तरह की थ्योरियां हैं। पहला तो यह कि पार्टी की राज्य इकाई ने नरोत्तम के इसरार पर उपचुनाव के लिए एक ही नाम आला कमान को भेजा था, लेकिन आला कमान ने अपने स्तर पर अलग से फीड बैक लिया और पाया कि नरोत्तम पे दांव लगाना जोखिम भरा है। अर्थात उनके प्रति आम जनता में नाराजी अभी भी कम नहीं हुई है। मप्र में इस वक्त जिन नेताओं के हाथ में कमान है, उनमें कतिपय अपवाद को छोड़ दें तो ज्यादातर साठ के आसपास या उससे कम उम्र के ही हैं। सत्तर की ?टच लाइन को छूने या पार करने वालों के लिए साफ संदेश है कि वो नए लोगों के लिए सिंहासन खाली करें, मुख्यमंत्री पद की ख्वाहिश पालना तो बहुत दूर की बात है। ऐसे लोग चाहिए जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष 45 वर्षीय नितिन नबीन को बेझिझक 'सर' कह सकें। लेकिन तीन दशकों से राजनीति में रचे पगे नरोत्तम के लिए 'रिटायरमेंट' की जिंदगी जीना मुश्किल है। जिस तरह उनके समर्थकों ने दतिया में बवाल काटा, उसके बाद संगठन में उनके पुनर्वास की संभावना पर भी पत्थर पड़ गए हैं। दूसरे, अपने पुत्र को राजनीति में आगे बढ़ाने की योजना का रायता भी फैलता दिख रहा है। अब देखना यह है कि बात कितनी दूर तलक जाती है।

नजरिया

रघु ठाकुर

लेखक समाजवादी विचारक हैं।

दुर्घटनाओं के लिये शासन जिम्मेदार

जून 2026 दिल्ली के मालवीय नगर इलाके के एक होटल में आगजनी की घटना में लगभग 21 लोगों के मरने की खबर है। इनमें विदेशी नागरिक भी थे जो इलाज के लिये साकेत के मेक्स हॉस्पिटल में आये थे तथा अग्निकांड के शिकार हो गये। एक श्री राधेश्याम अग्रवाल जो मैक्स में इलाज के लिए भर्ती थे उनके परिजन उनको देखने आये थे, उनमें से 8 लोगों की जलकर मौत हो गई। जैसा होता है कि सरकार ने जांच कमेटी बनाई, जांच होगी, कुछ सिफारिशें होंगी और फिर अतीत की पुनरूवृत्ति होगी। ऐसा प्रतीत होता है कि जब तक मीडिया किसी खबर को जिंदा रखता है तब तक वह खबर जिंदा रहती है और मीडिया के मुख्य पृष्ठों से ओझल होने के बाद जनता उसे भूल जाती है। आम जनता का स्मृति दोष क्यों है यह यक्ष प्रश्न है। जिसका कोई उत्तर अभी तक मुझे नहीं मिला है। आजादी के पहले जब जलियावाला कांड हुआ था और ब्रिटिश जनरल डायर ने जलियावाला बाग में निर्दोष लोगों को गोली से मरवाया था तब वह समाचार मीडिया में कुछ दिन रहा परंतु मीडिया के मुख्य पृष्ठों से हटने के बाद भी देश के लोगों के दिलों-दिमाग पर गहरा असर रहा, जिसके चलते शहीद ऊधम सिंह ने लंदन में जाकर उस घटना का बदला लिया था। इसी प्रकार साइमन कमीशन का विरोध करते हुए लाला लाजपतराय पर लाठियाँ पड़ी व वह मौत के शिकार हुए, उनकी मौत को देश ने याद रखा और शहीद भगत सिंह ने उसका प्रतिशोध लिया। निसंदेह यह घटनायें आजादी के आंदोलन की थी। इसलिये इनका अलग महत्व व भाव है। मैं उनकी तुलना नहीं कर रहा हूँ, न करना चाहता हूँ, मैं तो इन कारणों को खोजना चाहता हूँ कि ऐसी कितनी घटनायें देश में हुई हैं और जिन्हें अलग काल में देश ने भुला दिया। देश की पटाखा कंपनियों में आग लगने से पिछले डेढ़-दो दशक में मरने वालों की संख्या 100 से अधिक है। मप्र के धार में, हरदा में और हाल ही में देवास में पटाखा कंपनियों में घटना घटित हुई और बड़ी संख्या में लोग मारे गये। इसी प्रकार कुछ दिनों पूर्व तमिलनाडु के शिवकाशी में जो देश का पटाखा बनाने का सबसे बड़ा केंद्र है, में विस्फोट हुआ था जिसमें अनेक लोग मारे गये थे। इसी प्रकार अस्पतालों में, होटलों में, सार्वजनिक स्थलों पर आग लगने की बड़ी-बड़ी घटनायें पिछले दिनों मीडिया की प्रमुख खबरों में रही और कुछ दिनों बाद जन स्मृति में विलुप्त हो गई।

मैं मानता हूँ कि ये घटनायें सत्ता या व्यवस्था के प्रतिरोध में नहीं हुई हैं, परंतु ये घटनायें व्यवस्था की असफलता, और कुशासन और भ्रष्टाचार के परिणाम हैं। मालवीय नगर की घटना में दिल्ली नगर निगम ने होटल के मालिक श्री लवकेश बजाज को मात्र 6 कमरों को बनाने की अनुमति दी थी, परंतु यह 25 कमरे कैसे बन गये। दिल्ली का नगर निगम सरकार, दिल्ली सरकार का प्रशासन क्या इससे अनजान थे। जहां तक मैं समझता हूँ कि निगम से लेकर सरकार तक को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष जानकारियां रहती हैं, इसका प्रमाण इस बात से मिलता है कि होटल में आग लगने की सूचना के बाद श्री लवकेश बजाज वहां से निकले, वे रूके भी नहीं। बाद में मीडिया को बयान देते हुए कहा कि मैं रूका नहीं क्योंकि मैं डर गया था। उन्होंने यह भी कहा कि दिल्ली में यह सब चलता है। वह एक पंक्ति दिल्ली और देश की व्यवस्था को नंगा कर देती है। एक नागरिक के मन में यह आमधारणा है कि हमें धन कमाना है और उसके लिये नियमों के पालन की कोई जरूरत नहीं है, नियम तो केवल कागज पर लिखने के लिये होते हैं। बकाया व्यवस्था व कामकाज तो रिश्वत से चलते हैं। कुछ दिनों पूर्व दिल्ली में ही, कई जर्जर मकान गिरे जिनमें अनेकों मौतें हुई। यह कानून है कि जो मकान जर्जर है, निगम को मकान मालिक को नोटिस देना चाहिए कि वह इसे गिराये और यदि वह नहीं गिराते हैं तो निगम को उसे गिराने का अधिकार दिया गया है। परंतु इतने भवनों के गिरने व मौतों के बाद किसी भी राजनैतिक सत्ताधीश की कोई जिम्मेदारी तय नहीं की गई कि इन जर्जर मकानों की पहचान क्यों नहीं की गई, इन्हें गिराया क्यों नहीं गया और इसके पीछे किन अधिकारियों, राजनेता का आदेश या सिफारिश थी, किसी को भी जिम्मेवार नहीं ठहराया गया। आज भी दिल्ली में हजारों ऐसे मकान हैं जो जर्जर हैं, छोड़ देने के योग्य हैं, परंतु नीचे से लेकर ऊपर तक भ्रष्टाचार हर अपराध का संरक्षक बन गया है। यह स्थिति अकेले दिल्ली की नहीं है बल्कि देश के मेट्रोपोलिटिन सिटी और महानगरों लगभग हर नगर की है। बम्बई में पुरानी चालों के गिरने की खबर आई हैं जिनमें लोगों की मौत हुई है। यह नियम है कि निश्चित अवधि के बाद पुराने भवनों का या तो जिर्णोद्धार या पुनरू निर्माण होना चाहिये। श्री लवकेश बजाज ने बता दिया है कि दिल्ली में यह सब चलता है इसमें अंतरनिहित है कि देश में सब चलता है।

दिल्ली के मालवीय नगर की घटना ने जो समाचार अखबारों में आये थे, उनमें बताया गया था कि अग्नि शामक यंत्र तो थे ही नहीं, निकलने का रास्ता भी नहीं था। यहां तक कि छतों के दरवाजे बंद थे, कोई केन्टीन नहीं थी और कमरों में ही खाना पकाने के हीटर आदि रख दिये गये थे। लवकेश बजाज ने यह भी कहा था कि हमने 6 कमरों से बढ़ाकर 25 इसलिये किये थे क्योंकि अच्छा मुनाफा मिल रहा था। उसे अपनी गलती पर कोई पश्चाताप नहीं था। एक मरीज राधेश्याम अग्रवाल जो मैक्स में भर्ती थे, उनके स्वास्थ्य की जानकारी लेने के लिये उनके परिवार के आठ लोग आये थे और वह आठों मौत के शिकार हो गये। इस दुख में बेटा, बेटी, बहू उनके बेटे-बच्चे, उनकी पत्नी, जब सब जलकर खत्म हो गये तो उनकी खुद की भी मौत हो गई, क्योंकि वह इस दुख को बर्दाश्त नहीं कर सके। आग लगने की जानकारी मिलते ही आसपास के मुस्लिम भाईयों और नौजवानों ने जिस साहस व मानवता का परिचय दिया वह भुलाया नहीं जा सकता। जिन मुस्लिम भाईयों की दुकानें आसपास थीं उनमें कुछ टेंट वाले भी थे, उन्होंने अपनी दुकानों के सारे गद्दे नीचे सड़क पर बिछा दिये ताकि होटल में आग से घिरे लोग अपनी जान बचा सकें। एक मुस्लिम भाई ने तो जलती सलाकों के बीच उन्हें तोड़कर लोगों को बचाया। अनेक मुस्लिम नौजवानों ने आग से बेहोश और मृत्यु की ओर जा रहे घायलों को कृत्रिम सांस देकर बचाया। दिल्ली पुलिस के जवानों की प्रशंसा करना पड़ेगी कि उन्होंने भी अनेक लोगों की जान बचाई, इन्हें कृत्रिम सांस दी और आग से निकाला।

देश के हिंदु संगठनों और आरएसएस के मुखियाओं को अवश्य इस पर विचार करना चाहिये कि जब मालवीय नगर में यह मानवीय संकट आया तो मुसलमानों ने हिंदू की रक्षा की और श्री लवकेश बजाज कार में बैठकर सामने से यह कहते हुए निकल गए कि मैं डर गया था। मैं ना सारे हिंदूओं को दोष देता हूँ और न सारे मुसलमान भाईयों की प्रशंसा कर रहा हूं। मेरा कहना यही है कि हर धर्म में अच्छे व बुरे लोग होते हैं इसलिये किसी कौम को संपूर्ण रूप से बुरा नहीं कहना चाहिये। मानव के प्रति आस्था और विश्वास किया जाना चाहिये। अगर सारे हिंदु अच्छे होते तो क्या श्री लवकेश बजाज अपने अपराधों के चलते होटल में जल रहे लोगों को देखता हुआ कार से चला जाता, जलकर मरने वालों में अधिकांश हिंदु ही हैं। यह भी श्री बजाज जानते होंगे कि उनकी होटल में ठहरने वाले कौन लोग हैं, उनके होटल के मैनेजर भी हिंदु ही थे और उन्होंने भी इतनी भयाभय घटना के बाद इंसानों को बचाने के लिये कुछ नहीं किया।

इस कांड को लेकर राजनैतिक आरोप प्रत्यारोप शुरू हुए हैं कि होटल की अनुमति किसने दी, कौन गुनाहगार हैं, अब इन बातों से क्या होने वाला है। गुनाहगार परमीशन देने वाला नहीं है बल्कि बगैर परमीशन के 19 अतिरिक्त बनाने देने की अघोषित परमीशन देने वाले असली अपराधी हैं। पुलिस ने श्री लवकेश बजाज के खिलाफनिरूद्देश्य हत्या का मामला दर्ज किया है और बजाज ने सार्वजनिक बयान दिया है कि मैं होटल का मालिक हूँ, सारा होटल का कामकाज, प्रबंधन, निर्माण, कोई जय मिश्रा बतौर प्रबंधक देखते थे, याने कानून के पंजों से हो सकता है कि श्री बजाज भी बच जायें। आखिर इन 21 मौतों का जो एक अर्थ में क्रूर हत्यायें हैं, का जिम्मेदार कौन है? यह भी तय होना चाहिये कि न्यायपालिका में यह मुकदमा सुनवाई के लिये गया है और मैं न्यायपालिका से अनुरोध करूंगा कि

1. इन होटल के कमरों के निर्माण के समय जो भी जिम्मेवार अधिकार रहे हैं उन्हें भी अपराधी बनाया जाना चाहिये।

2. एक व्यक्ति 6 कमरों की अनुमति लेकर 25 कमरे बनवाता है तो इन मौतों के लिये जो हत्यारों के समान है वह निरूद्देश्य हत्या नहीं माना जा सकता बल्कि उसे उद्देश्यपूर्ण हत्या माना जाना चाहिये तथा न्यायपालिका को यह आदेश देश में घटी सभी दुर्घटनाओं, व आग लगने की, मकान गिरने, कारों से कुचले जाने की हों, पर लागू करने का आदेश देना चाहिए।

3. भारत सरकार को भारतीय न्याय संहिता में संशोधन करना चाहिये और ऐसी घटनाओं के जिम्मेवार व्यक्ति के प्रति सउद्देश्य अपराध माने जाने का कानून बनाना चाहिये।

4. जिन दुकानदारों, नौजवानों, या पुलिसवालों ने जान पर खेलकर लोगों को बचाने का प्रयास किया है उन्हें भारत सरकार को वीरता पुरुस्कार से सम्मानित और उनकी यथा संभव मदद करना चाहिये।

मोहम्मद शाहिल ने सीना दबाकर यानि सीपीआर देकर कई लोगों की जान बचाई। इसरार खान, वसीम राजा, मुस्तकीम, शिवानी उनके भाई सत्यम, पुलिस के जवान दिनेश राजा, राजवीर और करतार ने भी अपनी जान पर खेलकर यथारू संभव लोगों को बचाने का काम किया। ये सभी लोग वास्तव में मानवता के दूत हैं, मैं इनका हृदय से अभिनंदन करता हूँ।

दिल्ली की ईवी नीति

अरुण कुमार डनायक

लेखक समाजसेवी हैं।

क्या स्वच्छ हवा की राह इलेक्ट्रिक होगी?

सर्दियों में धीमी हवाओं और तापमान उलटाव से जहरीली हवा फँस जाती है। वाहनों का दबाव, निर्माण व औद्योगिक धूल, पराली जलाने का धुआँ और कचरा/बायोमास दहन प्रदूषण को और गहरा करते हैं। आसपास के कोयला आधारित बिजलीघर और मथुरा रिफायनरी से निकलने वाले सल्फर डाइऑक्साइड व नाइट्रोजन ऑक्साइड भी वायु गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं। इन सबके संयुक्त प्रभाव से सार्वजनिक स्वास्थ्य पर गंभीर संकट खड़ा होता है और सरकारों के सामने ऊर्जा संक्रमण, क्षेत्रीय सहयोग तथा शहरी परिवहन सुधार जैसी चुनौतियाँ उपस्थित होती हैं। इन परिस्थितियों के बीच दिल्ली सरकार द्वारा अधिसूचित नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति-2026 केवल परिवहन नीति नहीं, बल्कि पर्यावरण संरक्षण और ऊर्जा संक्रमण की दिशा में एक महत्वाकांक्षी पहल के रूप में सामने आई है।

लगभग डेढ़ दशक पहले बीजिंग दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में था। तब शायद ही किसी ने सोचा होगा कि वही शहर आज इलेक्ट्रिक मोबिलिटी का वैश्विक उदाहरण बन जाएगा। चीन सरकार ने शहरी परिवहन में इलेक्ट्रिक बसों व टैक्सियों का बड़े पैमाने पर बढ़ावा दिया । इससे वायु गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार हुआ, हालाँकि प्रदूषण पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ। दिल्ली आज बहुस्तरीय प्रदूषण संकट से जूझ रही है। सर्दियों में धीमी हवाओं और तापमान उलटाव से जहरीली हवा फँस जाती है। वाहनों का दबाव, निर्माण व औद्योगिक धूल, पराली जलाने का धुआँ और कचरा/बायोमास दहन प्रदूषण को और गहरा करते हैं। आसपास के कोयला आधारित बिजलीघर और मथुरा रिफायनरी से निकलने वाले सल्फर डाइऑक्साइड व नाइट्रोजन ऑक्साइड भी वायु गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं। इन सबके संयुक्त प्रभाव से सार्वजनिक स्वास्थ्य पर गंभीर संकट खड़ा होता है और सरकारों के सामने ऊर्जा संक्रमण, क्षेत्रीय सहयोग तथा शहरी परिवहन सुधार जैसी चुनौतियाँ उपस्थित होती हैं। इन परिस्थितियों के बीच दिल्ली सरकार द्वारा अधिसूचित नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति-2026 केवल परिवहन नीति नहीं, बल्कि पर्यावरण संरक्षण और ऊर्जा संक्रमण की दिशा में एक महत्वाकांक्षी पहल के रूप में सामने आई है।

भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों की यात्रा केवल राज्यों की पहल तक सीमित नहीं रही। केंद्र सरकार ने 2015 में फेम इंडिया योजना शुरू की, जिसे बाद में फेम-द्वितीय के रूप में विस्तारित किया गया।अनुदान, बैटरी निर्माण, चार्जिंग अवसंरचना तथा पीएम ई-ड्राइव जैसी पहलों के माध्यम से केंद्र सरकार ने केवल वाहन खरीद ही नहीं बल्कि पूरे ईवी पारितंत्र को विकसित करने का प्रयास किया है।

राष्ट्रीय प्रयासों के समानांतर अनेक राज्यों ने अपनी-अपनी इलेक्ट्रिक वाहन नीतियाँ बनाई हैं। दिल्ली के साथ, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना, केरल, हरियाणा और मध्य प्रदेश सहित कई राज्यों ने ऐसी नीतियाँ लागू कीं, जिससे जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता घटे, प्रदूषण कम हो और हरित अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन मिले। दिल्ली ने वर्ष 2020 में देश की सबसे प्रगतिशील इलेक्ट्रिक वाहन नीतियों में से एक लागू की थी, जिसका आधार प्रोत्साहन था। खरीद पर सब्सिडी, सड़क कर एवं पंजीकरण शुल्क में छूट, चार्जिंग स्टेशनों का विस्तार और जन-जागरूकता अभियानों के माध्यम से लोगों को स्वेच्छा से इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने के लिए प्रेरित किया गया। इसका सकारात्मक परिणाम यह हुआ कि दिल्ली देश के सबसे तेज़ी से बढ़ते इलेक्ट्रिक वाहन बाज़ारों में शामिल हो गई, विशेषकर दोपहिया वाहनों और ई-रिक्शा के क्षेत्र में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई। वर्ष 2026 की नई नीति इसी यात्रा का अगला चरण है। यदि 2020 की नीति को 'प्रोत्साहन आधारित नीति' कहा जाए, तो 2026 की नीति 'समयबद्ध परिवर्तन आधारित नीति' है। अब सरकार केवल रियायतें देकर लोगों की स्वैच्छिक भागीदारी पर निर्भर नहीं रहना चाहती, बल्कि स्पष्ट समय-सीमा निर्धारित कर चरणबद्ध रूप से पेट्रोल और सीएनजी वाहनों से इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर संक्रमण सुनिश्चित करना चाहती है। इसी उद्देश्य से 1 जनवरी 2027 से केवल इलेक्ट्रिक ऑटो-रिक्शा तथा 1 अप्रैल 2028 से केवल इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों के नए पंजीकरण का प्रावधान किया गया है। यही गुणात्मक परिवर्तन नई नीति को 2020 की नीति से अधिक साहसिक, स्पष्ट और दूरगामी बनाता है।

यद्यपि नई नीति में इलेक्ट्रिक कारों की खरीद पर भी कर एवं पंजीकरण शुल्क में छूट सहित विभिन्न प्रोत्साहनों का प्रावधान है, फिर भी सरकार का मुख्य जोर दोपहिया वाहनों के विद्युतीकरण पर है, क्योंकि दिल्ली के लगभग दो-तिहाई पंजीकृत वाहन इसी श्रेणी के हैं। इनके विद्युतीकरण से वायु प्रदूषण, ईंधन खपत और कार्बन उत्सर्जन में सबसे अधिक कमी लाई जा सकती है। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी केवल पर्यावरणीय परियोजना नहीं, बल्कि औद्योगिक नीति भी है। बैटरी निर्माण, सॉफ्टवेयर, चार्जिंग नेटवर्क, बिजली वितरण, ऑटोमोबाइल विनिर्माण और सेवा क्षेत्र में लाखों नए रोजगार सृजित हो सकते हैं। यदि भारत इस क्षेत्र में समय रहते निवेश करता है तो वह वैश्विक ईवी आपूर्ति श्रृंखला का महत्वपूर्ण हिस्सा बन सकता है।

परंतु किसी भी नीति की सफलता केवल उसकी घोषणा से नहीं, बल्कि उसके क्रियान्वयन से तय होती है। दिल्ली की नई नीति के सामने अनेक चुनौतियाँ भी हैं। भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों की सबसे बड़ी चुनौती चार्जिंग अवसंरचना है—लाखों नए ईवी सड़कों पर आने वाले हैं, जबकि मौजूदा नेटवर्क अभी भी अपर्याप्त है। दूसरी चुनौती बिजली वितरण व्यवस्था की है, जिसे बढ़ती मांग के अनुरूप सुदृढ़ करना होगा। तीसरी चुनौती बैटरी आपूर्ति श्रृंखला की है, क्योंकि भारत लिथियम और अन्य महत्त्वपूर्ण खनिजों के लिए चीन जैसे देशों पर निर्भर है; यदि संबंधों में खटास आती है तो आपूर्ति प्रभावित हो सकती है। इसलिए भारत को लिथियम, कोबाल्ट तथा दुर्लभ खनिजों के वैकल्पिक स्रोत विकसित करना भी उतना ही आवश्यक है । चौथी चुनौती बैटरी रीसाइक्लिंग की है, अन्यथा प्रदूषण का नया स्रोत पैदा होगा। उपभोक्ताओं के लिए इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों की दूरी भी अहम प्रश्न है—हालाँकि शुरुआती मॉडलों की सीमा 50 किमी थी, आज अधिकांश स्कूटर 120ङ्क160 किमी तक चल सकते हैं, जो दिल्ली जैसे महानगर में दैनिक यात्रा के लिए पर्याप्त है। इसके बावजूद कीमत, सर्विस नेटवर्क, प्रशिक्षित तकनीशियन और उपभोक्ता विश्वास जैसी व्यावहारिक चुनौतियाँ बनी हुई हैं। साथ ही, जब तक बिजली उत्पादन नवाचारी स्रोतों से नहीं बढ़ेगा, ईवी का पर्यावरणीय लाभ सीमित रहेगा।

यह भी ध्यान रखना होगा कि दिल्ली का वायु प्रदूषण केवल वाहनों से नहीं होता। पराली जलाना, निर्माण कार्यों से उठने वाली धूल, औद्योगिक गतिविधियाँ तथा पड़ोसी राज्यों से आने वाले प्रदूषक भी इसमें बड़ी भूमिका निभाते हैं। इसलिए केवल इलेक्ट्रिक वाहन नीति से समस्या का पूर्ण समाधान नहीं होगा। इसे सार्वजनिक परिवहन के विस्तार, मेट्रो, बसों, साइकिल मार्गों, हरित ऊर्जा और समग्र वायु गुणवत्ता प्रबंधन के साथ जोड़कर ही अपेक्षित परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। नीति की सफलता के लिए सख्त प्रशासनिक निगरानी आवश्यक है, क्योंकि निचले स्तर की लापरवाही, भ्रष्टाचार और उच्चाधिकारियों की अनदेखी अक्सर क्रियान्वयन को कमजोर कर देती है।

फिर भी यह स्वीकार करना होगा कि दिल्ली की नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति भारत में हरित परिवहन की दिशा में एक साहसिक और दूरदर्शी कदम है। यदि बीजिंग अपने कठिन अनुभवों से सीख लेकर प्रदूषण नियंत्रण की दिशा में आगे बढ़ सकता है, तो दिल्ली भी सुविचारित नीतियों, मजबूत आधारभूत ढाँचे और प्रभावी क्रियान्वयन के माध्यम से स्वच्छ परिवहन की नई मिसाल बन सकती है। यह नीति केवल वाहनों को बदलने की योजना नहीं है; यह ऊर्जा, पर्यावरण और शहरी जीवन शैली के व्यापक परिवर्तन का आरंभ है। इसकी सफलता अंततः इस बात पर निर्भर करेगी कि सरकार, उद्योग और नागरिक—तीनों इस परिवर्तन को कितनी गंभीरता से स्वीकार करते हैं।

स्वामी, सुबह सवेरे मीडिया एल.एल.पी. के लिए उमेश त्रिवेदी द्वारा पंकज प्रिंटर्स एंड पैकेजिंग, 16, अल्फा इंडस्ट्रीयल पार्क, जाखिया, इंदौर, म.प्र.-453555 से मुद्रित एवं 662, साई कृपा कॉलोनी, बॉम्बे हॉस्पिटल के सामने, इंदौर से प्रकाशित।

प्रधान संपादक
उमेश त्रिवेदी
कार्यकारी प्रधान संपादक
अजय बोकिल
संपादक (मध्यप्रदेश)
विनोद तिवारी
स्थानीय संपादक
हेमंत पाल
प्रबंध संपादक
रमेश रंजन त्रिपाठी

(सभी विवादों का न्याय क्षेत्र इंदौर रहेगा)
RNI No. MPHIN/ 2015/ 66040,
Mobile No.: 09893032101
Email- subahsaverenews@gmail.com

'सुबह सवेरे' में प्रकाशित विचार लेखकों के निजी मत हैं। इनसे समाचार पत्र का सहमत होना आवश्यक नहीं है।

दृष्टिकोण

सीमा देवेन्द्र

लेखक साहित्यकार हैं।

बचपन की बारिश यानी अनुभव की पहली सीढ़ी

बरसती रही रात-भर जो वो बारिश
अक्सर सुबह को बन्द हो जाया करती !
बचपन की स्मृतियाँ कभी भुलाई नही जा सकती और ना ही कभी वो मद्धिम पड़ती है । जैसे जैसे उम्र बढ़ती है , बचपन उतना ज्यादा याद आता है और फिर एक समय आता है जब उम्र का ग्राफ गिरकर बचपन के ही माफिक हो जाता है । बचपन की समयावधि भले कम हो लेकिन केवल बचपन की अवधि का आंकलन किया जाय तो इसमें सबसे ज्यादा हिस्सा विद्यालयीन ही होता है । इसलिए उस दौर की स्मृतियाँ स्थायी रह जाती है समय परिस्थितियाँ या कहें मौसम कोई भी हो । हमारी रूचि , हमारा बर्ताव , हमारे आसपास के लोग एवं पृकृति उस दौरान जैसी भी थी आज याद बनकर हमारे सामने आ जाती है और जब हमें फिर उस जैसा माहौल महसूस होता है तब कहीं न कहीं फिर से वो चिर-स्मृतियाँ हमारे मस्तिष्क पटल पर पुनः जीवित हो उठती है ।

आज बात करें बचपन में जुलाई की बरसात पर तो सबसे ज्यादा बरसात और स्कूल का नाता ही सामने उभरकर आता है , भीगी गलियाँ , भीगा बस्ता जिसमें से किताब कॉपी की भीगी महक आती थी । नई नई पुस्तकों की गंध इतनी अच्छी लगती कि बार बार पुस्तकों को खोलकर उसे सूंघना और टीचर समझते बच्चे पढ़ रहे हैं । पुस्तकों में विद्या रखना उसमें मोर पंख रखना ।

नया शैक्षणिक सत्र नए संकल्पों को चुनौती देता है । अतः जुलाई की बरसात हर संभव यादगार ही होती है । पूरे वर्ष की पढ़ाई का पहला पन्ना होता है जुलाई और बादल भी इसी माह में अधिक मंडराते हैं इसलिए संतुलन बनाना भी अतिआवश्यक होता था । बचपन की सहज अनुभूति को याद करें तो जुलाई हमें अतीत से जोड़ती है और याद दिलाती है वो बरसाती अनुभव जो बरसते पानी में किस तरह दौड़ते भागते स्कूल जाना होता वो भी प्रार्थना की घंटी के पहले । आधे गीले और आधे सूखे कक्षामें बैठकर जीवन के उन अध्यायों को बाँचना और सलीके से लिखना होता जिनके होमवर्क पिताजी अपनी निगरानी में करवाते थे । इतनी सख्ती के बाद भी बालमन अपनी शैतानी से नही चूकता । पानी के डबरों में छप्पकछई करते करते काग़ज की नाव चलाते हुए भीगते भागते घर पहुँचते । फिर आँगन में फुदकती पीली चीड़िया से भी दो टूक बात करनी होती , उनकी शादी हुई के नही ? क्योंकि मैं दादी से पूछती थी चिड़या पीली क्यों हो जाती है इस समय ? दादी बोलती इस समय इनकी शादी होती है ।

बरसात और बचपन को देखें तो इतनी मस्ती किसी मौसम में नही होती क्योंकि शायद बच्चों के लिए भी बरसात ही बनी है , बाक़ी मौसम तो बचपन को बड़ा कर देते हैं । एक बरसात ही है जो बचपन , यौवन और जीवन के उत्तरार्द्ध में भेद करती है ।

कभी-कभी ऐसा होता कि आज की बारीश घर में ही मनायी जाए , पापा के ऑफिस जाने के बाद घर के आँगन में भीगकर धींगामस्ती करेंगे आसपास के दोस्त मित्रों के साथ और पापा से तेज बारिश के नाम पर छुट्टी की एप्लीकेशन लिखवा लेते हैं लेकिन ये सपना तब टूट जाता जब पापा सुबह उठाते हैं.. बेटा बारिश बन्द हो गई है तैयार हो जाओ भैया स्कूल छोड़ आएंगे ।

वो बचपन की बरसात रेनकोट , छाता , आधे भीगे बस्ते का याद आना और भीगी यूनिफार्म का ना सूखना जिसके बहाने टीचर के सामने कमजोर पड़ जाते क्योंकि वो तो एक और होती थी ।

याद आते हैं वो लम्हें जिन्हे हमने ही महसूस किए हैं और शायद ये बने भी हमसे ही हैं क्योंकि आजकल के बच्चों को भीगने का ज़रा अनुभव नहीं ।

इतनी सर्वसुविधायुक्त वातावरण में जो बच्चे पढ़ रहे हैं । लेकिन याद रखिए इनके पास आगे जाकर अपने बचपन के और उस जुलाई वाली बरसात के वो अनुभव नही होगें जो आज हम सबको और अपने आपको बीते लम्हे सुनाकर उस बचपन में लौट जाते हैं थोड़ी देर के लिए।

बरसात बचपन की हो या किसी और उम्र की , वह जीवन का उजला अध्याय होती है ।

भीगने की भी सीमा तय थी इतने भीगे कभी नही बादल भी तब खूब बरसते इतने बरसे कभी नही !

हर मौसम जीवन में कुछ न कुछ सिखाता है क्योंकि जीवन प्रकृति के वशीभूत है और जीवन में मिली हर सीख संस्कृति के विकास में सहायक है जिसकी प्रथम सीढ़ी है बचपन की बारिश।

न्याय और कानून

समान नागरिक संहिता-2

विनय झैलावत

(पूर्व असिस्टेंट सॉलीसीटर जनरल एवं वरिष्ठ अधिवक्ता)

निजी कानून सामाजिक मूल्यों के अनुरूप बनाने का मौका

व्यक्तिगत कानून संविधान की समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं, जिसके तहत राज्य और केंद्र दोनों सरकारों को उन पर कानून बनाने का अधिकार है। आलोचकों का मानना है कि केंद्र द्वारा अधिरोपित समान नागरिक संहिता राज्य स्वायत्तता को कमजोर कर सकती है। हाल ही में उत्तराखंड में राज्य की स्वयं की पहल के रूप में युसीसी का कार्यान्वयन सवाल खड़े करता है कि राष्ट्रीय समान नागरिक संहिता राज्य विशिष्ट कानूनों एवं रीति रिवाजों के साथ किस प्रकार तालमेल स्थापित करेगी। इस कानून के कार्यान्वयन के लिये कानूनी प्रणाली में बड़े पैमाने पर सुधार की आवश्यकता है। इसके लिए संभावित रूप से महत्वपूर्ण लागतें उठानी पड़ेंगी।

समान नागरिक संहिता सभी समुदायों में पुरानी प्रथाओं में व्यक्तिगतकानूनों को समकालीन सामाजिक मूल्यों के अनुरूप बनाने का एक अवसर है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समलैंगिक संबंधों को वैध बनाना आधुनिक व्यक्तिगत कानूनों की आवश्यकता को उजागर करता है। समान नागरिक संहिता संभावित रूप से विवाह, दत्तक ग्रहण और उत्तराधिकार जैसे मामलों में इन अधिकारों जैसे मुद्दों को संबोधित कर सकती है। इन्हें वर्तमान मेंविभिन्न व्यक्तिगत कानूनों के तहत समान रूप से मान्यता नहीं दी गई है। विविध जनसंख्या वाले कई देशों ने एकीकृत नागरिक संहिताओं को सफलतापूर्वक लागू किया है। वर्ष 1926 में तुर्की द्वारा धर्मनिरपेक्ष नागरिक संहिता का अंगीकरण इसका एक प्रमुख उदाहरण है। समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के अंगीकरण से भारत अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार मानकों के अनुरूप बन सकता है। इससे वैश्विक सूचकांकों (जैसे ग्लोबल जेंडर गैप सूचकांक) पर इसकी स्थिति में सुधार हो सकता है, जहां वह वर्तमान में 146 देशों के बीच 129वें स्थान पर है।

समान नागरिक संहिता के विरूद्ध जो तर्क दिए जाते हैं, उनमें सांस्कृतिक संरक्षण, भारत की विविध विरासत की रक्षा शामिल है। भारत का बहुलवादी समाज सांस्कृतिक एवं धार्मिक प्रथाओं के समृद्ध मिश्रण से चिन्हित होता है। इनमें से कई व्यक्तिगत कानूनों के तहत संरक्षित हैं। यह प्रश्न भी है कि क्या समान नागरिक संहिता इस विविधता को नष्ट कर सकती है और सांस्कृतिक एकरूपता की ओर ले जा सकती है। उदाहरण के लिए, खासी जनजाति की अद्वितीय मातृवंशीय उत्तराधिकार प्रणाली खतरे में पड़ सकती है। समान नागरिक संहिता के विरोधियों का तर्क है कि यह संविधान के अनुच्छेद 25 द्वारा गारंटीकृत धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन कर सकता है। उनका तर्क यह है कि व्यक्तिगत कानून कई समुदायों के लिये धार्मिक आचरण का अभिन्न अंग हैं। प्यू रिसर्च सेंटर के सन 2021 के एक सर्वेक्षण में पाया गया कि 84त्न भारतीय अपने जीवन में धर्म को अत्यंत महत्वपूर्ण मानते हैं। धर्म से प्रभावित व्यक्तिगत कानूनों में किसी बदलाव को संभावित प्रतिरोध का सामना करना पड़ सकता है।

ऐसी चिंताऐं व्यक्त की गई हैं कि समान नागरिक संहिता अल्पसंख्यक समुदायों को असंगत रूप से प्रभावित कर सकती है। इससे उनमें संभावित रूप से हाशिये पर धकेले जाने की संभावना पैदा हो सकती है। आलोचकों ने उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता के कार्यान्वयन की ओर ध्यान दिलाया है, जिसे अल्पसंख्यक समूहों के विरोध का सामना करना पड़ा। उनका कहना था कि इसमें उनकी परंपराओं पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है। भारत की अल्पसंख्यक आबादी को भय है कि समान नागरिक संहिता बहुसंख्यक प्रथाओं से अधिक प्रभावित हो सकती है। इससे उनकी अपनी सांस्कृतिक पहचान कमजोर हो सकती है। आलोचकों का तर्क है कि भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में सभी समुदायों को संतुष्ट कर सकने वाली सामन नागरिक संहिता का निर्माण करना व्यावहारिक रूप से असंभव है। विधि आयोग की वर्ष 2018 की रिपोर्ट में देश की विविधता का हवाला देते हुए निष्कर्ष दिया गया था कि वर्तमान समय में समान नागरिक संहिता 'न तो आवश्यक है और न वांछनीय। चुनौती इस तथ्य से स्पष्ट है कि हिंदू कानून में भी, जिसे 1950 के दशक में संहिताबद्ध किया गया था, अभी भी क्षेत्रीय भिन्नता मौजूद हैं। उदाहरण के लिए, हिंदू उत्तराधिकार (केरल संशोधन) अधिनियम 2015 केरल में विभिन्न उत्तराधिकार नियमों का प्रावधान करता है।

एक राष्ट्रव्यापी समान नागरिक संहिता का कार्यान्वयन संभावित रूप से भारत के संघीय ढांचे का उल्लंघन कर सकता है। व्यक्तिगत कानून संविधान की समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं, जिसके तहत राज्य और केंद्र दोनों सरकारों को उन पर कानून बनाने का अधिकार है। आलोचकों का मानना है कि केंद्र द्वारा अधिरोपित समान नागरिक संहिता राज्य स्वायत्तता को कमजोर कर सकती है। हाल ही में उत्तराखंड में राज्य की स्वयं की पहल के रूप में युसीसी का कार्यान्वयन सवाल खड़े करता है कि राष्ट्रीय समान नागरिक संहिता राज्य विशिष्ट कानूनों एवं रीति रिवाजों के साथ किस प्रकार तालमेल स्थापित करेगी।

इस कानून के कार्यान्वयन के लिये कानूनी प्रणाली में बड़े पैमाने पर सुधार की आवश्यकता है। इसके लिए संभावित रूप से महत्वपूर्ण लागतें उठानी पड़ेंगी। इसमें कानूनी पेशेवरों को पुनः प्रशिक्षित करना, कानूनी डेटाबेस को अद्यतन करना तथा संक्रमण काल के दौरान न्यायालय पर बोझ बढ़ान शामिल है। आलोचकों का तर्क है कि भारत की न्यायपालिका पहले से ही 47 मिलियन से अधिक लंबित मामलों का सामना कर रही है, समान नागरिक संहिता के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक संसाधनों को बेहतर उपयोग यह होगा कि उन्हें मौजूदा न्यायिक अक्षमताओं को दूर करने के लिए किया जाए।

इस कानून के लिए आगे की राह में विविध हितधारकों के साथ व्यापक, राष्ट्रव्यापी परामर्श शामिल होना चाहिए। इसमें धार्मिक नेताओं, कानूनी विशेषज्ञों, नागरिक समाज संगठनों और विभिन्न समुदायों के प्रतिनिधियों को शामिल किया जाना चाहिये। यह प्रक्रिया पारदर्शी होनी चाहिए तथा प्रस्तावित परिवर्तनों और उनके निहितार्थों के बारे में स्पष्ट जानकारी होनी चाहिये। जागरूकता पैदा करने और विविध दृष्टिकोणों से अवगत होने के लिये सार्वजनिक बहस एवं चर्चाओं को प्रोत्साहित किया जाना चाहिये। यह समावेशी दृष्टिकोण चिंताओं को दूर करने और व्यापक आम सहमति का निर्माण करने में मदद कर सकता है, जिससे कार्यान्वयन के प्रति प्रतिरोध में कमी आ सकती है। यह लगता है कि अचानक आमूलचूल परिवर्तन के बजाय, इस कानून का चरणबद्ध कार्यान्वयन अधिक व्यवहार्य और कम विघटनकारी सिद्ध हो सकता है। इसकी शुरुआत व्यापक सहमति वाले विषयों से हो सकती है, जैसे विवाह की कानूनी आयु का मानकीकरण, महिलाओं को समान अधिकार या उत्तराधिकार अधिकार। फिर अगले चरण में अधिक विवादास्पद मुद्दों को संबोधित किया जा सकता है। यह क्रमिक दृष्टिकोण प्राप्त प्रतिक्रिया (फीडबैक) और वास्तविक व्यवहार्य परिणामों के आधार पर समायोजन की अनुमति प्रदान करेगा। यह समुदायों को अनुकूलित होने और कानूनी प्रणाली को परिवर्तनों के लिये तैयार होने का समय भी प्रदान करेगा।

किसी भी समान नागरिक संहिता के कार्यान्वयन में अल्पसंख्यक अधिकारोंऔर सांस्कृतिक प्रथाओं की रक्षा के लिए सुदृढ़ संवैधानिक सुरक्षा उपाय शामिल होने चाहिये। इसमें युसीसी कार्यान्वयन की निगरानी और षिकायतों के समाधान के लिये एक निकाय का गठन करना शामिल हो सकता है। समुदायों के लिये स्पष्ट तंत्र स्थापित किया जाना चाहिये। इससे वे उन विशिष्ट प्रथाओं के लिये छूट प्राप्त कर सकेंगे जो मूल अधिकारों के साथ टकराव की स्थिति में नहीं है। यह दृष्टिकोण एकरूपता और सांस्कृतिक संरक्षण के लक्ष्यों को संतुलित करने में मदद कर सकता है। साथ ही युसीसी के आलोचकों की प्रमुख चिंताओं का समाधान कर सकता है। समान नागरिक संहिता की तुलना में न्यायपूर्ण नागरिक संहिता अधिक महत्वपूर्ण है।

आगे बढ़ने के लिये व्यक्तिगत कानून सुधारों से संबंधित मौजूदा राज्य-स्तरीय पहलों का सावधानीपूर्वक अध्ययन किया जाना चाहिये। उदाहरण के लिये, गोवा की नागरिक संहिता (जो पुर्तगाली शासन के समय से लागू है) और उत्तराखंड में हाल में समान नागरिक संहिता के कार्यान्वयन के परिणामों का विष्लेषण किया जाना चाहिये। यह साक्ष्य आधारित दृष्टिकोण राष्ट्रीय युसीसी के डिजाइन को सूचना संपन्न कर सकता है तथा सफल रणनीतियों और संभावित खामियों को उजागर कर सकता है। यह युसीसी के पक्ष और विपक्ष में तर्कों को समर्थन देने या संषोधित करने के लिये ठोस आंकड़ों भी उपलब्ध करा सकता है।

शतरंज की बिसात और न्याय- पश्चाताप का स्टेलमेट

पुस्तक समीक्षा

सुरेश उपाध्याय

समीक्षक

स्टेलमेट, वरिष्ठ साहित्यकार व समीक्षक दीपक गिरकर का न्यू वर्ल्ड पब्लिकेशन, नई दिल्ली से हाल ही में प्रकाशित उपन्यास है। इसके पूर्व गिरकर के दो उपन्यास 'अम्मा' व 'एक बैंक मैनेजर की डायरी' के अतिरिक्त एक व्यंग्य संग्रह, प्रेरक आलेख संग्रह, बैंक एनपीए पर पुस्तक प्रकाशित होकर चर्चा में रही है। उत्कृष्ट लघुकथा विमर्श (आलोचना) के सम्पादन के साथ साहित्यिक शोधकार्य, समालोचना व समीक्षा के क्षेत्र में उनकी सक्रियता उल्लेखनीय है।

स्टेलमेट' उपन्यास को मुख्यपात्र 'माधवी' के माध्यम से जेल की सजा काटते वक्त 'फ्लैशबैक' में प्रथम पुरुष के रुप में नरेट (वाचन) किया गया है। सम्पन्न परिवार में बचपन, कालेज की शोख, चंचल, होनहार व प्रतिभाशाली छात्रा का अपने सहपाठी से प्रेम, प्रेम विवाह में जातीय, आर्थिक असमानता, सामाजिक पृष्ठभूमि की दीवारे, परिवार के अलगाव व समयोपरांत स्वीकृति से उपन्यास की शुरुआत होती है। बेटे कार्तिक के बाद मूक बधिर बेटी अनामिका के जन्म के साथ उत्पन्न हुई चुनौती को वह स्वीकारती है तथा शतरंज में उसका केरियर बनाने की ठानती है। अपना केरियर छोडकर उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर का खिलाडी बनाती है। आध्यात्मिक गुरु ब्रह्मर्षी सुब्बाराव के प्रति झुकाव होता है तथा अपने सहपाठी राजनीतिज्ञ के आग्रह पर राजनीति में आती है और शिक्षामंत्री बनती है इस बीच पति श्रीनिवासन का जुडाव अपनी सहकर्मी से होता है तथा शराब की आदत के साथ वापसी होती है। एक दिन बेटी का अपहरण, बलात्कार व हत्या की सूचना पुलिस से मिलती है और सुब्बाराव का सेवक वेंकट रेड्डी अपराधी घोषित कर सजा पाता है बेटी के हाथ की मुट्ठी में सफेद बाल से सही अपराधी को लेकर उसे संदेह रहता है। इसी बीच खोजी पत्रकार लक्ष्मी अय्यर कैदी वेंकट रेड्डी से चर्चा के बाद खोजबीन करती है तथा ब्रह्मर्षी सुब्बाराव के अपराधी होने तथा उसे बचाने के षडयंत्रो का खुलासा करती है। ट्रायल फिर से होती है तथा ब्रह्मर्षी को आजीवन कैद की सजा तथा वेंकट रेड्डी को निर्दोष घोषित किया जाता है। बारङ्कबार पेरोल, जेल में सारी सुविधाओं तथा अनुयायियों में ब्रह्मर्षी के प्रति वही भाव माधवी को बैचेन करते हैं तथा पेरोल के दौर में वह ब्रह्मर्षी के दोनो हाथ काटकर दो वर्ष की सजा काट रही है। इस स्थिति में वह सोच रही है -क्या उसकी बेटी को न्याय मिला?, क्या सुब्बाराव को कोई पछतावा है? और इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि न तो सुब्बाराव हारा है और न वह जीती है तथा शतरंज के खेल की तरह 'स्टेलमेट' की स्थिति निर्मित हुई है।

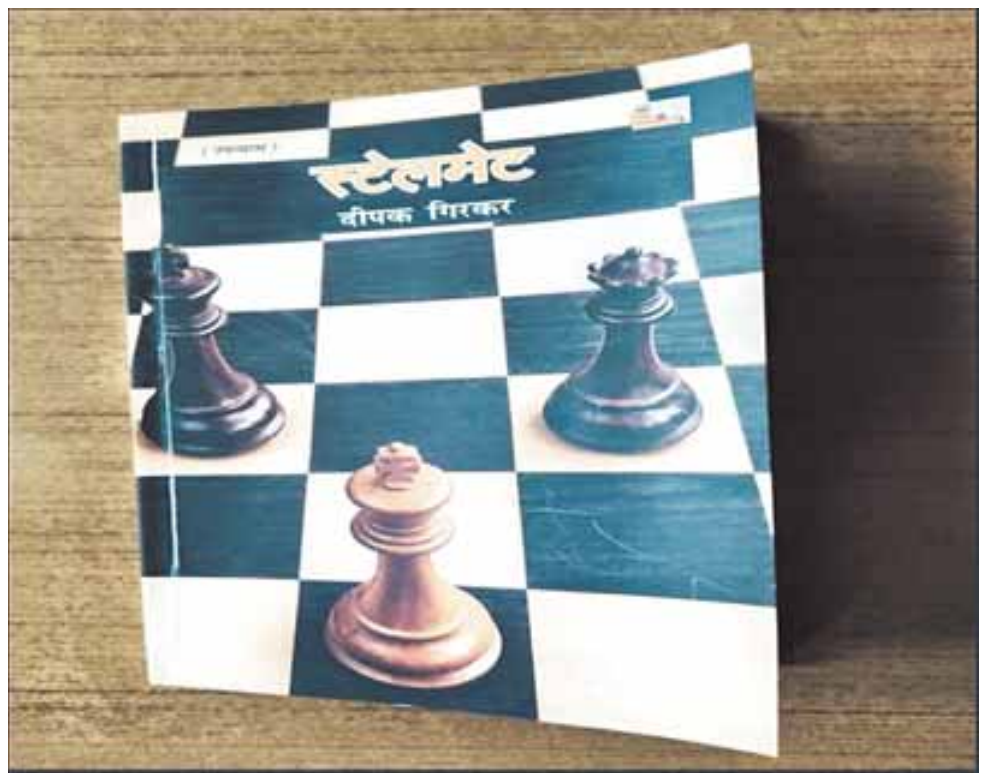

इस उपन्यास के निमित्त दीपक गिरकर ने सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, खेल व आध्यात्मिक क्षेत्र की विसंगतियो व कुरुपताओ को रेखांकित किया है। एक खिलाडी को तैयार करने में उसका, उसके परिवार व प्रशिक्षक का त्याग व बलिदान तो दिखाई देता ही है, साथ ही खेल संगठनो में गुटबाजी, दांवपेंच, राजनीति व छल प्रपंच किस तरह समाए हुए हैं, यह भी अनुभव किया जा सकता है। सरकारी शिक्षा व्यवस्था में संसाधनों का अभाव तथा हतोत्साहित करने की नीतियों से निजी संस्थाओं के लिए बढते अवसर हैं तो नई शिक्षा मंत्री के समक्ष कोई नई दृष्टि नही है। एनजीओ से अपेक्षा व संविदा नियुक्ति का ही फार्मूला दिखाई देता है।

उपन्यास की भाषा व लय ने कथासूत्रों को इस तरह गूंथा है कि निर्बाध पढने की आकांक्षा बनी रहती है। पाठक इस उपन्यास को पसंद करेंगे, इसी विश्वास के साथ इस उपन्यास का स्वागत करते हुए लेखक श्री दीपक गिरकर को बधाई देता हूँ।

उपन्यास - स्टेलमेट
लेखक - दीपक गिरकर
प्रकाशक - न्यू वर्ल्ड पब्लिकेशन
मूल्य - रु 299/-

'विजिटर बुक' में बचीं पं. माधवराव सप्रे की यादें

गौरव अवस्थी

11 हिंदी पत्रकारिता के 200वें वर्ष में यह स्मरण केवल उत्सव का नहीं, बल्कि उन पुरखों को याद करने का भी अवसर है जिन्होंने हिंदी को जनचेतना का माध्यम बनाया। ऐसे ही पुरखों में एक महत्वपूर्ण नाम है पंडित माधवराव सप्रे का। मराठी भाषी होते हुए भी उन्होंने हिंदी को अपनी साधना बनाया और पत्रकारिता, साहित्य तथा समाज सुधार–तीनों क्षेत्रों में अमिट छाप छोड़ी।

वर्ष 1900 में सप्रेजी ने सरकारी नौकरी का सुरक्षित रास्ता छोड़ पेंड्रा से हिंदी समाचार पत्र 'छत्तीसगढ़ मित्र' का प्रकाशन शुरू किया। यह पत्र भले ही केवल तीन वर्ष चल पाया, लेकिन हिंदी पत्रकारिता के इतिहास में उसका स्थान स्थायी हो गया। छत्तीसगढ़ के प्रथम हिंदी पत्रकार होने का श्रेय भी सप्रेजी को ही दिया जाता है। हिंदी साहित्य में भी उनका योगदान उतना ही महत्वपूर्ण है। उनकी रचना 'एक टोकरी भर मिट्टी' को हिंदी की पहली कहानी माना जाता है। इस प्रकार हिंदी पत्रकारिता और हिंदी कहानी–दोनों विधाओं के प्रारंभिक इतिहास में उनका नाम आदर के साथ दर्ज है।

लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के मराठी पत्र 'केसरी' के हिंदी संस्करण 'हिंदी केसरी' में प्रकाशित लेखों के कारण अंग्रेज सरकार ने उन्हें जेल भेज दिया। बाद में परिस्थितियों के दबाव में उन्हें माफीनामा देकर रिहाई मिली, लेकिन इस घटना ने उन्हें भीतर तक तोड़ दिया। उन्होंने सार्वजनिक जीवन से लगभग संन्यास ले लिया और लंबे समय तक अज्ञातवास जैसा जीवन बिताया। इसी दौरान रायपुर उनके जीवन का प्रमुख केंद्र बना। मित्र वामनराव लाखे और केशव नारायण पाध्ये के माध्यम से उनकी भेंट श्रीधर विष्णु परांजपे से हुई। सप्रेजी ने हनुमानगढ़ में रहकर दासबोध का 13 बार पारायण किया। बाद में रायपुर लौटकर उन्होंने बूढ़ापारा स्थित रामदास मठ में निवास किया। वर्ष 1913 में तात्यापारा में मकान खरीदकर उन्होंने वहां रामदास मठ की स्थापना की। यहीं तपस्वी जीवन जीते हुए उन्होंने दासबोध तथा तिलक कृत 'गीता रहस्य' सहित कई ग्रंथों का मराठी से हिंदी में अनुवाद किया।

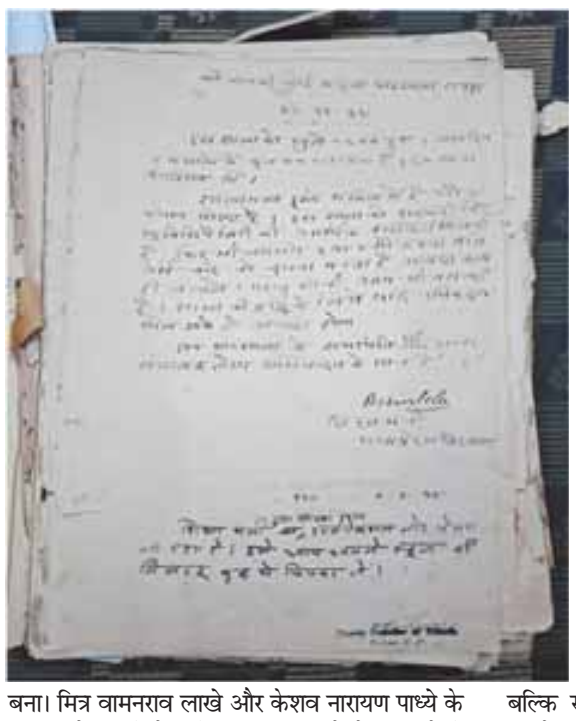

सप्रेजी केवल पत्रकार और साहित्यकार ही नहीं थे, बल्कि स्त्री शिक्षा के भी बड़े समर्थक थे। मित्रों के सहयोग से उन्होंने रायपुर के सदर बाजार में 'श्री जानकी देवी महिला पाठशाला' की स्थापना की। मराठी और हिंदी माध्यम की इस पाठशाला में योग्य शिक्षिकाओं की नियुक्ति की गई। उमाबाई पटवर्धन प्रधान अध्यापिका बनीं, जबकि गंगाबाई पवार और गोदावरीबाई मुले सहायक शिक्षिका नियुक्त हुईं। 23 छात्राओं से शुरू हुई यह पाठशाला शीघ्र ही क्षेत्र में स्त्री शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र बन गई। छात्राओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए इसकी नई शाखा भी खोलनी पड़ी।

सप्रेजी का सपना था कि विद्यालय के संचालन के लिए स्थायी कोष बने और उसका अपना भवन हो, लेकिन यह सपना अधूरा रह गया। आज इस पाठशाला की एक पुरानी विजिटर बुक सप्रेजी की स्मृतियों को संजोए हुए है। प्रधानाध्यापक जितेंद्र सेन ने इन दस्तावेजों को संभालकर रखा है, अन्यथा यह इतिहास शायद गुम हो चुका होता।

विजिटर बुक में दर्ज टिप्पणियां बताती हैं कि 20वीं सदी के आरंभ में यह पाठशाला कितनी प्रभावशाली थी। 27 जून 1917 को तत्कालीन कार्यवाहक इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स गुलाब सिंह ने लिखा था–

'अनेक सरकारी कन्या पाठशालाओं में इतनी योग्य अध्यापिकाएं नहीं पाई जातीं... यह पाठशाला इस बात का प्रत्यक्ष उदाहरण है कि उत्तम प्रबंधन और शिक्षिकाओं के उत्साह से कितने महत्वपूर्ण परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। '

13 जुलाई 1915 को तत्कालीन डिप्टी कमिश्नर की पत्नी एच. रुस्तमजी ने टिप्पणी की थी–

'ऐसी पाठशाला का होना हिंदुओं के लिए गौरव की बात है। ' इसी प्रकार 21 दिसंबर 1937 को तत्कालीन शिक्षा मंत्री ने विद्यालय के संचालन और समाज के सहयोग की सराहना की थी। इन टिप्पणियों से स्पष्ट होता है कि यह पाठशाला केवल शिक्षा का केंद्र नहीं, बल्कि सामाजिक जागरण का भी माध्यम थी।

समय के साथ सप्रेजी से जुड़ी अधिकांश निशानियां मिटती चली गईं। रामदास मठ अब अस्तित्व में नहीं है। 'श्री जानकी महिला पाठशाला' भी बाद में 'सौ. कुसुमताई दाबके स्मृति पाठशाला' के नाम से संचालित होने लगी। आज भी विद्यालय चल रहा है, लेकिन उसकी मूल पहचान लगभग धुंधली पड़ चुकी है।

तात्यापारा स्थित वह मकान भी, जिसे सप्रेजी ने खरीदा था, वर्ष 2008 में बिक गया। इसके साथ ही हिंदी और मराठी सांस्कृतिक संवाद की एक महत्वपूर्ण स्मृति भी लगभग समाप्त हो गई। दुखद यह है कि अब रायपुर में बहुत कम लोग ऐसे बचे हैं, जो सप्रेजी के निवास का सही स्थान बता सकें।

हिंदी पत्रकारिता की द्विशताब्दी केवल अतीत का उत्सव नहीं, बल्कि स्मृतियों को बचाने की जिम्मेदारी भी है। पंडित माधवराव सप्रे जैसे पुरखों की विरासत को सहेजना इसलिए जरूरी है, क्योंकि उन्होंने हिंदी को केवल भाषा नहीं, बल्कि समाज जागरण का माध्यम बनाया था।

हिंदी लेखिका संघ की वार्षिक सभा में नवाचारों की सराहना

भोपाल। हिंदी लेखिका संघ, मध्यप्रदेश, भोपाल की वार्षिक साधारण सभा का आयोजन हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता संघ की पूर्व अध्यक्ष डॉ. राजश्री रावत ने मुख्य अतिथि संघ की पूर्व अध्यक्ष एवं वरिष्ठ साहित्यकार ऊषा जायसवाल थीं। विशिष्ट अतिथि संघ की पूर्व अध्यक्ष अनीता सक्सेना तथा डॉ. कुंकुम गुप्ता थीं। संघ की अध्यक्ष डॉ. साधना गंगराडे ने स्वागत भाषण के साथ गत वर्ष का आय-व्यय विवरण, वार्षिक लेखा-जोखा तथा संस्था की गतिविधियों का विस्तृत प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। सह सचिव शेफालिका श्रीवास्तव ने वर्षभर आयोजित

साहित्यिक, सांस्कृतिक एवं रचनात्मक गतिविधियों का प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए संस्था की उपलब्धियों बताईं।

अध्यक्षीय उद्बोधन में डॉ. राजश्री रावत ने कहा कि हिंदी लेखिका संघ की संस्थापक स्वर्गीय सुशीला जी द्वारा बोया गया साहित्यिक बीज आज एक विशाल वटवृक्ष का रूप ले चुका है। उन्होंने कहा कि डॉ. साधना गंगराडे के नेतृत्व में संस्था ने गत वर्ष उल्लेखनीय उपलब्धियाँ अर्जित की हैं और साहित्यिक गतिविधियों को नई ऊर्जा मिली है। मुख्य अतिथि ऊषा जायसवाल ने वर्षभर आयोजित नवाचारपूर्ण कार्यक्रमों एवं कार्यशालाओं की सराहना करते हुए कहा कि संस्था ने साहित्य को नई पीढ़ी से जोड़ने की दिशा में सार्थक प्रयास किए हैं। विशिष्ट अतिथियों ने भी संस्था की सक्रियता की प्रशंसा करते हुए पदाधिकारियों को शुभकामनाएँ दीं। कार्यक्रम का शुभारंभ कल्पना विजयवर्गीय द्वारा प्रस्तुत सरस्वती वंदना से हुआ। कार्यक्रम संचालन उपाध्यक्ष वर्षा चौबे ने किया, जबकि उपाध्यक्ष साधना शुक्ला ने आभार व्यक्त किया। अंत में हिंदी लेखिका संघ की दिवंगत सदस्य, वरिष्ठ साहित्यकार आशा सक्सेना एवं प्रख्यात व्यंग्यकार विजया तेलंग को दो मिनट का मौन रखकर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई।

कार्यकर्ता पूरे मनोयोग के साथ बूथ केंद्रों पर संगठन विस्तार में जुटे - कांतदेव सिंह

जिला कार्यसमिति की मासिक जिला बैठक संपन्न

बैतूल। भाजपा की महत्वपूर्ण मासिक बैठक भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय विजय भवन में संपन्न हुई। बैठक को संबोधित करते हुए भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष एवं संभाग प्रभारी कांतदेवसिंह ने कहा कि भाजपा का हर कार्यकर्ता राष्ट्र निर्माण के पथ पर पूरी निष्ठा के साथ अग्रसर है। मंडल अध्यक्ष एवं मंडल प्रभारीयों से वन टू वन चर्चा में श्री सिंह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा से अंत्योदय और जनसेवा के संकल्प के साथ आगे

बढ़ती आई है। संगठन की मजबूती ही पार्टी की सबसे बड़ी ताकत है और हर एक कार्यकर्ता राष्ट्र निर्माण के पथ पर पूरी निष्ठा के साथ अग्रसर है। हर कार्यकर्ता की जिम्मेदारी है कि पूरे मनोयोग के साथ शक्ति केन्द्र व बूथ पर प्रशिक्षित कार्यकर्ताओ के साथ संगठन विस्तार में जुट जाए। बैठक को संबोधित करते हुए भाजपा जिलाध्यक्ष सुधाकर पंवार ने कहा कि पिछले दिनों जो कार्यक्रम संपन्न हुए उसमें अपेक्षित सफलता हमें मिली है। जिससे हर कार्यकर्ता और पदाधिकारी की अतिरिक्त जिम्मेदारी इस सफलता को बरकरार रखने की है। आने वाले दिनो में जो भी कार्यक्रम प्रदेश नेतृत्व की ओर से प्राप्त होगें उन्हे भी पूरी तरह से सफल कराने की जिम्मेदारी को समझते हुए हमें कार्यक्रमो की रणनीति बनानी हैं। श्री पंवार ने कहा कि संगठन विस्तार के लिए कार्यकर्ता को मंडल एवं शक्ति केंद्र की बैठकें पूरी जिम्मेदारी के साथ संपन्न हो इसकी चिंता करनी है। बैठक को संबोधित करते हुए डिजिटल लर्निंग अभियान के जिला संयोजक कमलेश सिंह ने कहा कि यह अभियान हर बूथ पर ग्यारह लोगो की प्रशिक्षित टोली का अहम हिस्सा है। आज का डिजिटल दौर हर क्षेत्र में डिजिटल लर्निंग पर जोर देने वाला है। हमारे बूथ के कार्यकर्ता डिजिटल रूप से प्रशिक्षित होकर अपेक्षित लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकता है। बैठक के दौरान मुलताई विधायक चंद्रशेखर देशमुख, भैसदेही विधायक महेन्द्रसिंह चौहान, आमला विधायक डा.योगेश पंडाग्रे, घोडाडोगरी विधायक गंगा उइके , जिला पंचायत अध्यक्ष राजा पंवार मंचासीन रहे। बैठक का संचालन जिला महामंत्री कृष्णा गायकी ने किया एवं अंत में आभार जिला महामंत्री डा.महेन्द्रसिंह चौहान ने व्यक्त किया।

सतपुड़ा वैली स्कूल के 21वें फाउंडेशन डे पर छात्र परिषद ने ली शपथ

लोकतांत्रिक चुनाव में दीवा डागा और मोक्षा डागा बने छात्र संघ अध्यक्ष

बैतूल। सतपुड़ा वैली पब्लिक स्कूल में 21वें फाउंडेशन डे के अवसर पर लोकतांत्रिक मूल्यों, नेतृत्व क्षमता और अनुशासन का अनूठा संगम देखने को मिला। विद्यालय में आयोजित छात्र परिषद के शपथ ग्रहण समारोह में लोकतांत्रिक प्रक्रिया से निर्वाचित छात्र प्रतिनिधियों ने पद एवं गोपनीयता की शपथ लेकर अपने दायित्वों का निर्वहन करने का संकल्प लिया। इस दौरान सीबीएसई विंग में मोक्षा डागा तथा कैम्ब्रिज विंग में दीवा डागा ने भारी बहुमत से छात्र संघ अध्यक्ष (स्कूल कैप्टन) निर्वाचित होकर छात्र नेतृत्व की नई मिसाल पेश की। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि निर्मला डागा एवं निलय विनोद डागा रहे, जबकि विद्यालय की डायरेक्टर दीपाली निलय डागा की विशेष उपस्थिति रही। समारोह का शुभारंभ अतिथियों द्वारा दीप प्रज्ज्वलन से हुआ। इसके बाद विद्यालय के छात्र-छात्राओं ने आकर्षक एवं अनुशासित परेड प्रस्तुत कर सभी का मन मोह लिया। शपथ ग्रहण समारोह में सीबीएसई विंग की छात्र परिषद के स्कूल कैप्टन मोक्षा डागा, कल्चरल कैप्टन नेतल अग्रवाल, डिसिप्लिन कैप्टन आशी खंडेलवाल एवं स्पोर्ट्स कैप्टन समर्थ चौहान ने पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। वहीं कैम्ब्रिज विंग में स्कूल कैप्टन दीवा डागा, कल्चरल कैप्टन दृष्टि नरवरे तथा स्पोर्ट्स कैप्टन सेजल साहू ने अपने दायित्व ग्रहण किए। सीबीएसई विंग के गुंजन (ग्रीन) हाउस के हाउस कैप्टन यश कावड़े एवं हाउस रिप्रेजेंटेटिव मोक्षदा धाकड़े, नीनाद (ब्लू) हाउस की हाउस कैप्टन प्रगति जैन एवं हाउस रिप्रेजेंटेटिव अविराज चौहान, कलरव (रेड) हाउस की हाउस कैप्टन जिज्ञासा गुजरे एवं हाउस रिप्रेजेंटेटिव रक्षित गोठी तथा झंकार (येलो) हाउस के हाउस कैप्टन झबक पवार एवं हाउस रिप्रेजेंटेटिव बुरहानुद्दीन कुतबी ने भी शपथ लेकर अपनी जिम्मेदारियां संभालीं। कैम्ब्रिज विंग में वीनस हाउस की हाउस कैप्टन अरुंधति वैद्य एवं वाइस कैप्टन श्रष्टि राठौर, नेपच्यून हाउस की हाउस कैप्टन आराध्या दीक्षित एवं वाइस कैप्टन भानुजा पवार, मार्स हाउस की हाउस कैप्टन कनिष्का गोठी एवं वाइस कैप्टन प्रतिभा ठाकुर तथा जुपिटर हाउस के हाउस कैप्टन सारांश देशमुख एवं वाइस कैप्टन बतुल नाज़ ने भी नेतृत्व, अनुशासन और जिम्मेदारी के साथ कार्य करने की शपथ ली। विद्यालय की डायरेक्टर दीपाली निलय डागा ने अपने संबोधन में कहा कि विद्यालय का उद्देश्य केवल गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना नहीं, बल्कि विद्यार्थियों में श्रेष्ठ संस्कार, अनुशासन, नैतिक मूल्यों और नेतृत्व क्षमता का विकास करना भी है। उन्होंने कहा कि शिक्षा और संस्कार का समन्वय ही बच्चों को जिम्मेदार, संवेदनशील और सफल नागरिक बनाता है। मुख्य अतिथि निर्मला डागा ने विद्यार्थियों को ईमानदारी, सेवा, अनुशासन और समर्पण की भावना से कार्य करने की प्रेरणा दी। वहीं निलय विनोद डागा ने अनुशासित नेतृत्व, टीम भावना और जिम्मेदारी के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने का संदेश दिया। विद्यालय के उप-प्राचार्य अरविंद सिंह राजपूत ने नव-निर्वाचित छात्र प्रतिनिधियों को शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की तथा कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों, अभिभावकों और सहयोगियों के प्रति आभार व्यक्त किया।

विद्यालय की विशेषता यह रही कि छात्र परिषद के चुनाव पूरी तरह लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत बैलेट पेपर के माध्यम से संपन्न कराए गए, जिसमें विद्यार्थियों के साथ शिक्षकगण ने भी मतदान कर अपने प्रतिनिधियों का चयन किया। विद्यालय की इस परंपरा को विद्यार्थियों में लोकतांत्रिक मूल्यों, नेतृत्व क्षमता, उत्तरदायित्व, आत्मविश्वास और निर्णय लेने की योग्यता विकसित करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जाता है।

इस वर्ष छात्र नेतृत्व के चुनाव में उत्साहपूर्ण मुकाबले के बाद कैम्ब्रिज विंग में दीवा डागा और सीबीएसई विंग में मोक्षा डागा ने भारी बहुमत से जीत दर्ज कर छात्र-छात्राओं का विश्वास हासिल किया। विद्यालय प्रबंधन, शिक्षकों एवं विद्यार्थियों ने दोनों नव-निर्वाचित छात्र संघ अध्यक्षों को शुभकामनाएं देते हुए विश्वास जताया कि वे विद्यार्थियों की समस्याओं और सुझावों को प्रभावी ढंग से विद्यालय प्रशासन तक पहुंचाने के साथ-साथ शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक गतिविधियों में सक्रिय और सकारात्मक नेतृत्व प्रदान करेंगी।

सांदीपनि स्कूल के विद्यार्थियों ने शुरू किया हरित अभियान

100 परिवारों में विकसित होंगे आम के बगीचे

बैतूल। पर्यावरण संरक्षण को जनभागीदारी से जोड़ते हुए बैतूल बाजार के सांदीपनि स्कूल ने 100 विद्यार्थियों और उनके परिवारों के साथ सघन पौधरोपण अभियान शुरू किया है। स्कूल के ईको-क्लब की इस पहल के तहत जहां विद्यार्थी रहते है उनके विभिन्न गांवों में 100 परिवारों के यहां आम के बगीचे विकसित किए जाएंगे, जिससे हरियाली बढ़ाने के साथ भविष्य में परिवारों को फल और आर्थिक लाभ भी मिल सकेगा। अभियान की खासियत यह है पौधे बांटने तक सीमित न रहकर उनके संरक्षण की डिजिटल मॉनिटरिंग भी की जाएगी। प्रभारी प्राचार्य आर.के. मालवीय के मार्गदर्शन में ईको-क्लब की छात्राएं डाली कामतकर, माधुरी बारस्कर, वंशिका पाल और दिव्यांशी खैरकर ने अभियान का संचालन किया एवं

इसकी संपूर्ण मॉनिटरिंग भी यह विद्यार्थी ही करेंगे। कक्षा 9वीं से 12वीं तक के 100 ऐसे विद्यार्थियों का चयन किया गया, जिन्होंने अपने खेत, आंगन या घर के परिसर में पहले से पौधरोपण के लिए गड्ढे तैयार कर लिए थे। चयन पूरी तरह पारदर्शी रखा गया और विद्यार्थियों को गड्ढों की फोटो दिखाने के बाद ही अभियान में शामिल कर पौधे वितरित किए गए। जे.आर.सी. प्रभारी निशा पवार ने बताया कि अभियान की सतत निगरानी के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है। इसमें विद्यार्थी गड्ढा खोदने, पौधारोपण, परिवार और दोस्तों के साथ पौधों की सेल्फी तथा सुरक्षा व्यवस्था की तस्वीरें साझा करेंगे। हर दूसरे-तीसरे दिन पौधों की नई तस्वीरें भेजना भी अनिवार्य रहेगा, ताकि उनके विकास और संरक्षण की लगातार मॉनिटरिंग हो सके। इस व्यवस्था का उद्देश्य विद्यार्थियों में नेतृत्व क्षमता विकसित करने के साथ पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी की भावना मजबूत करना है। अभियान के तहत विद्यार्थियों को आम की उन्नत बडिंग प्रजातियों के पौधे वितरित किए गए, जिनमें दशहरी, लंगड़ा, चौसा और आम्रपाली शामिल हैं। इन पौधों के माध्यम से विभिन्न गांवों में हरियाली बढ़ाने के साथ भविष्य में परिवारों को पोषण और आय का अतिरिक्त स्रोत भी उपलब्ध होगा। पौधा वितरण कार्यक्रम में उत्कृष्ट प्राचार्य उदयपुरे, जिला शिक्षा कार्यालय के आई.टी. सेल प्रमुख विनोद पड़लक, दिलीप गीद, मनोज रघुवंशी, अभय जोशी और शिवकुमार दांदडे उपस्थित रहे। अतिथियों ने विद्यार्थियों के प्रयास की सराहना करते हुए पौधारोपण और संरक्षण की उपयोगी तकनीकों की जानकारी दी तथा विश्वास जताया कि युवाओं की यह पहल स्कूल ही नहीं, पूरे जिले के लिए प्रेरणादायी उदाहरण बनेगी।

विश्वकर्मा समाज के निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर में 500 से अधिक लोगों ने कराया परीक्षण

ब्रेन को स्वस्थ रखने के पांच मंत्र देकर डॉ. सिकंदर आडवाणी ने किया जागरूक

बैतूल। विश्वकर्मा मंदिर बैतूल गंज में रविवार को विश्वकर्मा समाज समिति एवं समाज के चिकित्सा प्रकोष्ठ के संयुक्त तत्वावधान में स्व.अभिषेक मालवी, स्व.शैलेन्द्र मालवी एवं स्व.राजेश मालवी की स्मृति में विशाल निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर आयोजित किया गया। शिविर की सबसे बड़ी विशेषता यह रही कि सर्वधर्म समभाव की भावना के साथ आयोजित इस सेवा कार्य में सभी समुदायों के 500 से अधिक लोगों ने स्वास्थ्य परीक्षण कराया, चिकित्सकीय परामर्श लिया तथा निःशुल्क दवाइयों का लाभ प्राप्त किया। शिविर की सबसे बड़ी विशेषता यह रही कि सर्व धर्म समभाव की भावना के साथ एक पेड़ मां के नाम पौध रोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। बैतूल सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से बड़ी संख्या में पहुंचे मरीजों का विभिन्न विशेषज्ञ

चिकित्सकों ने स्वास्थ्य परीक्षण किया। इस अवसर पर अमरावती से पधारे सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉ. सिकंदर आडवाणी ने बैतूल वन ब्रेन अभियान के माध्यम से मस्तिष्क को स्वस्थ रखने के पांच महत्वपूर्ण सूत्र बताए। उन्होंने प्रतिदिन 20 से 25 मिनट पैदल चलने, 6 से 7 घंटे की पर्याप्त नींद लेने, ब्लड प्रेशर और शुगर को नियंत्रित रखने, सामाजिक रूप से लोगों से जुड़े रहने तथा जीवनभर कुछ नया सीखते रहने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि मस्तिष्क को जितनी चुनौती दी जाएगी, वह उतना ही सक्रिय रहेगा। तंबाकू को मस्तिष्क के लिए सबसे खतरनाक बताते हुए इससे पूरी तरह दूर रहने की अपील की। उन्होंने बताया कि इन पांच आदतों को अपनाकर लगभग 10 बीमारियों के खतरे को 45 प्रतिशत तक कम किया जा सकता है। साथ ही उन्होंने कहा कि ब्रेन स्ट्रोक के लक्षण दिखाई देने पर चार घंटे के भीतर अस्पताल पहुंचना बेहद जरूरी है और इन स्वास्थ्य आदतों को अपनाने का सकारात्मक परिणाम छह माह के भीतर दिखाई देने लगता है। कार्यक्रम में बैतूल रेडक्रॉस सोसायटी के जिलाध्यक्ष एवं सिटी हॉस्पिटल के संचालक डॉ. अरुण जयसिंहपुरे तथा सुभद्रा हॉस्पिटल के संचालक डॉ. विनय सिंह चौहान मुख्य रूप से उपस्थित रहे।

नई कार्यकारिणी का हुआ पदभार ग्रहण, सेवा कार्यों को नई ऊंचाई देने का लिया संकल्प

सेवा और समर्पण के संकल्प के साथ लायंस क्लब की नई टीम ने संभाली जिम्मेदारी

डॉ. संतोष जायसवाल बने लायंस क्लब बैतूल सिटी के नए अध्यक्ष

बैतूल। सेवा, नेतृत्व और सामाजिक उत्तरदायित्व के संकल्प के साथ लायंस इंटरनेशनल डिस्ट्रिक्ट 3233-जी2 के अंतर्गत लायंस क्लब बैतूल सिटी, लायंस क्लब महक और लायंस क्लब अमिगोस का संस्थापन एवं शपथ ग्रहण समारोह शनिवार को गरिमामय वातावरण में संपन्न हुआ। समारोह में तीनों क्लबों की नवगठित कार्यकारिणी ने पद एवं गोपनीयता की शपथ लेकर समाजहित में निष्ठा, पारदर्शिता और समर्पण के साथ कार्य करने का संकल्प लिया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लायंस सदस्य, गणमान्य नागरिक एवं आमंत्रित अतिथि उपस्थित रहे। समारोह में डॉ. संतोष जायसवाल ने लायंस क्लब बैतूल सिटी के अध्यक्ष पद की शपथ लेकर नई कार्यकारिणी के साथ विधिवत पदभार ग्रहण किया। इसी अवसर पर लायंस क्लब महक की अध्यक्ष रक्षा अग्रवाल तथा लायंस क्लब अमिगोस के अध्यक्ष प्रजग भार्गव सहित दोनों क्लबों की नई कार्यकारिणी ने भी शपथ लेकर अपने दायित्वों का निर्वहन करने का संकल्प लिया।

वरिष्ठ लायन अधिकारियों ने दिलाई शपथ....- पास्ट डिस्ट्रिक्ट गवर्नर एमजेएफ लायन डॉ. आर.के. चौरसिया ने संस्थापन अधिकारी के रूप में तीनों क्लबों की कार्यकारिणी को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। वहीं पास्ट डिस्ट्रिक्ट गवर्नर एमजेएफ लायन डॉ. जे.पी.एस. जौहर ने न्यू मेंबर इंडक्शन अधिकारी के रूप में नए सदस्यों का इंडक्शन कराया। कार्यक्रम में एमजेएफ लायन पी.एस. बग्गा एवं जोन चेयरपर्सन डॉ. निहारिका भावसार विशेष अतिथि के रूप में मौजूद रहीं।

समाजसेवा को मिलेगी नई दिशा....

अपने संबोधन में अतिथियों ने कहा कि लायंस क्लब सेवा, सहयोग और मानवता का प्रतीक संगठन है। नई कार्यकारिणी से अपेक्षा है कि वह शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण संरक्षण, जरूरतमंदों की सहायता और जनकल्याण के कार्यों को और अधिक प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाएगी। नवनियुक्त अध्यक्ष डॉ. संतोष जायसवाल ने कहा कि उनकी टीम समाज के हर वर्ग तक सेवा कार्य पहुंचाने के उद्देश्य से नवाचार और समर्पण के साथ कार्य करेगी।

उत्साहपूर्ण माहौल में हुआ आयोजन.....

समारोह का आयोजन होटल आभाश्री के सामने स्थित वृंदावन गार्डन में हुआ। कार्यक्रम में लायंस क्लब बैतूल सिटी के सचिव अनिल दुबे एवं कोषाध्यक्ष शिशिर चौधरी, लायंस क्लब महक की सचिव कीर्ति चंदेल एवं कोषाध्यक्ष संगीता गुप्ता तथा लायंस क्लब अमिगोस के सचिव नीलराज पगारिया एवं कोषाध्यक्ष हिमांशी घोटे सहित तीनों क्लबों के पदाधिकारी, सदस्य और शहर के अनेक गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। पूरे आयोजन में सेवा भावना, संगठनात्मक एकता और सामाजिक दायित्व का संदेश प्रमुखता से दिखाई दिया।

हजरत गौरी शाह की ऐतिहासिक मजार बागरातवा में तोड़फोड़ करने वाले आरोपी को सलाखों के पीछे किया माखननगर पुलिस ने

सोहागपुर। सोहागपुर से 39 किलोमीटर दूर हज़रत गोरी शाह की ऐतिहासिक मजार बागरातवा में तोड़-फोड़ करने वाले आरोपी को सलाखों के पीछे किया माखननगर पुलिस ने। विगत 5 जुलाई को इस ऐतिहासिक मजार में तोड़-फोड़ की घटना से पूरे नर्मदापुरम जिले सनसनी फ़ैल गई थी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों एसडीओ पुलिस संजू चौहान सोहागपुर, नगर निरीक्षक कंचनसिंह माखन नगर,नगर निरीक्षक गिरीश त्रिपाठी सोहागपुर आदि एवं फोरेंसिक विशेषज्ञों ने जांच की थी। घटना की गम्भीरता के कारण पुलिस अधीक्षक नर्मदापुरम श्री साईकृष्णा एस.थोटा एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री अभिषेक राजन एवं अनुविभागीय अधिकारी सोहागपुर श्री संजू चौहान के निर्देश एवं मार्गदर्शन में थाना प्रभारी माखननगर के नेतृत्व टीम गठित की गई थी। पुलिस ने बताया कि

दिनाँक 05 जुलाई 2026 को फरियादी सलीम शाह पिता बाबू शाह उम्र 50 साल निवासी पठान चौक सेमरी हरचंद सोहागपुर के

सूचना दी कि बागरातवा के पास बनी हजरत गौरी शाह बादशाह की मजार मे अज्ञात व्यक्ति के द्वारा धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाने की नियत से मजार की रेलिंग तोडने एवं चादर ,कुरान शरीफ ,बगैरह फेंकने की रिपोर्ट माखन नगर पुलिस थाने में की थी।

थाना माखननगर ने अज्ञात आरोपी के विरूध्द अपराध क्र.- 487/26 धारा - 298 बी.एन.एस. का पंजीबध्द कर विवेचना मे लिया था । मामले की विवेचना के दौरान संकलित साक्ष्य के आधार पर आरोपी अमजद उर्फ गोंगा पिता नियामत अली उम्र 35 साल निवासी टांडा मोहल्ला माखन नगर को माखन नगर पुलिस ने अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की गई। उसके द्वारा बताया गया कि शराब पीने का आदी है ।तथा आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने से घटना दिनाँक को शराब पीने के लिये रूपये नहीं होने के कारण मजार में दानपात्र , चादर, कुरान मे रूपये तलाशने पर नहीं मिलने पर दूषित मानसिकता के कारण मजार की रेलिंग को तोड़ना तथा मजार की चादर व कुरान को साइड मे फैकना एवं बैटरी चोरी करने की घटना स्वीकार किया गया । आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष किया गया। आरोपी को माननीय न्यायालय के आदेश से जेल भेज दिया गया । पुलिस ने आगे बताया कि आरोपी के विरुद्ध माखन नगर थाने में का आदतन अपराधी है ।उसके विरूद्ध 24 अपराध पंजीबध्द है।

इस मामले में पुलिस टीम के अनुविभागीय अधिकारी सोहागपुर श्री संजू चौहान , थाना प्रभारी निरीक्षक कंचनसिंह ठाकुर , उपनिरीक्षक आकाशदीप पचाया , सहायक उपनिरीक्षक वीरेन्द्र शुकाल, प्रधान आरक्षक 674 कैलाश , आरक्षक 37 गजेन्द्र चौहान आरक्षक 858 मनीष कपाले , आरक्षक 588 अर्जुन , आरक्षक 795 रविन्द्र , आरक्षक 390 रोहित , आरक्षक 346 राहुल पवार आदि की सराहनीय भूमिका रही ।

पिछड़ा वर्ग ओबीसी को दें 27 प्रतिशत आरक्षण 20जुलाई को करेंगे विधानसभा का घेराव

सोहागपुर। श्री चंदन कुशवाहा के निवास पर पिछड़ा वर्ग (ओबीसी)महासभा के तत्वावधान में बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में चर्चा हुई कि पिछड़ा वर्ग को कमजोर करने के लिए 27%आरक्षण को 13% सरकार ने किया गया है। इस ओबीसी पिछड़ा वर्ग को पुनः 27% करवाने करने का निर्णय लिया गया। जिसमें समस्त पिछड़ा वर्ग अपनी मांग को पूरा करवाने के लिए 20 जुलाई 2026 को विधानसभा घेराव करेंगे । इस घेराव में सभी महासभा के सदस्यों को अधिक से अधिक संख्या में प्रदेश कार्यालय द्वारिकापुरी कालोनी अशोक नगर भोपाल में इकट्ठा होना है ।इस महासभा में ओबीसी महासभा के प्रदेश उपाध्यक्ष श्री मदन पटेल ,जिला

अध्यक्ष राजा भैया पटेल, नगर अध्यक्ष कमलेश मालवीय प्रजापति , रामबाबू सराठे, ओ पी पटेल ,कुशवाहा समाज जिला अध्यक्ष मालक जी कुशवाहा, प्रदीप वर्मा सालकराम कुशवाहा, डॉ सतीश कुशवाहा ,विष्णु कुशवाहा, अमित कुशवाहा , पूर्व मोहन कहार , नर्मदा सैनी आदि समाज उपस्थित थे। इस आश्य की जानकारी नगर अध्यक्ष कमलेश कुशवाहा प्रजापति ने दी।

संक्षिप्त समाचार

परिवार और जनसंख्या नियंत्रण का संदेश लेकर निकला प्रचार वाहन

राजगढ़, निप्र। विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर जिला अस्पताल परिसर से जनसंख्या स्थिरीकरण, परिवार कल्याण और स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता का संदेश देने के लिए प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। अभियान का उद्देश्य आमजन को परिवार नियोजन और जनसंख्या संतुलन के प्रति जागरूक करना है। इस अवसर पर डीएचओ-2, डीटीओ, डॉ. मनीष चौहान, डेंटल सर्जन, अस्पताल प्रबंधक डॉ. देवाशीष, डॉ. महेंद्रपाल सिंह सहित स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी, कर्मचारी एवं नागरिक उपस्थित रहे।

5000 पौधे लगाने के अभियान की शुरुआत, 50 पौधों का हुआ रोपण

सुसनेर, निप्र। सुसनेर-डग रोड पर शनिवार दोपहर नगर परिषद द्वारा पौधरोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान पूर्व विधायक राणा विक्रम सिंह, नगर परिषद अध्यक्ष प्रदीप सोनी, भाजपा मंडल अध्यक्ष डॉ. सौरभ जैन सहित जनप्रतिनिधियों और पार्षदों ने 50 पौधे रोपकर पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया। नगर परिषद ने बताया कि अभियान के तहत नगर क्षेत्र में कुल 5000 पौधे लगाए जाएंगे। जनप्रतिनिधियों ने नागरिकों से भी अधिक से अधिक पौधे लगाने और उनकी देखभाल करने की अपील की।

राज्य स्तरीय राज पुरस्कार स्काउट-गाइड, रोवर-रेंजर जांच शिविर का सफलतापूर्वक समापन

मुरैना (निप्र)। भारत स्काउट एवं गाइड, मध्य प्रदेश द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय राज पुरस्कार स्काउट-गाइड, रोवर-रेंजर जांच शिविर का आयोजन 6 जुलाई 2026 से 10 जुलाई 2026 तक संभागीय शासकीय ज्ञानोदय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, महाराजपुर, मुरैना में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। पांच दिवसीय इस राज्य स्तरीय शिविर में मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए स्काउट, गाइड, रोवर, रेंजर एवं यूनिट लीडरों सहित कुल 110 प्रतिभागियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया तथा विभिन्न मूल्यांकन परीक्षाओं में सहभागिता की। शिविर के समापन अवसर पर आयोजित भव्य ग्राउंड कैम्प फायर कार्यक्रम विशेष आकर्षण का केंद्र रहा। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि नगर निगम मुरैना की महापौर श्रीमती शारदा सोलंकी थीं, जबकि अध्यक्षता जिला पंचायत मुरैना के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री कमलेश कुमार भार्गव ने की। विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रदेश उपाध्यक्ष, स्काउट-गाइड मध्य प्रदेश श्री ओ.पी. गुप्ता उपस्थित रहे। शिविर का संचालन सहायक राज्य संगठन आयुक्त श्री मनोज पटेल (इंदौर) एवं जिला संगठन आयुक्त (स्काउट) तथा रोवर लीडर श्री मुकेश कुशवाह के कुशल निर्देशन में किया गया। जिला संगठन आयुक्त स्काउट छिंदवाड़ा श्री नरेंद्र शर्मा, श्री जितेंद्र मंडलोई (देवास), श्रीमती कीर्ति भदौरिया एवं श्रीमती रेखा भदौरिया (भिंड) के नेतृत्व में समस्त गतिविधियां अनुशासित, व्यवस्थित एवं सफलतापूर्वक संपन्न हुईं। सहयोगी अधिकारियों ने जांच प्रक्रिया को निष्पक्ष एवं सुचारु रूप से संपन्न कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। शिविर में प्रतिभागियों की स्काउटिंग एवं गाइडिंग से संबंधित विभिन्न दक्षताओं, नेतृत्व क्षमता, सेवा भावना, प्राथमिक उपचार, गांठें एवं बंधन, मानचित्र अध्ययन, शिविर कौशल, ध्वज शिष्टाचार, सामूहिक जीवन, अनुशासन तथा अन्य विषयों पर व्यावहारिक, लिखित एवं मौखिक परीक्षाएं आयोजित की गईं।

अब प्रत्येक गुम इंसान प्रकरण में अनिवार्य रूप से दर्ज होगी एफआईआर

राजगढ़ (निप्र)। मध्यप्रदेश पुलिस ने गुमशुदा व्यक्तियों की शीघ्र खोज एवं उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए प्रदेश के सभी पुलिस इकाइयों को प्रत्येक गुम इंसान (महिला एवं पुरुष) के प्रकरण में अनिवार्य रूप से एफआईआर पंजीबद्ध करने के निर्देश जारी किए हैं। इस संबंध में पुलिस मुख्यालय द्वारा प्रदेश के सभी पुलिस आयुक्तों, पुलिस महानिरीक्षकों, उप पुलिस महानिरीक्षकों एवं पुलिस अधीक्षकों को विस्तृत निर्देश प्रेषित किए गए हैं। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2012 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वाराबचपन बचाओ आंदोलन बनाम भारत सरकारप्रकरण में दिए गए निर्देशों के अनुसार गुम नाबालिग बच्चों के मामलों में एफआईआर दर्ज करने की व्यवस्था लागू की गई थी। अब हाल ही में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वाराजी. गणेश बनाम तमिलनाडु राज्य एवं अन्य में दिए गए निर्णय के अनुसार प्रत्येक गुम इंसान, चाहे वह महिला हो या पुरुष, के मामले में भी अनिवार्य रूप से एफआईआर दर्ज किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उक्त निर्देशों के अनुपालन में पुलिस मुख्यालय, मध्यप्रदेश द्वारा प्रदेश के समस्त पुलिस अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि प्रत्येक गुमशुदगी की सूचना प्राप्त होते ही तत्काल एफआईआर पंजीबद्ध कर विधि सम्मत जांच प्रारंभ की जाए तथा गुम व्यक्ति की शीघ्र तलाश हेतु सभी आवश्यक वैधानिक एवं तकनीकी उपाय सुनिश्चित किए जाएं।

ब्यावरा में नीम, पीपल जैसे राज्यमंत्री ने 50 पौधे लगाए

बोले- कीटनाशकों से जमीन खराब हो रही और खेत में जीव-जंतु मर रहे

ब्यावरा, निप्र। ब्यावरा के चारपुरा गांव में शनिवार को हरियाली महोत्सव के तहत पौधे लगाने का कार्यक्रम हुआ। इसमें राज्य मंत्री नारायण सिंह पंवार ने लवकुश मंदिर और सरकारी प्राइमरी स्कूल के मैदान में नेताओं, अफसरों, स्कूली बच्चों और गांव वालों के साथ मिलकर 50 से अधिक पौधे रोपे। इनमें नीम, पीपल, अमरूद, आम और पारस पीपल जैसे पेड़ शामिल हैं।

मंत्री पंवार ने लोगों को समझाते हुए कहा कि पेड़ लगाना जितना ज़रूरी है, उससे कहीं अधिक उनको बचाना और बड़ा करना जरूरी है। उन्होंने चारपुरा के लोगों की तारीफ की कि वे पर्यावरण को लेकर जागरूक हैं। मंत्री ने हर व्यक्ति से साल में कम से कम एक पौधा लगाने और उसे पेड़ बनने तक संभालने का वादा लेने को कहा। उन्होंने कहा कि पीपल, बरगद, नीम और तुलसी सिर्फ पेड़ नहीं हैं, बल्कि हमारी आस्था और परंपरा से जुड़े हैं, जो हमें ऑक्सीजन और दवाइयां देते हैं।

केमिकल वाली खेती पर जताई चिंता : मंत्री पंवार ने आजकल हो रही पेड़ों की अंधाधुंध कटाई और बढ़ते प्रदूषण पर चिंता जताई। उन्होंने खास तौर पर खेती में इस्तेमाल होने वाली केमिकल खादों और कीटनाशकों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इससे जमीन खराब हो रही है, खेत के मददगार जीव-जंतु मर रहे हैं और इंसानों की सेहत भी बिगड़ रही है। उन्होंने किसानों से अपील की कि वे गोबर की खाद, केंचुआ खाद (वर्मी कम्पोस्ट) और जीवामृत का इस्तेमाल कर के प्राकृतिक खेती अपनाएं, जिससे लागत भी कम आएगी और जमीन भी बची रहेगी। इस दौरान दिलवर यादव, कल्याण गुर्जर, मोहन कुशवाह और पवन कुशवाह सहित कई लोग मौजूद रहे।

नए एसडीएम दफ्तर में भी हुआ पौधारोपण : दूसरी तरफ, ब्यावरा के नए एसडीएम और तहसीलदार दफ्तर के मिले-जुले परिसर में भी हरियाली महोत्सव मनाया गया। यहां राज्य मंत्री नारायण सिंह पंवार और विधायक मोहन शर्मा ने पौधे लगाए। दोनों ने मिलकर नए दफ्तर की व्यवस्थाएं भी देखीं। मंत्री ने लोगों से 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान से जुड़ने की अपील की और कहा कि एक ही जगह सारे सरकारी दफ्तर होने से जनता को भटकना नहीं पड़ेगा।

सरकार हर क्षेत्र में कर रही है काम : विधायक मोहन शर्मा ने कार्यक्रम में कहा कि हमारी सरकार सड़क, पढ़ाई, इलाज और सरकारी बिल्डिंगों को बेहतर बनाने के लिए हर क्षेत्र में तेजी से विकास कर रही है। इस मौके पर मंडल अध्यक्ष देवेंद्र सिंह परमार, रमेश मालवीय और एसडीएम सुशील कुमार सहित कई अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे।

राजगढ़ में 20 वर्षीय युवक ने फांसी लगाई, मौत

घर में फंदे पर लटका मिला युवक, डॉक्टरों ने मृत घोषित किया; पोस्टमार्टम के बाद अंतिम संस्कार

राजगढ़, निप्र। राजगढ़ की भंडारा गली में रहने वाले 20 वर्षीय युवक ने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। परिजन उसे गंभीर हालत में शनिवार तड़के जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलने पर पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, मृतक की पहचान आदित्य सिंह भाटी (20) के रूप में हुई है। वह घर में हाफ लोअर और बनियान पहने फंदे पर लटका मिला। घटना का पता चलते ही परिजन उसे सुबह करीब चार बजे जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी।

पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंपा शव : सूचना मिलने पर पुलिस जिला अस्पताल पहुंची और आवश्यक कार्रवाई के बाद मर्ग कायम किया। शनिवार सुबह करीब 10 बजे जिला अस्पताल में शव का पोस्टमार्टम कराया गया। इसके बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। सुबह करीब 11 बजे भंडारा गली स्थित निवास से आदित्य की अंतिम यात्रा निकाली गई। बांसवाड़ा श्मशान घाट में परिजनों, रिश्तेदारों और परिचितों की मौजूदगी में उसका अंतिम संस्कार किया गया। फिलहाल युवक द्वारा आत्महत्या किए जाने का कारण सामने नहीं आया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि जांच और परिजनों के बयान के बाद ही आत्महत्या के कारणों का खुलासा हो सकेगा।

मरीजों के लिए प्रबंधक ने 12वीं बार रक्तदान किया

राजगढ़, निप्र। थैलेसीमिया से पीड़ित मरीज गोविंद राजपूत की जरूरत को देखते हुए जल निगम के प्रबंधक सचिन दांगी ने जिला अस्पताल पहुंचकर स्वैच्छिक रक्तदान किया। उन्होंने जिला अस्पताल के ब्लड बैंक में अपने जीवन का 12वीं बार रक्तदान कर मरीज के उपचार में सहयोग दिया। सचिन दांगी ने कहा कि रक्तदान से किसी जरूरतमंद को नया जीवन मिल सकता है, इसलिए स्वस्थ लोगों को नियमित रूप से रक्तदान करना चाहिए।

राजगढ़ और ब्यावरा में हुआ पौधरोपण, ब्रह्मकुमारी संस्था सदस्यों ने रोपे 100 पौधे

राजगढ़, निप्र। सिर्फ पौधे लगाना ही नहीं, उन्हें वृक्ष बनने तक सहेजने का संकल्प ही पर्यावरण संरक्षण की असली शुरुआत है। इसी संदेश के साथ शनिवार को शहर से करीब तीन किलोमीटर दूर ढंड जोड़ स्थित नगर वन में ब्रह्मकुमारीज संस्था के सदस्यों ने 100 पौधों का रोपण किया। वन विभाग के सहयोग से आयोजित इस अभियान में फलदार, छायादार और औषधीय प्रजातियों के पौधे लगाए गए। पौधरोपण के दौरान संस्था प्रमुख मधु दीदी ने कहा कि पेड़ मनुष्य के जीवन के हर पड़ाव से जुड़े हैं। जन्म से लेकर अंतिम यात्रा तक प्रकृति का साथ बना रहता है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवनकाल में कम से कम एक पौधा लगाकर उसे वृक्ष बनने तक उसकी देखभाल की जिम्मेदारी निभानी चाहिए। सुबह करीब साढ़े नौ बजे शुरू हुआ पौधरोपण अभियान लगभग दो घंटे तक चला। इस दौरान आम, जामुन, अमरूद, आंवला, नीम, पीपल सहित कई फलदार एवं छायादार पौधे लगाए गए। कार्यक्रम में मौजूद ब्रह्मकुमारीज संस्था के सदस्यों ने पौधरोपण को केवल एक अभियान नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित पर्यावरण की नींव बताया। सभी ने पौधों की नियमित देखभाल का संकल्प भी लिया। अभियान में डिप्टी रेंजर राजू गुर्जर, रणजीत गुर्जर, समाज सेवी प्रताप सिंह सिसोदिया, ओमप्रकाश गुप्ता, ट्रेनिंग ऑफिसर कपिल गुप्ता, सेवानिवृत्त बैंक प्रबंधक शिवनारायण नामदेव, गिरिराज गुप्ता, रिटायर्ड एसडीओ रमेश चंद्र शर्मा, ब्रह्मा कुमारीज बहने व संस्था से जुड़े अन्य लोग मौजूद थे।

10 मामलों में फरार बदमाश ने किया सरेंडर

सारंगपुर के बोड़ा थाने में माखन सांसी ने छोड़ा अपराध का रास्ता ; 2017 से फरार था

सारंगपुर, निप्र। राजगढ़ जिले के गुलखेड़ी गांव निवासी एक शातिर बदमाश ने पुलिस की समझाइश और जागरूकता अभियानों से प्रभावित होकर अपराध का रास्ता छोड़ दिया है। वर्ष 2017 से करीब 10 अलग-अलग आपराधिक मामलों में फरार चल रहे आरोपी माखन सांसी ने शनिवार को बोड़ा थाने पहुंचकर पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। एसपी अमित तोलानी के मार्गदर्शन में चलाई जा रही इस अनूठी पहल के बाद आरोपी ने समाज की मुख्यधारा से जुड़ने का फैसला किया है।

आबकारी और पुलिस पर हमले सहित 10 गंभीर केस : थाना प्रभारी देवेंद्रसिंह राजपूत ने बताया कि आत्मसमर्पण करने वाले माखन सांसी का पुराना आपराधिक रिकॉर्ड है। उसके खिलाफ विभिन्न थानों में कुल 10 गंभीर मामले दर्ज हैं। इनमें से 5 मामले अवैध शराब की बिक्री और तस्करी (आबकारी अधिनियम) से जुड़े हैं।

इसके अलावा, आपसी मारपीट और विवाद के 3 प्रकरण तथा शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाने, पुलिस टीम पर जानलेवा हमला करने और बलवा करने जैसे संगीन जुर्म में 2 प्रकरण दर्ज हैं। पुलिस लंबे समय से उसकी गिरफ्तारी के प्रयास कर रही थी।

गांवों में लगी पुलिस की चौपालों का दिखा असर : बोड़ा पुलिस क्षेत्र के कड़िया, गुलखेड़ी और हुलखेड़ी जैसे संवेदनशील गांवों में आपराधिक गतिविधियों में लिप्त लोगों को सुधारने के लिए लगातार संवाद कर रही है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, इन गांवों के कुछ युवा और नागरिक देश के अलग-अलग हिस्सों में चोरी, मारपीट, जुआ और मादक पदार्थों की खरीद-फरोख्त जैसे अपराधों में शामिल रहे हैं। पुलिस अब केवल कानूनी कार्रवाई नहीं कर रही, बल्कि गांवों में चौपाल लगाकर युवाओं को सामान्य जीवन जीने के लिए प्रेरित कर रही है। माखन सांसी का आत्मसमर्पण इसी मुहिम का नतीजा है। पुलिस ने अब अन्य फरार आरोपियों से भी सरेंडर कर मुख्यधारा में लौटने की अपील की है।

जनसंख्या दिवस पर कॉलेज में हुई प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता

राजगढ़, निप्र। विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस, शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में वाणिज्य विभाग और राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) के संयुक्त तत्वावधान में वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता आयोजित की गई। प्रतियोगिता में नवप्रवेशित 20 छात्र-छात्राओं ने जनसंख्या, स्वास्थ्य, परिवार कल्याण और सतत विकास से जुड़े 50 प्रश्नों के उत्तर दिए। कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों में जनसंख्या संतुलन और सामाजिक उत्तरदायित्व के प्रति जागरूकता बढ़ाना था। अंत में प्रतिभागियों को भविष्य में भी ऐसे जागरूकता कार्यक्रमों में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित किया गया।

राजगढ़ में शराब के नशे में नदी में कूदा युवक

बोला- अब जीना नहीं चाहता ; राहगीरों ने डूबता देख बाहर निकाल बचाई जान

राजगढ़, निप्र। राजगढ़ जिले के खिलचीपुर गाड़गंगा नदी में शुक्रवार रात एक युवक ने शराब के नशे में आत्महत्या की कोशिश कर दी। वह नदी में कूद गया और डूबने लगा। मौके पर मौजूद लोगों के शोर के बीच एक युवक ने अपनी जान की परवाह किए बिना नदी में छलांग लगा दी। उसने डूब रहे युवक को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। सूचना मिलते ही डायल-112 मौके पर पहुंची और युवक को थाने ले गई।

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, नदी में कूदने वाला युवक खुद को कमल वर्मा निवासी कुंडीबे बता रहा था। वह नशे की हालत में बार-बार कह रहा था कि अब वह जीना नहीं चाहता। पूछताछ में उसने बताया कि खिलचीपुर के रहने वाले एक व्यक्ति कल्लू भाई से उसका पैसों का लेन-देन था। उसका आरोप है कि विवाद के बाद उसकी बाइक रख ली गई। इसी बात से परेशान होकर उसने शराब पी और गाड़गंगा नदी पहुंचकर छलांग लगा दी।

पुलिस ने थाने ले जाकर समझाइश दी युवक को डूबता देख मुकेश मोगिया ने बिना देर किए नदी में छलांग लगा दी। कुछ देर की मशक्कत के बाद उसने युवक को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। घटना के बाद नदी किनारे बड़ी संख्या में लोग एकत्र हो गए।

सूचना मिलने पर डायल-112 पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को थाने ले गई। पुलिस के अनुसार युवक शराब के नशे में था। इसलिए रात में उसके परिजनों को थाने बुलाया गया और समझाइश के बाद युवक को उनके सुपुर्द कर दिया गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि मुकेश मोगिया समय रहते नदी में नहीं कूदते, तो यह घटना जानलेवा साबित हो सकती थी। उनकी सतर्कता और साहस से एक युवक की जान बच गई।

3 लोगों पर तलवार से हमला करने वाला गिरफ्तार

बोडा पुलिस ने जेल भेजा, आरोपी ग्राम आंकखेड़ी का रहने वाला

सारंगपुर, निप्र। बोडा थाना क्षेत्र में पुरानी दुश्मनी के चलते तलवार से जानलेवा हमला करने वाले फरार आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस हमले में तीन लोग घायल हुए थे, जिनमें से 64 साल के बुजुर्ग भागीरथ भिलाला की हालत गंभीर है और उनका इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है।

पुलिस ने शनिवार को आरोपी को कोर्ट में पेश किया। जहां से उसे जेल भेज दिया गया है।

यह घटना 7 जुलाई की है। ग्राम आंकखेड़ी कला के रहने वाले भागीरथ भिलाला (64 वर्ष) ने बोडा थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि गांव के ही छगनलाल रुहेला ने पुरानी रंजिश के कारण उन्हें जान से मारने की नीयत से तलवार से हमला कर दिया। इस हमले में भागीरथ के साथ-साथ दो अन्य लोग भी घायल हुए थे। भागीरथ की गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें तुरंत राजगढ़ जिला अस्पताल रेफर किया गया था, जहां वे अभी भी भर्ती हैं। छगनलाल के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं और एससी-एसटी एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया। पुलिस अफसरों का कहना है कि गंभीर अपराध करके फरार होने वाले अपराधियों को पकड़ने का यह अभियान आगे भी जारी रहेगा।

राष्ट्रीय संत सुधा सागर महाराज ब्यावरा पहुंचे, प्रवचन में कहा- सिर्फ पूजा कर लेना ही काफी नहीं, सच्ची श्रद्धा से ही फल मिलता

ब्यावरा, निप्र। ब्यावरा नगर में शनिवार को राष्ट्रीय संत मुनि पुंगव सुधा सागर महाराज का आगमन हुआ। उनके ससंघ नगर प्रवेश करते ही पूरा माहौल धर्ममय हो गया। जैन समाज के लोगों ने ढोल-बैंड के साथ गुरुदेव का भव्य स्वागत किया। रास्ते में कई जगहों पर श्रद्धालुओं ने उनके पैर धोकर (पादपूजन) आशीर्वाद लिया। नगर के जैन मंदिर में भगवान अतिशयकारी पार्श्वनाथ के सामने भव्य अभिषेक और शांतिधारा का आयोजन किया गया। इस मौके पर राष्ट्र संत सुधा सागर महाराज ने अपने प्रवचन में कहा कि केवल पूजा कर लेना ही काफी नहीं है।

शास्त्रों में लिखी गई विधि और सच्ची श्रद्धा के साथ किया गया अभिषेक और शांतिधारा ही सबसे ज्यादा आध्यात्मिक फल देता है। उन्होंने मन, वचन और कर्म की पवित्रता के साथ भगवान की भक्ति करने और संयम, सेवा व सदाचार के मार्ग पर चलने की बात कही।

धर्मेंद्र और ऋषभ जैन परिवार को मिला आहार कराने का सौभाग्य मुनि श्री ने ब्यावरा में विराजमान भगवान पार्श्वनाथ की महिमा बताते हुए कहा कि आज के भौतिकवादी युग में इंसान बाहरी सुख-सुविधाओं के पीछे भाग रहा है, जबकि असली सुख आत्मा की शांति में है। इस दौरान उन्होंने श्रद्धालुओं के मन में उठ रहे सवालों और शंकाओं का समाधान भी किया। इस खास मौके पर पूज्य सुधा सागर महाराज को आहार कराने का सौभाग्य ब्यावरा के धर्मेंद्र जैन और ऋषभ कुमार जैन परिवार को मिला।

देवास के लिए किया विहार, चातुर्मास के लिए इंदौर की ओर प्रस्थान दोपहर करीब 3:30 बजे, राष्ट्र संत मुनि पुंगव सुधा सागर महाराज ससंघ ने देवास के लिए विहार किया।

वे बीनागंज से इंदौर की तरफ चातुर्मास करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। गुरुदेव के विहार के समय भी बड़ी संख्या में भक्त उनके दर्शनों के लिए रास्तों में खड़े रहे और उन्हें भावभीनी विदाई दी।

गांव में लगा बिजली सेवा शिविर, 35 उपभोक्ताओं की केवाईसी हुई

झाड़ला, निप्र। विद्युत वितरण केंद्र झाड़ला ने 'संपर्क अभियान-2026 : विद्युत संबंधी सेवाएं आपके द्वार' के तहत ग्राम मानपिछोड़ी में बिजली सेवा शिविर आयोजित किया। शिविर में 35 उपभोक्ताओं की समग्र ई-केवाईसी की गई। साथ ही दो घरेलू बिजली कनेक्शन और ?5 योजना के तहत चार नए कृषि पंप कनेक्शनों के लिए सर्वे एवं आवश्यक कार्रवाई की गई। ग्रामीणों ने झूलते बिजली तार और नई केबल बिछाने की मांग भी रखी। विभागीय अधिकारियों ने शिकायतों के निराकरण का आश्वासन देते हुए उपभोक्ताओं को विभिन्न विद्युत सेवाओं और योजनाओं की जानकारी भी दी।

पर्यावरण

प्रयाग पाण्डे
लेखक उत्तराखण्ड के नैनीताल निवासी वरिष्ठ स्तंभकार हैं।

दूरदर्शी राजनेता थे वन महोत्सव के प्रणेता

आज से करीब साढ़े सात दशक पूर्व जब पर्यावरण अपघटन, ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन और प्रदूषण बात-बहस और चिंता का विषय नहीं थे। तब भारत वनों और वन संपदा के मामले में आज के बनिस्बत बहुत समृद्ध था। देश को गुलामी की जंजीरों से मुक्त हुए तीन वर्ष का वक्त भी नहीं बीता था। उस समय भारत के तत्कालीन नेतृत्व के सामने पर्यावरण के बजाय देश की दूसरी अनेक ज्वलंत समस्याएं चुनौती बनी हुई थीं। उस समय की राजनीतिक परिस्थितियों में देश की तात्कालिक समस्याओं के मुकाबले पेड़ और पर्यावरण के मुद्दे गौण थे। बावजूद इसके हमारे दूरदर्शी राजनेता पर्यावरण को लेकर बेहद संवेदनशील थे। उन्हें भविष्य में पेश आने वाली पर्यावरणीय समस्याओं का भान था। उन्हीं में से एक राष्ट्रवादी नेता थे- कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी। श्री मुंशी की दीर्घकालिक सोच, पर्यावरण के प्रति भारतीय संस्कृति की समझ, संवेदनशीलता और पहल का ही सुफल है- ' महोत्सव।'

कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी अग्रणीय पंक्ति के स्वाधीनता संग्राम सेनानी, प्रख्यात साहित्यकार, शिक्षाविद और श्रेष्ठ राजनेता थे। वे संविधान सभा के सदस्य थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में बनी संविधान सभा की प्रारूप समिति के महत्वपूर्ण सदस्य भी रहे थे। 13 मई,1950 को कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी भारत के तीसरे कृषि मंत्री बने। उन्होंने वन और पर्यावरण के संरक्षण एवं संवर्धन के प्रति जन-जागरूकता पैदा करने की मंशा से वृक्षारोपण अभियान चलाने का मन बनाया। भारत सरकार के कृषि एवं खाद्य मंत्री के रूप में कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी के कार्यकाल के दौरान 1950 में पर्यावरण संरक्षण के लिए वृक्षारोपण का राष्ट्रव्यापी अभियान प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया था। जिसको नाम दिया गया-'वन महोत्सव।' एक जुलाई, 1950 को दिल्ली के राजघाट से वन महोत्सव का शुभारंभ हुआ।

आधुनिक भारत में प्रकृति और पर्यावरण के संरक्षण के लिए वन महोत्सव जैसे राष्ट्रव्यापी अभियान का शुभारंभ प्रथमदृष्ट्या अभिनव प्रयोग प्रतीत होता है । वस्तुतः यह विचार पेड़, पर्यावरण और प्रकृति के संरक्षण एवं संवर्धन को लेकर भारत की प्राचीन संस्कृति और अवधारणा से प्रेरित था। भारत की प्राचीन संस्कृति में वृक्ष रोपण की परंपरा बहुत पुरानी है। हमारे वेदों, पुराणों, उपनिषदों और अन्य धर्म ग्रंथों में पौधों, वृक्षों और वन्यप्राणियों के महत्व का विस्तारपूर्वक वर्णन मिलता है। वराह पुराण में स्वर्ग प्राप्ति के लिए नियमित वृक्षारोपण की सलाह दी गई है। मत्स्य पुराण और पद्मपुराण में भी वृक्ष महोत्सव का वर्णन हुआ है। मत्स्य पुराण में एक वृक्ष रोपण को दस पुत्रों के समान बताया गया है। प्रकृति को देव तुल्य माना गया है। प्रकृति की विभिन्न संरचनाओं में देवी - देवताओं की संकल्पना की गई है।

2 जून, 1952 को कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी अविभाजित उत्तर प्रदेश के राज्यपाल बने। 1953 में नैनीताल प्रवास के दौरान उन्होंने ही नैनीताल के राजभवन में वन महोत्सव की शुरूआत की थी। वन महोत्सव का शुभारंभ करते हुए श्री मुंशी ने राजभवन परिसर, नैनीताल में बांज का पौधा लगाया था। कालांतर में श्री मुंशी द्वारा रोपा गया पौधा राजभवन परिसर में मौजूद अनगिनत दरख्तों का हिस्सा बन गया। हर साल वन महोत्सव मनाने की परंपरा का निर्वहन होता रहा, लेकिन किसी ने भी वन महोत्सव के प्रणेता द्वारा लगाए गए बांज के पौधे की सुध लेने की आवश्यकता नहीं समझी।

पृथक उत्तराखंड राज्य बनने के करीब पंद्रह वर्ष बाद 2015 में डॉक्टर कृष्ण कांत पॉल उत्तराखंड के राज्यपाल बने। चूंकि डॉक्टर पॉल पर्यावरण के प्रति बेहद संवेदनशील और प्रकृति प्रेमी हैं। जब डॉक्टर पॉल नैनीताल प्रवास में आए तो उन्होंने श्री मुंशी द्वारा राजभवन परिसर में लगाए गए बांज के वृक्ष को खोजने में गहरी दिलचस्पी दिखाई। लोक निर्माण विभाग एवं वन विभाग के अफसरों को इस पेड़ को खोजने के आदेश दिए। लंबी -चौड़ी कसरत के बाद अंततः श्री मुंशी द्वारा लगाए गए बांज के पेड़ की शिनाख्त कर ली गई। तत्कालीन राज्यपाल डॉक्टर पॉल के आदेश पर इस वृक्ष में विधिवत सूचना पट्टिका लगा दी गई थी। श्री मुंशी द्वारा करीब तिहत्तर साल पहले नैनीताल के राजभवन परिसर में लगाया गया बांज का वह नन्हा पौधा अब दरख्त बन गया है और हमारे तत्कालीन राजनीतिक नेतृत्व की पर्यावरण संरक्षण के प्रति अटूट प्रतिबद्धता और दूरदर्शिता की कहानी बयां कर रहा है।

आज जबकि संपूर्ण विश्व पर्यावरण अपघटन से उपजी अनेक समस्याओं से जूझ रहा है। लगातार हो रहे वन विनाश से पर्यावरण में असंतुलन पैदा हो गया है। अनियंत्रित एवं असंयोजित विकास, नगरीकरण और बढ़ती आबादी के कारण नित बढ़ते ध्वनि, वायु, मृदा, जल एवं स्थल प्रदूषण से पर्यावरणीय संकट बढ़ा है। पृथ्वी के सभी जीवधारी ग्लोबल वॉर्मिंग से उत्पन्न समस्याओं से जूझ रहे हैं। वनोन्मूलन के कुप्रभावों से बचने और पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन के लिए सघन वृक्षारोपण की वकालत की जा रही है, लेकिन जंगलात महकमे ने पर्यावरण संरक्षण के इस महत्वपूर्ण अभियान को महज रस्म अदायगी बना दिया है। पिछले करीब साढ़े सात दशक से वन महोत्सव के दौरान लाखों हेक्टेयर भूमि में पौधे रोपे जाने के दावे किए जाते रहे हैं। वृक्षारोपण के नाम पर सरकारी खजाने से बेहिसाब धन खर्चा जाता रहा है, लेकिन वृक्षारोपण अभियान की जमीनी कामयाबी और उपलब्धियों की पड़ताल करने की जहमत नहीं उठाई जाती है।

हर साल बरसात में जुलाई के महीने वन महोत्सव मनाया जाता है। पौधारोपण होता है। जंगलात विभाग की फाइलों में झक हरियाली छा जाती है। गर्मी के मौसम में अक्सर जंगलों में आग लग जाया करती है। वृक्षारोपण की जमीनी असलियत दावाग्नि की लपटों की ओट में छिप जाती है। नतीजतन जिन स्थानों में पिछले वर्षों वन महोत्सव मनाया गया, उनमें से अधिकतर जगहें वृक्ष विहीन ही नज़र आती हैं। प्रकृति और पर्यावरण संरक्षण के लिए वन महोत्सव जैसे व्यापक जन सहभागिता वाले कार्यक्रम का शुभारंभ करने वाले राजनेताओं का नज़रिया भले ही दूरगामी रहा हो, लेकिन अब वन महोत्सव अन्य सरकारी कार्यक्रमों जैसा ही उपक्रम बन कर रह गया है। पर्यावरण अपघटन से उपजी समस्याओं से निपटने के लिए वन महोत्सव जैसे राष्ट्रव्यापी अभियानों की अब तक की उपलब्धियों और विफलताओं का तटस्थ आकलन किया जाना आवश्यक है। अन्यथा वन महोत्सव भी मात्र औपचारिकता बन कर रह जाएगा।

किनारे पर घर बसा लो..., कभी खुद को समंदर बताने वाले नरोत्तम मिश्रा के बदले सुर

समंदर किनारे घर बसा लें, कोई दिक्कत नहीं है

भोपाल (नप्र)। समंदर का पानी उतरता देखकर किनारे पर घर मत बना लेना, मैं वापस लौटकर आऊंगा... साल 2023 के विधानसभा चुनाव में हार के बाद कार्यकर्ताओं के सामने यह डायलॉग मारने वाले पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के सुर अब पूरी तरह बदल चुके हैं। दतिया उपचुनाव में टिकट कटने और सीएम हाउस में सीक्रेट मीटिंग के बाद अब वे कहते नजर आ रहे हैं, समंदर किनारे घर बसा लें, कोई दिक्कत नहीं है।

सीएम हाउस में मोहन यादव, संगठन महामंत्री अजय जामवाल, प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल से सीक्रेट मीटिंग के बाद जब नरोत्तम मिश्रा बाहर निकले तो तेवर और महौल बदल चुका था। कार्यकर्ताओं से शांति की अपील के बाद उनका एक और वीडियो खूब वायरल हो रहा है। मीडिया के समंदर किनारे घर मत बना लेना वाले डायलाग पर पूछने पर उनका कहना था। अब बड़े आराम से घर बना लें, क्या दिक्कत है...।

सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे वीडियो में वे उन्होंने बताया कि कार्यकर्ताओं को मना लेंगे। सब अपने हैं। भाजपा प्रत्याशी आशुतोष तिवारी के चुनाव प्रचार को लेकर कहा कि, मन से डूब के काम करेंगे पार्टी प्रत्याशी को जिताएंगे। सब मिलकर काम करेंगे। मीडिया के एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि, अब समंदर किनाने घर बना लें आराम से...आराम से घर बनाएं, किसी को कोई दिक्कत नहीं।

दतिया में टिकट कटने पर समर्थकों का उग्र प्रदर्शन

दरअसल, दतिया उपचुनाव में बीजेपी से टिकट न मिलने के बाद नरोत्तम मिश्रा के समर्थक बेहद नाराज हो गए। टिकट कटने की खबर आते ही दतिया में उनके समर्थकों ने एनएच-44 जाम कर दिया। रात भर धरना-प्रदर्शन किया। बाजार बंद करा दिए गए और स्थिति इस कदर बिगड़ी कि उग्र भीड़ ने पुलिस पर पथराव भी कर दिया। हालात को काबू में करने के लिए पुलिस और प्रशासन को आंसू गैस के गोले तक दागने पड़े।

नरोत्तम ने कहा- दतिया में चुनाव प्रचार करूंगा

दतिया में हुए इस भारी बवाल और हिंसा को देखते हुए प्रशासन ने क्षेत्र में तुरंत धारा 163 लागू कर दी। वहीं, समर्थकों के इस उग्र प्रदर्शन के बाद पुलिस ने 28 नामजद सहित करीब दो सैकड़ा भाजपा कार्यकर्ताओं पर एफआईआर दर्ज की है। वहीं नरोत्तम मिश्रा ने भोपाल पहुंचकर कार्यकर्ताओं से शांति बनाए रखने की अपील की। उन्होंने अपने समर्थकों को सख्त हिदायत दी कि वे किसी भी तरह की कानून-व्यवस्था की स्थिति या परेशानी पैदा न करें।

समंदर का टिकट कट गया, सोशल मीडिया पर तंज

नरोत्तम मिश्रा के इस नए बयान के बाद सोशल मीडिया पर लोग जमकर चुटकी ले रहे हैं। यूजर्स का कहना है कि जो नेता कभी खुद को समंदर बताकर वापस लौटने का दावा करता था, आज वह खुद अपना फेंका हुआ बयान समेट रहा है। इंटरनेट पर लोग लिख रहे हैं, अब किनारे पर घर बसा लो, क्योंकि समंदर का टिकट कट गया है। बहरहाल, टिकट कटने के बाद नरोत्तम मिश्रा का यह बैकफुट पर आना और कार्यकर्ताओं को घर बसाने की सलाह देना प्रदेश के सियासी गलियारों में भारी चर्चा का विषय बना हुआ है।

दिल्ली से ग्वालियर सिर्फ 4 घंटे में 120 की स्पीड से दौड़ेंगी गाड़ियां

4613 करोड़ के नए सुपरवे से तीन राज्यों की बदल जाएगी किस्मत

ग्वालियर (नप्र)। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच का सफर अब पहले जैसा नहीं रहेगा। एनएचएआई ने आगरा से ग्वालियर के बीच 88 किलोमीटर लंबे एक हाई-स्पीड 6-लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे पर काम तेज कर दिया है, जो आने वाले समय में 8 लेन का किया जा सकेगा।

इस नए एक्सेस-कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे के चालू होने से आगरा से ग्वालियर की दूरी महज 75 से 80 मिनट में सिमट जाएगी, जबकि दिल्ली से ग्वालियर का सफर सिर्फ 4 घंटे का रह जाएगा। वर्तमान में संकरी सड़कों और एनएच-44 पर भारी जाम के कारण इस यात्रा में 6 से 7 घंटे का वक्त बर्बाद होता है।

बीहड़ और चंबल सेंचुरी से गुजरेगा रूट- लगभग 4,613 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाला यह एक्सप्रेसवे बेहद चुनौतीपूर्ण रास्तों से गुजरेगा। रूट का एक बड़ा हिस्सा चंबल नदी और उसके बीहड़ों के पास से होकर जाएगा। यात्रा को सुगम बनाने के लिए इस पूरे मार्ग में 8 बड़े पुल, 23 छोटे पुल, 6 फ्लाईओवर्स और एक रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण किया जा रहा है। चंबल वाइल्डलाइफ सेंचुरी के संवेदनशील क्षेत्र को देखते हुए यहां विशेष ग्रीन बेल्ट और जानवरों के लिए अंडरपास भी बनाए जाएंगे।

इन तीन राज्यों के 63 गांवों को होगा सीधा फायदा- यह एक्सप्रेसवे आगरा के देवरी गांव से शुरू होकर ग्वालियर बाईपास के पास सुसेरा गांव पर समाप्त होगा। इसके दायरे में उत्तर प्रदेश (आगरा), राजस्थान (धौलपुर) और मध्य प्रदेश (मुरैना व ग्वालियर) के कुल 63 गांव आ रहे हैं। इस परियोजना के लिए 93 फीसदी से अधिक भूमि का अधिग्रहण पहले ही पूरा किया जा चुका है और एनएचएआई ने 2027-2028 तक इसे पूरी तरह तैयार करने का लक्ष्य रखा है। मुरैना के पास इसका इंटरचेंज अटल प्रगति पथ से होगा, जिससे यह कोटा के पास दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे ग्रिड से भी जुड़ जाएगा।

आईएसएसएफ वर्ल्ड कप शॉटगन में जीता स्वर्ण, मनीषा भी टॉप-10 में

इटली में एमपी की नीरू का गोल्डन निशाना

भोपाल(नप्र)। मध्यप्रदेश राज्य शूटिंग शॉटगन अकादमी की खिलाड़ी नीरू ढांडा ने इटली के लोनाटो में आयोजित ट्वस्स्त्र शॉटगन वर्ल्ड कप में स्वर्ण पदक जीतकर भारत और मध्यप्रदेश का नाम रोशन किया है। 3 से 13 जुलाई तक आयोजित इस प्रतियोगिता में दुनिया के कई देशों के निशानेबाजों के बीच नीरू ने शानदार प्रदर्शन करते हुए गोल्ड मेडल अपने नाम किया। वहीं, अकादमी की दूसरी खिलाड़ी मनीषा ने भी बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए शीर्ष-10 में जगह बनाई।

कठिन मुकाबले में जीता गोल्ड- विश्व शूटिंग कैलेंडर की प्रमुख प्रतियोगिताओं में शामिल इस वर्ल्ड कप में नीरू ढांडा ने पूरे मुकाबले के दौरान सटीक निशाने और शानदार प्रदर्शन से स्वर्ण पदक जीता। उनकी इस सफलता को मध्यप्रदेश की खेल अकादमियों के बेहतर प्रशिक्षण का परिणाम माना जा रहा है।

मनीषा भी टॉप-10 में- अकादमी की खिलाड़ी मनीषा ने भी प्रतियोगिता में अच्छा प्रदर्शन करते हुए दसवां स्थान हासिल किया। इसे भविष्य के लिए सकारात्मक उपलब्धि माना जा रहा है।

खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने नीरू ढांडा को स्वर्ण पदक जीतने और मनीषा को उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि दोनों खिलाड़ियों ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश और देश का गौरव बढ़ाया है। यह उपलब्धि खिलाड़ियों की मेहनत, प्रशिक्षकों के मार्गदर्शन और खेल विभाग की बेहतर प्रशिक्षण व्यवस्था का परिणाम है।

खेल एवं युवा कल्याण विभाग के संचालक अंशुमान यादव, संयुक्त संचालक बी.एस. यादव, शूटिंग अकादमी के प्रशिक्षकों और सहयोगी स्टाफ के मार्गदर्शन को भी इस सफलता का श्रेय दिया गया है।

11 साल से फरार सांसी गैंग का बदमाश गिरफ्तार

15 वारंट, 54 हजार का इनाम; 6 राज्यों में की थी वारदात

भोपाल (नप्र)। रेलवे स्टेशनों और ट्रेनों में यात्रियों के सामान पर हाथ साफ करने वाले कुख्यात सांसी गैंग के एक बड़े शातिर को भोपाल रेल पुलिस ने 11 साल बाद धर दबोचा। आरोपी सत्यभान सांसी उर्फ सत्यभान पिता महेंद्र सांसी (40) हरियाणा के भिवानी जिले का रहने वाला है। उस पर पूरे देश में 15 स्थायी और गिरफ्तारी वारंट थे, जिसमें 13 अकेले भोपाल जीआरपी और 2 इटारसी जीआरपी के थे।

ट्रेनों में काटते थे बैग, उड़ाते थे नकदी-जेवर- सत्यभान सांसी सांसी गैंग का सक्रिय सदस्य है। यह गिरोह ट्रेनों के जनरल डिब्बों और स्लीपर कोच में सवार होकर यात्रियों के बैग या वॉलीबैग में चाकू या ब्लेड से चीरा लगाकर कीमती सामान, नकदी और जेवरात चोरी करता था। पिछले एक दशक में इस गिरोह ने मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और असम समेत कई राज्यों में वारदातों को अंजाम दिया।

11 साल पुराने केस, 54 हजार का इनाम- जीआरपी भोपाल के मुताबिक, सत्यभान पर 11 साल पुराने 15 अपराधिक मामले दर्ज थे, जिनमें आईपीसी की धारा 379 (चोरी), 380 (भवन में चोरी), 401 (आदतन चोर) और 201 (साक्ष्य छिपाना) शामिल हैं। पुलिस ने उस पर 54,000 रुपये का इनाम घोषित किया था।

कैसे पकड़ा गया? मोबाइल लोकेशन ने खोला राज

भोपाल जीआरपी ने पिछले कई महीनों से पुराने स्थायी वारंटों की तामील के लिए एक विशेष अभियान छेड़ा हुआ था। इसी कड़ी में सत्यभान की तलाश शुरू की गई। पुलिस ने उसके संभावित ठिकानों - भिवानी, हिसार और हरियाणा के अन्य इलाकों - में लगातार दबिश दी, लेकिन वह नहीं मिला।

इसके बाद साइबर सेल भोपाल की मदद से आरोपी के मोबाइल का डेटा निकाला गया और उसकी लोकेशन ट्रैक की गई। कुछ दिनों तक उसके मूवमेंट पर नजर रखी गई। अचानक जब उसका मोबाइल गुवाहाटी (असम) में बंद हो गया, तो पुलिस को संदेह हुआ कि वह वहां किसी अपराध में पकड़ा गया है।

जीआरपी ने तुरंत थाना जालुकबाड़ी, गुवाहाटी से संपर्क किया। वहां से पुष्टि मिली कि सत्यभान को स्थानीय अपराध में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। इसके बाद भोपाल की माननीय अदालत से प्रोडक्शन वारंट जारी कराया गया और उसे गुवाहाटी सेंट्रल जेल से भोपाल लाया गया, जहाँ उसके खिलाफ दर्ज सभी 15 वारंटों की तामील की गई।

कही-सुनी

रवि भोई
(लेखक पत्रिका समवेत सृजन के प्रबंध संपादक और स्वतंत्र पत्रकार हैं।)

छत्तीसगढ़ के एक मंत्री का नितिन नबीन की टीम में जाना तय

चर्चा है कि छत्तीसगढ़ के एक मंत्री का बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन की टीम में जाना लगभग तय हो गया है। मंत्री जी को पार्टी के राष्ट्रीय नेताओं ने इसके संकेत भी दे दिए हैं। कहते हैं कि पार्टी के बड़े नेताओं के संकेत मिलने के बाद मंत्री जी ने सात जुलाई को विधायक दल की बैठक में शामिल नहीं हुए और न ही आठ जुलाई को कैबिनेट की बैठक में गए। कहा जा रहा है कि विधायक दल और कैबिनेट की बैठक में मंत्री की गैरहाजिरी पर राज्य के एक बड़े नेता ने संज्ञान लिया और मंत्री जी से साफ़-साफ़ लहजे में समझाया कि अभी तो आप विधायक और मंत्री हैं। राष्ट्रीय टीम में नियुक्ति नहीं होते तक राज्य की जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। मंत्री और विधायक के नाते कैबिनेट और विधायक दल में बैठक में उन्हें जाना होगा। कैबिनेट और विधायक दल की बैठक में मंत्री जी का न जाना उनकी नाराजगी का संकेत है या खुशी का, यह चर्चा का विषय बन गया है। बताया जा रहा है कि राज्य के बड़े नेता की समझाइस के बाद मंत्री जी विधानसभा में अपने विभागों के सवालों का जवाब भी देंगे और सरकार के कामों में हिस्सेदार भी। खबर है कि मंत्री जी को नितिन नबीन की टीम में महामंत्री बनाया जा रहा है। सुनने में आ रहा है कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन जल्द ही अपनी टीम का ऐलान करने वाले हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मंत्रिमंडल का पुनर्गठन करेंगे। केंद्र में बदलाव के बाद छत्तीसगढ़ पर नजर दौड़ाई जाएगी। हल्ला है कि विष्णुदेव साय के मंत्रिमंडल में फेरबदल के लिए सभी मंत्रियों से इस्तीफे ले लिए जाएंगे। इसके बाद नए सिरे से मंत्रिमंडल बनाया जाएगा। चर्चा है कि साय मंत्रिमंडल में पुनर्गठन के साथ राज्य में उपमुख्यमंत्री का पद ही खत्म न कर दिया जाय।

साय सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आएगा

कहते हैं कि विधानसभा के मानसून सत्र में कांग्रेस राज्य के विष्णुदेव साय सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएगी। बताते हैं विधानसभा सत्र के पहले दिन 13 जुलाई को कांग्रेस इसकी सूचना सदन में देगी। विष्णुदेव साय की सरकार को ढाई साल से ज्यादा समय हो गए हैं। यह पहला मौका है, जब कांग्रेस साय सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने जा रही है। छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र 13 जुलाई से 17 जुलाई 2026 तक चलेगा। 5 दिनों तक चलने वाले इस सत्र में कुल 5 बैठकें होंगी, जिसमें प्रश्नोत्तर, वित्तीय मामलों और अन्य शासकीय विधेयकों पर चर्चा के साथ सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर बहस हो सकती है। माना जा रहा है कि मानसून सत्र छोटा भले है, पर धमाकेदार होगा। कांग्रेस नकटी गांव को उजाड़ने से लेकर खाद संकट, बिजली बिल में बढ़ोतरी अन्य मुद्दों में सरकार को घेरने की कोशिश करेगी।

पद भी गया और पैसा भी डूबा

स्कूल शिक्षा विभाग के एक जूनियर प्रिंसिपल साहब धन बल से जिला शिक्षा अधिकारी बन गए थे , पर हाईकोर्ट के ऐसा डंडा पड़ा कि पद भी चल गया और पद के लिए जो पैसा दिया था, वह भी डूब गया। कहते हैं की प्रिंसिपल साहब ने एक साहब को 15 पेटी दक्षिणा दिए थे। प्रिंसिपल साहब को डीईओ बनाए जाने के खिलाफ उनके दो सीनियर हाईकोर्ट चले गए। सीनियर के रहते जूनियर प्रिंसिपल को डीईओ का चार्ज देने को हाईकोर्ट ने गलत माना और पोस्टिंग रद्द कर दी, तो प्रिंसिपल साहब का पद चला गया। अब प्रिंसिपल साहब ने पद के लिए जिसे दक्षिणा दी थी, उसने भी लौटाने से मना कर दिया। प्रिंसिपल साहब उसका कुछ बाल बांका भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दक्षिणा लेने वाले एक आईएएस और एक मंत्री का खासमखास बताए जाते हैं। अब प्रिंसिपल साहब की जग हसाई हो रही है, सो अलग।

छत्तीसगढ़ के मंत्रालय में खटपट

सामान्य प्रशासन विभाग की उप सचिव अंशिका पांडे को लेकर छत्तीसगढ़ के मंत्रालय में इन दिनों खटपट चल रहा है। डिप्टी कलेक्टर अंशिका पांडे के खिलाफ मंत्रालय के कर्मचारियों ने मोर्चा खोल लिया है। अंशिका पांडे को मंत्रालय से बाहर भेजने के लिए मंत्रालय कर्मचारी संघ ने मुख्य सचिव को ज्ञापन सौंपा है। कहते हैं एक जमाने में मंत्रालय में सचिवालयीन सेवा के कर्मचारियों का दबदबा था। तब गिने-चुने डिप्टी कलेक्टर हुआ करते थे। पहले डिप्टी कलेक्टर फील्ड में ज्यादा रहते थे। अब मंत्रालय में डिप्टी कलेक्टरों की संख्या तीन दर्जन से अधिक बताई जाती है। ये अवर सचिव और उप सचिव के तौर पर महत्वपूर्ण विभागों में तैनात हैं। अंशिका पांडे जीएडी के साथ लोक निर्माण विभाग की उप सचिव है। जीएडी की उप सचिव के रूप में अंशिका पांडे मंत्रालय स्टाफ की पोस्टिंग देखती है। कहते हैं अंशिका पांडे की सिफारिश पर मंत्रालय के स्टाफ को जल्दी-जल्दी इधर-उधर कर दिया जाता है। यह मंत्रालय के कर्मचारियों को नहीं भा रहा है। कहा जा रहा है कि अंशिका पांडे काफी दिनों से एक ही काम देख रही है। यही विवाद की जड़ है।

छोटे जिलों के ही एसपी बदले

सरकार ने लंबे इंतजार के बाद 12 जिलों के एसपी बदले, किसी बड़े जिले को डिस्टर्ब नहीं किया। बिलासपुर, दुर्ग, जशपुर समेत कुछ अन्य जिलों के एसपी डीआईजी बनने के बाद भी वहीं बने रहे। कोरिया के एसपी का हटना तय था। भाजपा नेता को जिंदा जलाने की घटना के बाद भी कोरिया एसपी को रूटीन ट्रांसफर में हटाने का फैसला चर्चा का विषय है। बलौदाबाजार-भाटापारा की एसपी भावना गुप्ता काफी दिनों से अवकाश पर चल रही थीं। अब जाकर उन्हें पुलिस मुख्यालय में एआईजी बनाया गया। अभी तक प्रभारी एसपी के जिम्मे बलौदाबाजार-भाटापारा जिला था। इस ट्रांसफर में सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले को एसपी मिल गया। सरकार ने फील्ड में पदस्थ कुछ आईपीएस को पीएचक्यू लाया है। माना जा रहा है जल्द ही पीएचक्यू में भी फेरबदल होगा।

आखिर रामगोपाल ने किया सरेंडर

कहते हैं कांग्रेस नेता रामगोपाल अग्रवाल ने अचानक सरेंडर नहीं किया, उनके सरेंडर करने की प्लानिंग तो एक महीने से चल रही थी। कोल, चावल और गलत तरीके से पार्टी फंड जुटाने जैसे कई आरोपों से घिरे रामगोपाल अग्रवाल करीब तीन साल से लापता थे। जानकारों का कहना है कि रामगोपाल अग्रवाल ने नेपाल में अज्ञातवास बिताया। रामगोपाल अग्रवाल कांग्रेस पार्टी के कोषाध्यक्ष हैं और भूपेश बघेल के राज में नागरिक आपूर्ति निगम के अध्यक्ष थे। कोषाध्यक्ष के नाते सरकार में दखलंदाजी ज्यादा थी।

प्रिंसिपल पोस्टिंग में खेला

चर्चा है कि राज्य के कई कालेजों में प्रिंसिपल की पोस्टिंग में खेला चल रहा है। जुगाड़-पानी फिट नहीं बैठने के कारण कई कालेज प्रभारी प्राचार्य के भरोसे चल रहे हैं। रायपुर के छत्तीसगढ़ और डिग्री गर्ल्स कालेज ही प्रभारी प्राचार्य के भरोसे हैं। नया शिक्षा सत्र शुरू हो गया है, अब सरकार कब पूर्णकालिक प्राचार्यों की पोस्टिंग करेगी, इसका लोगों को इंतजार है।